नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार से प्रसारित

सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2)
Press/2023

वर्ष 03, अंक 268, नई दिल्ली, गुरुवार 04 दिसम्बर 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

जब तक सांस है, तब तक संघर्ष है, और जब तक संघर्ष है, तब तक उम्मीद है।

02 7 हल्के-फुल्के बैलेंस व्यायाम जो सीनियर्स को पैरों में स्थिरता देते हैं

06 प्रदूषण की मार सांसों पर आफत

08 राष्ट्रीय महिला आयोग – अमृतसर में आज करेगा महिला जन सुनवाई

वाहनों से प्रदूषण या वाहनों के चलने से सड़को द्वारा प्रदूषण, जांच का मुद्दा

"यहां सबसे महत्वपूर्ण बात आपके जानने योग्य यह है की स्वयं दिल्ली सरकार, परिवहन विभाग आयुक्त, नगर निगम दिल्ली प्रदूषण करवाने के कारगर कदम उठा रहे है तो मॉनिटरिंग कैसे करें

संजय बाटला

दिल्ली - एनसीआर में प्रदूषण का मुख्य कारण एक बड़ी जांच का मुद्दा, पर कोई नहीं चाहेगा इस पर जांच करवाना,

प्रदूषण के नाम से सरकारी राजस्व में जुर्माने से वसूले हुए ईमानदारी से आते है खरबों रुपए और अधिकारियों और कर्मचारियों की जब मैं आने वाले रुपयों की गिनती ही संभव नहीं, ऐसे में कौन ढूंढना चाहेगा प्रदूषण का असली कारण और कौन चाहेगा की हो प्रदूषण समाप्त,

राजनीतिक नेताओं, सरकारों ने न्यायिक प्रणाली को गुमराह करने के लिए दे दिए कुछ प्रदूषण को करने वालो के नाम जैसे

पराली का जलना
वाहनों से प्रदूषण
डीजल वाहनों से प्रदूषण

और आश्चर्य जनक बात यह है की न्यायिक प्रणाली ने भी जांच करवाए बिना ही मान ली सरकार और सरकारी विभाग की बात और दे दिया सरकार के पक्ष मे आदेश,

1. क्या न्यायिक प्रणाली, सरकार और सरकारी विभाग के मुखिया जनता को यह बता सकते हैं "अब तक क्यों नही हुआ दिल्ली - एनसीआर प्रदूषण रहित और क्यों नहीं हुई वायु गुणवत्ता" ?

2. क्या जनता से लूट कर / जुर्माना लगाकर खजाना भरने से हो जाएगा प्रदूषण समाप्त या प्रदूषण मुक्त राज्य बनाने के लिए प्रदूषण के असली कारणों पर विचार कर / ढूंढकर उसका करना होगा निवारण ?

बार बार सरकारों द्वारा पॉल्यूशन के लिए किसानों द्वारा पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराने पर सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने की टिप्पणी, आप भी जानेः

* कोविड के दौरान भी पराली जलाना हो रहा था, लेकिन उस समय साफ़ और नीला आसमान कैसे दिखाई दे रहा था ?

* पराली जलाने के मुद्दे को अनावश्यक रूप से राजनीतिक मुद्दा या अहंकार का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए,

सीजेआई का बयान गहरा हैः 'पराली जलाने का मुद्दा अनावश्यक रूप से राजनीतिक या अहंकार का विषय नहीं बनना चाहिए।" किसान, जो कोर्ट में अपनी बात रखने के लिए सशक्त नहीं हैं, पर सारा दोष लादना अन्याय है। हरियाणा के हिसार से आने वाले सीजेआई (जो खुद किसान परिवार से हैं) ने इसे व्यक्तिगत स्पर्श दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ कहा कि यह सीजनल फॉर्मेलिटी नहीं – दिल्ली - एनसीआर प्रदूषण की सुनवाई अब साल भर में दो-दो बार होगी, न कि सिर्फ अक्टूबर-नवंबर में।

आगे क्या ? एक संतुलित रास्ता

यह टिप्पणी हमें याद दिलाती है कि प्रदूषण बहुआयामी समस्या है। किसानों को पराली न जलाने के लिए सब्सिडी, मशीनें और वैकल्पिक तरीके (जैसे बेलिंग या कम्पोस्टिंग) देने की जरूरत है, लेकिन साथ ही दिल्ली - एनसीआर मेंः

1. **वाहनों परः** मेट्रो विस्तार लंबे समय का समाधान, लेकिन तत्काल ई-वाहन प्रोत्साहन और ट्रैफिक मैनेजमेंट।

2. **धूल परः** निर्माण साइट्स पर सख्ती, गीली सफाई और हरित कवर बढ़ाना।

3. **मॉनिटरिंग परः** कई एयर क्वालिटी डिवाइस खराब हैं – इन्हें ठीक करें।

"यहां सबसे महत्वपूर्ण बात आपके जानने योग्य यह है की स्वयं दिल्ली परिवहन विभाग आयुक्त

दिल्ली में अलग अलग झूठे सच्चे मापदंडों का प्रयोग कर दिल्ली में ई वाहन खास तौर से व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अति आवश्यक ई वाहनों को पंजीकृत करने पर ही पाबंदी लगा रहा है,

"यहां सबसे महत्वपूर्ण बात आपके जानने योग्य यह है की स्वयं दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम दिल्ली की सड़को की सफाई करवाना ही नहीं चाहते और जानबूझकर सड़को के किनारों पर अपने कर्मचारियों से ढेर लगवाते है जिससे वाहन जितनी तेज गति से आए वह कूड़ा हवा में उतनी तेजी से जाकर मिल सके और वायु गुणवत्ता कभी नहीं बन पाए

"यहां सबसे महत्वपूर्ण बात आपके जानने योग्य यह है की स्वयं दिल्ली सरकार, परिवहन विभाग आयुक्त, नगर निगम दिल्ली प्रदूषण करवाने के कारगर कदम उठा रहे है तो मॉनिटरिंग कैसे करें

सीजेआई की यह आवाज़ जनता में एक उम्मीद जगाती हैः-

प्रदूषण से लड़ाई में किसान दुश्मन नहीं, सहयोगी हैं। अगर हम सब – सरकारें, उद्योग और नागरिक – जिम्मेदारी साझा करें, तो नीला आसमान फिर से हकीकत बनेगा।

अगली सुनवाई 10 दिसंबर को – देखते हैं, क्या ठोस कदम उठते हैं। आपका क्या ख्याल है ?

भ्रष्टाचार विरोधी शाखा दिल्ली द्वारा मुख्य सतर्कता अधिकारी परिवहन विभाग दिल्ली को एफआईआर संख्या 05/ 2025, यू/एस 13(ए) पीओसी एक्ट आर/डब्ल्यू 409/34/120बी आईपीसी, पीएस भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, जीएनसीटी दिल्ली में धारा 94 बीएनएसएस के तहत भेजा गया नोटिस

संजय बाटला

इस नोटिस के अंतर्गत इंस्पेक्टर पवन कुमार ने सतर्कता अधिकारी परिवहन विभाग से 11 अगस्त 2024 से 27 फरवरी 2025 तक दिल्ली में आयु सीमा पूरी या अन्य प्रवर्तन शाखा द्वारा जब्त और बाहरी राज्यों में पंजीकृत वाहन स्क्रैप डीलरो को सुपुर्द किए गए वाहनों का पूरा डिटेल मांगा है।

आपकी जानकारी हेतु बता दें यह नोटिस जनता के जब्त वाहनों पर परिवहन विभाग, वाहन स्क्रैप डीलरो और अन्य अधिकारियों के खिलाफ दर्ज शिकायत पर जांच के प्रति जारी किया गया है।

इसके अंतर्गत विभाग से उठाए गए वाहनों के नंबर, के साथ उसके प्रति दी गई स्क्रैप मूल्य की पूरी जानकारी भी मांगी गई है।

अगर यह जांच सही दिशा में आगे चली तो परिवहन विभाग के कई अधिकारियों के साथ आला अधिकारी को भी दिक्कत उत्पन्न होगी।

अब देखना होगा की सच उजागर होगा या यह जांच भी अन्य कई जांचों की तरह बीच में ही खो जाएगी।

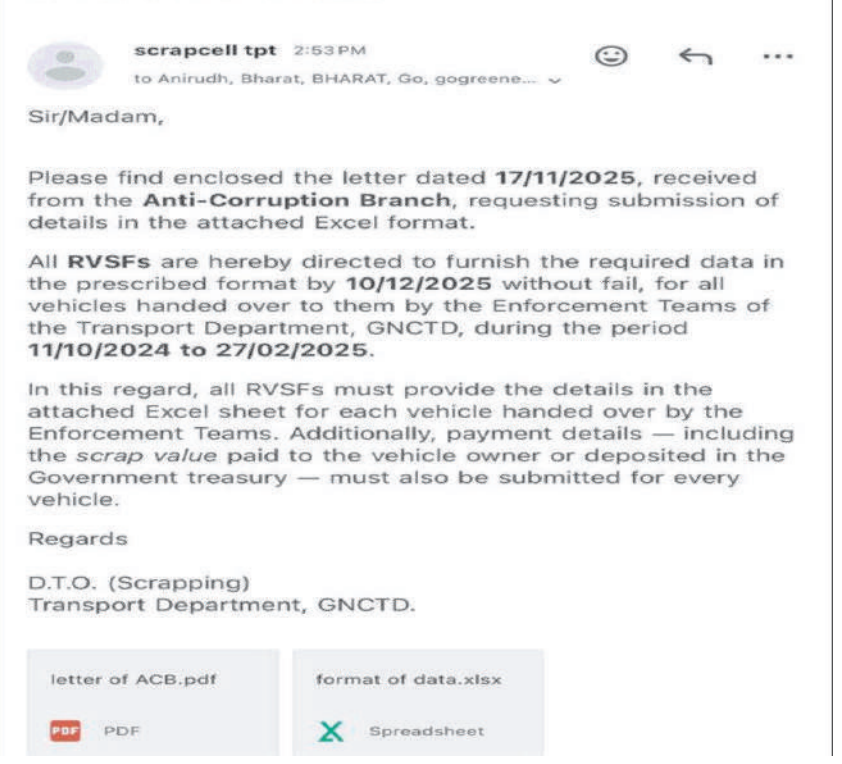
received from Anti Corruption Branch, GNCT of Delhi. . Inbox

scrapcell tpt 2:53 PM
to Anirudh, Bharat, BHARAT, Go, gogreene...

Sir/Madam,

Please find enclosed the letter dated **17/11/2025**, received from the **Anti-Corruption Branch**, requesting submission of details in the attached Excel format.

All **RVSFs** are hereby directed to furnish the required data in the prescribed format by **10/12/2025** without fail, for all vehicles handed over to them by the Enforcement Teams of the Transport Department, GNCTD, during the period **11/10/2024 to 27/02/2025**.

In this regard, all RVSFs must provide the details in the attached Excel sheet for each vehicle handed over by the Enforcement Teams. Additionally, payment details — including the *scrap value* paid to the vehicle owner or deposited in the Government treasury — must also be submitted for every vehicle.

Regards

D.T.O. (Scrapping)
Transport Department, GNCTD.

letter of ACB.pdf PDF
format of data.xlsx Spreadsheet

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत

https://tolwa.com/about.html | tolwaindia@gmail.com
tolwadelhi@gmail.com

आज का साइबर सुरक्षा विचार

संचार साथी ऐप की अनिवार्य स्थापना (Mandatory Installation) दूरसंचार धोखाधड़ी पर रोक लगाने, चोरी हुए उपकरणों को ट्रैक करने और नकली IMEI नंबरों के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इसके प्रभाव को एकीकरण, जागरूकता और प्रवर्तन की रणनीतिक रूपरेखा के माध्यम से और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है।*

"अब हर मोबाइल में होगा साइबर सुरक्षा का साथी – संचार साथी ऐप! जानिए कैसे बचाएगा आपको फ्रॉड से..."

संचार साथी साइबर सुरक्षा को कैसे मज़बूत करता है दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा अनिवार्य किया गया संचार साथी ऐप निम्न कार्यों के लिए बनाया गया हैः

1. • IMEI आधारित पहचान के माध्यम से चोरी या गुम मोबाइल फोन को ट्रैक और ब्लॉक करना

2. •नकली या क्लोन किए गए IMEI नंबरों के दुरुपयोग को रोकना, जिन्हें अक्सर धोखाधड़ी और आतंकी नेटवर्क में इस्तेमाल किया जाता है

3. • संदिग्ध स्रोतों से आने वाली कॉल और SMS को ब्लॉक करना, जिससे फ़िशिंग और स्कैम प्रयासों में कमी आती है

4. • धोखाधड़ी की तेज़ रिपोर्टिंग और दूरसंचार शिकायत निवारण को सक्षम करना, जिससे साइबर अपराध शिकायतों पर प्रतिक्रिया समय सुधरता है

अधिकतम प्रभाव के लिए रणनीतिक रोडमैप

1. अवसंरचना और एकीकरण (0–3 माह)

१. सभी नए उपकरणों में ऐप को हटाने योग्य न बनाते हुए इंस्टॉल करना; पुराने उपकरणों में OTA अपडेट द्वारा जोड़ना

२. CEIR (सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर) और Cybercrime.gov.in से वास्तविक समय डेटा साझा करना

3. ग्रामीण और वरिष्ठ उपयोगकर्ताओं के लिए बहुभाषी समर्थन और सुलभता सुविधाएँ सक्षम करना

2. जन-जागरूकता और प्रशिक्षण (3–6 माह)

१. व्हाट्सऐप, रेडियो और स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों के माध्यम से राष्ट्र व्यापी अभियान चलाना

२. पुलिस थानों, स्कूलों और साइबर कैफ़े में द्विभाषी गाइड और पोस्टर वितरित करना

3. बीट अधिकारियों और साइबर सेल

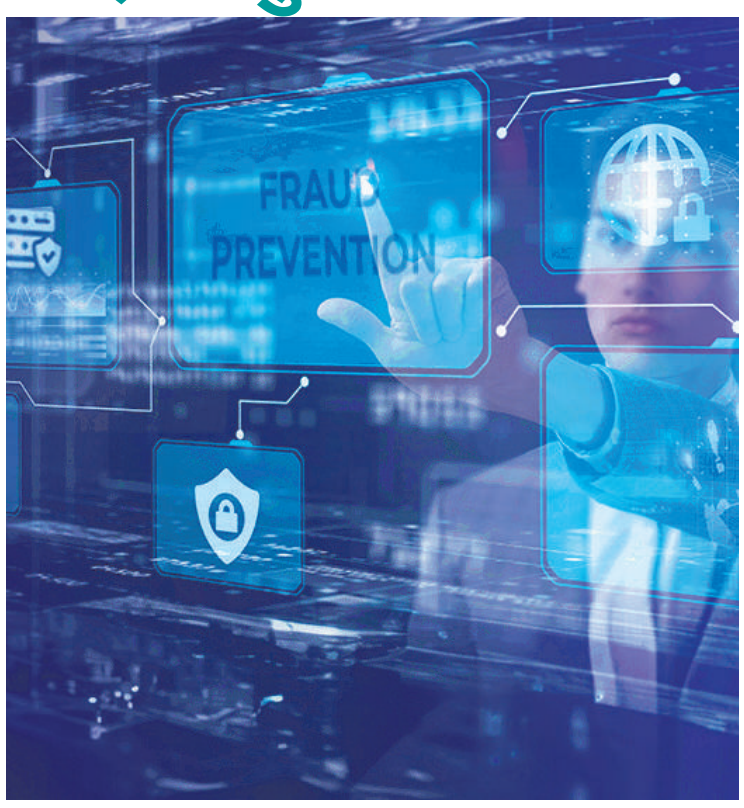

को प्रशिक्षित करना ताकि वे नागरिकों को धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और उपकरण ट्रैकिंग में मदद कर सकें

3. नीति और प्रवर्तन (6–12 माह)

१. सिम सक्रिय करने से पहले दूरसंचार ऑपरेटरों को IMEI की प्रामाणिकता सत्यापित करना अनिवार्य करना

२. संचार साथी ऐप के उपयोग को KYC और सिम पुनः सत्यापन प्रोटोकॉल से जोड़ना

3. निर्माताओं/विक्रेताओं पर दंड लगाना जो ऐप इंस्टॉलेशन से बचते हैं या IMEI रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करते हैं

4. उन्नत विश्लेषण और AI एकीकरण (12–18 माह)

१. धोखाधड़ी पैटर्न, स्पूफ़ कॉल और बड़े पैमाने पर स्कैम अभियानों का पता लगाने के लिए AI का उपयोग करना

२. स्थान, कॉल व्यवहार और स्कैम रुझानों के आधार पर उपयोगकर्ताओं को पूर्वानुमानित अलर्ट भेजना

. CERT-In और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ गुमनाम डेटा साझा करना ताकि सीमा-पार धोखाधड़ी का पता लगाया जा सके

जोखिम और समाधान

गोपनीयता चिंताएँः आलोचकों का कहना है कि यदि सही तरीके से विनियमित न किया जाए तो ऐप उपयोगकर्ता अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है जो निराधार है ,यह ऐप्प पारदर्शिता पर आधारित है तथा न्यूनतम डेटा संग्रह करता है इस संदर्भ में माननीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान उल्लेखनीय हैः "यदि आप इस एप्लिकेशन का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, तो पंजीकरण न करें। यह निष्क्रिय रहेगा। यदि आप इसे हटाना चाहते हैं, तो हटा दें। हमारा कर्तव्य है कि यह ऐप हर नागरिक तक पहुँचे ताकि साइबर सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। यदि आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, तो पंजीकरण न करें। यह तब तक सक्रिय नहीं होगा जब तक आप पंजीकरण नहीं करते।"

28 नवंबर को DoT ने सभी मोबाइल कंपनियों को दिया गया आदेश कि हर स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप को शामिल करें 90 दिनों के भीतर लागु होगाः

1. डिवाइस सेटिंग्स में पूर्व-स्थापित होगा, जिसे उपयोगकर्ता हटा नहीं सकेंगे

2. पुराने फोन में सॉफ़्टवेयर अपडेट के माध्यम से जोड़ा जाएगा

3. उपयोगकर्ता की गोपनीयता की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी

इस प्रकार, संचार साथी ऐप हर नागरिक का साइबर सुरक्षा साथी बनकर धोखाधड़ी से बचाव करेगा और राष्ट्रीय दूरसंचार सुरक्षा को मज़बूत करेगा।

पिंकी कुंडू
सदस्य बंगाली प्रकोष्ठ
भाजपा दिल्ली प्रदेश,
सदस्य उज्जवला योजना
भाजपा दिल्ली प्रदेश

उतना ही लो थाली में व्यर्थ न जाए नाली में

यह तस्वीर सिर्फ एक टेबल नहीं, इंसानों के बदलते संस्कारों का आइना है।

अपनी जेब से पैसा जाए तो लोग दाना तक नहीं छोड़ते, और

जहाँ मुफ्त मिले वहाँ इंसानियत तक फिसल जाती है।

अन्न की कद्र नहीं रही
बस आदतें बिगड़ चुकी हैं.
थोड़ी सी शर्म साथ ले आते तो
यह टेबल भी इतना अपमानित न होती
और इंसानियत भी इतनी सस्ती न लगती...

यह खाने की बर्बादी है या लोगों की परवरिश का सच..

जिस किसान ने अपने खुन पसीना और मेहनत से अपनी खेती मे इसको उगाया है, उसका ये अपमान है और पैसो की मस्ती की निशाणी है...!

इसे रोकने के लिए हर इन्सान को सोचना पडेगा.

निवेदनएक बाप ने इसी दिन के लिए पाई पाई जोड़ी थी , किसी को एक वक्त की रोटी नसीब नहीं तो किसी को फेंकने के लिए कमी नहीं

उतना ही लें थाली में व्यर्थ न जाए नाली में

गुजरात का GIFT City अब भारत की आर्थिक शक्ति का नया प्रतीक बन रहा है

गांधीनगर स्थित यह इंटरनेशनल फाइनेंस-टेक सिटी न केवल देश का पहला ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है, बल्कि वैश्विक वित्तीय केंद्रों जैसे दुबई और सिंगापुर को चुनौती देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।

विस्तृत रिपोर्ट :- पृष्ठभूमि

1. GIFT City (Gujarat International Finance Tec-City) की परिकल्पना वर्ष 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी।

2. इसे एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया गया, जिसका उद्देश्य भारत को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं और तकनीकी नवाचार का केंद्र बनाना था।

3. 2011 से इसके विकास को गति मिली और आज यह लगभग 1,000 एकड़ में फैला है, जिसे आगे बढ़ाकर 3,300 एकड़ तक विस्तार करने की योजना है।

आर्थिक उपलब्धियाँ

1. GIFT City के International Financial Services Centre (IFSC) में अब तक 1,034 से अधिक कंपनियाँ पंजीकृत हो चुकी हैं।

2. इनमें 38 बैंक शामिल हैं, जो मिलकर 100 बिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति का प्रबंधन कर रहे हैं।

3. यहाँ बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, फंड मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, फिनटेक, एयरक्राफ्ट और शिप लीज़िंग जैसी सेवाएँ उपलब्ध हैं।

4. यह केंद्र अब सिंगापुर और हांगकांग जैसे वैश्विक वित्तीय हब का प्रतिस्पर्धी बन रहा है।

स्मार्ट सिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर

1. GIFT City को भारत का पहला ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी कहा जाता है।

2. यहाँ अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आवासीय और व्यावसायिक सुविधाएँ, SEZ और Domestic Tariff Area का एकीकृत ढाँचा मौजूद है।

3. इसे केवल वित्तीय जिला नहीं, बल्कि एकीकृत शहरी केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।

हाल की प्रगति

1. अहमदाबाद द्वारा 2030 Commonwealth Games की सफल बोली के बाद GIFT City पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

2. इस अवसर ने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और रिहायशी विकास को तेज़ी से आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया है।

महत्व और दृष्टि

1. प्रधानमंत्री मोदी की दृष्टि के अनुरूप, GIFT City को भारत का दुबई और सिंगापुर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है।

2. यह न केवल आर्थिक विकास का प्रतीक है, बल्कि भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता को भी दर्शाता है।

3. यहाँ स्टार्टअप्स और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए आकर्षक अवसर उपलब्ध हैं, जिससे यह निवेशकों और पेशेवरों का केंद्र बन रहा है।

निष्कर्षः GIFT City गांधीनगर अब केवल गुजरात या भारत की परियोजना नहीं रही, बल्कि यह वैश्विक वित्तीय मानचित्र पर भारत की पहचान को मजबूत कर रही है। आने वाले वर्षों में यह भारत की आर्थिक शक्ति और तकनीकी नवाचार का सबसे बड़ा प्रतीक बन सकता है।

कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है

आप इसे देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते और महसूस भी नहीं कर सकते। इसी कारण इसे दुनिया भर में Silent Killer (मौन हत्यारा) कहा जाता है।

कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों खतरनाक है?

1. जब CO हवा में बढ़ता है और हम उसे साँस के साथ अंदर लेते हैं, तो यह हमारे खून में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ तेज़ी से जुड़ जाता है।

2. हीमोग्लोबिन का असली काम शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुँचाना होता है।

3. लेकिन जब CO उससे जुड़ जाता है, तो खून ऑक्सीजन ले जाना बंद कर देता है।

4. इससे शरीर के महत्वपूर्ण अंग—दिमाग, दिल, फेफड़े—ऑक्सीजन के बिना काम करने लगते हैं, जो कुछ ही मिनटों में गंभीर समस्या या मृत्यु तक पहुँचा सकता है।

कार्बन मोनोऑक्साइड के मुख्य स्रोत

1. अधूरी दहन (Incomplete Combustion)
2. बंद कमरे में जलता हुआ चूल्हा/हीटर
3. खराब जेनरेटर
4. गैस गीजर
5. कार/बाइक का इंजन
6. कोयले की अंगीठी
7. खराब चिमनी, भट्ठियाँ और औद्योगिक उपकरण

लक्षण (Symptoms) — शुरुआती से गंभीर तक

शुरुआती लक्षणः
1. सिरदर्द
2. चक्कर
3. थकान
4. उलझन (Confusion)
5. मतली

गंभीर लक्षणः
1. बेहोशी
2. साँस लेने में कठिनाई
3. दिल की विफलता (Cardiac failure)
4. दौरे (Seizures)
5. कोमा
6. मृत्यु

कार्बन मोनोऑक्साइड से बचाव (Prevention)

1. घर में CO Alarm/Detector लगाएँ।
2. गैस गीजर कभी भी बंद कमरे में न इस्तेमाल करें।
3. जेनरेटर, मोटर या कार को बंद कमरों/गैरेज में न चालू रखें।
4. चूल्हों, बर्नरों और चिमनियों की नियमित सर्विस कराएँ।
5. अंगीठी का इस्तेमाल हमेशा खुली हवा में करें।

Latest Developments (नवीनतम प्रगतियाँ)

1. Smart CO Detectors अब विश्वभर में ऐसे स्मार्ट सेंसर उपलब्ध हैं जो CO को माइक्रो-स्तर पर भी पहचान लेते हैं। यह मोबाइल फोन पर रियल-टाइम अलर्ट भेजते हैं।

2. IoT-Based Safety Systems उद्योगों और होटलों में ऐसे सिस्टम लगाए जा रहे हैं जो किसी भी लीकेज को पहचानकर ऑटोमेटिक वेंटिलेशन चालू कर देते हैं।

3. Wearable CO Monitors खदानों, फैक्ट्रियों व दमकल कर्मियों के लिए शरीर पर पहनने वाले CO मॉनिटर्स विकसित किए गए हैं।

4. Healthcare Innovations अब CO poisoning के इलाज के लिए Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT) अधिक आधुनिक और तेज़ की जा रही है, जिससे मरीज के खून से CO तेजी से हटाया जा सके।

5. Environmental Tracking कई देशों में स्मार्ट सिटी सेंसर कार्बन मोनोऑक्साइड स्तर को लगातार मापते हैं और खतरा बढ़ने पर लोगों को स्वतः SMS अलर्ट भेजते हैं।

संक्षेप में (In Summary) कार्बन मोनोऑक्साइड एक अदृश्य, अत्यंत विषैली और जानलेवा गैस है।

इसके संपर्क में आना कई बार अनजाने में ही होता है, इसलिए रोकथाम = सुरक्षा।

वैज्ञानिक दुनिया अब स्मार्ट तकनीकों की मदद से CO को रोकने और जान बचाने में और अधिक सक्षम होती जा रही है।

हेल्थ टिप्स / गलत समय पर खाना खाने से सेहत को हो सकते हैं बड़े नुकसान, आज से ही आदत डालें ये बदलाव, जानें सही टाइमिंग

हेल्थ के लिए सबसे ज़रूरी है ब्रेकफ़ास्ट ब्रेकफ़ास्ट को हेल्थ के लिए सबसे ज़रूरी माना जाता है। ब्रेकफ़ास्ट के लिए सबसे अच्छा समय सुबह 7 से 9 बजे के बीच का माना जाता है। बहुत से लोग सुबह ब्रेकफ़ास्ट और दोपहर में लंच करते हैं। इससे गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी और ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं।

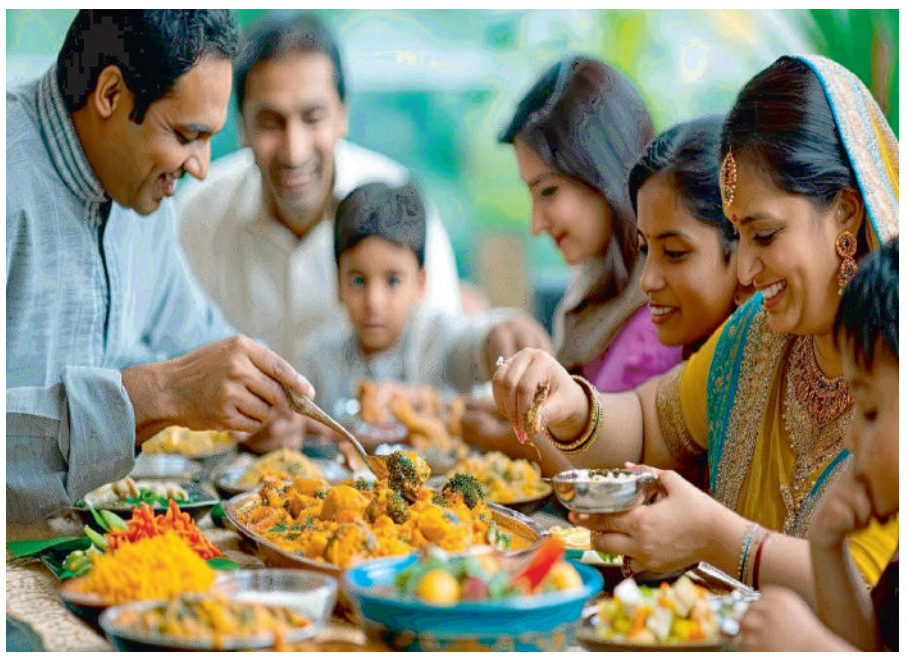

हमें लंच कब करना चाहिए सही समय पर ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद, लंच दोपहर 12.30 से 2 बजे के बीच करना चाहिए। यह वह समय है जब मेटाबॉलिज़्म सबसे तेज़ी से काम करता है। इस समय खाया गया खाना ठीक से पचता है। अगर आप बिज़ी हैं, तो आप दोपहर 3 बजे तक लंच कर सकते हैं, लेकिन इसे और देर भी किया जा सकता है। अगर आप इससे देर से लंच करते हैं, तो आपका वज़न तेज़ी से बढ़ सकता है और पेट की प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। जिससे खाना ठीक से पचता नहीं है। इसलिए, लंच सही समय पर करना चाहिए।

डिनर कब करना चाहिए हमें रात को सोने से कम से कम दो से तीन घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आप रात को 2 बजे सोते हैं, तो आपको 11 बजे डिनर कर लेना चाहिए। अगर किसी वजह से आप देर से सोते भी हैं, तो आपको शाम को 7 से 8 बजे के बीच खाना खा लेना चाहिए। यह सबसे अच्छा समय माना जाता है। रात में देर से खाने से डाइजेशन खराब हो सकता है। इसके अलावा, देर से खाने से स्ट्रेस हार्मोन भी बनते हैं। इससे नींद कम आती है और पेट की चर्बी भी बढ़ सकती है। रात में देर से नाश्ता करने से भी बचना चाहिए।

संपूर्ण संक्षिप्त ड्राफ़्ट (हिन्दी में)

3-इंग्रीडिएंट वाला फुट स्प्रे रात को मन और शरीर को शांत करने में लोगों की कर रहा मदद

3-इंग्रीडिएंट वाला फुट स्प्रे रात को मन और शरीर को शांत करने में लोगों की मदद कर रहा है। सोने से 10 मिनट पहले पैरों पर स्प्रे करें—नींद जल्दी आने में सहायता मिल सकती है।

अच्छी नींद क्यों ज़रूरी है बड़ों को रोज़ 7–8 घंटे की नींद चाहिए। कम नींद से शरीर और मन दोनों पर असर पड़ता है।

यह आसान नाइट-टाइम ट्रिक आपकी नींद में सुधार ला सकती है।

3-इंग्रीडिएंट स्लीप स्प्रे

1. कैमोमाइल एसेंशियल ऑयल रोमन कैमोमाइल में नींद लाने और तनाव कम करने वाले गुण होते हैं।

2. लैवेंडर एसेंशियल ऑयल लैवेंडर की खुशबू ही मन को शांत कर देती है। एसेंशियल ऑयल और भी प्रभावी है।

3. मैग्नीशियम ऑयल ज़्यादातर लोग मैग्नीशियम कम लेते हैं। यह 300+ बॉडी फंक्शन्स में काम आता है और सबसे रिलैक्सिंग मिनेरल माना जाता है। जितना ज़्यादा मैग्नीशियम, उतना ज़्यादा सुकून और गहरी नींद।

पैरों पर क्यों लगाएँ? पैरों में सबसे बड़े पोर्स होते हैं, इसलिए तेल जल्दी अवशोषित होता है। जब बाथ का समय न हो, यह आसान विकल्प है।

स्लीपीटाइम फुट स्प्रे कैसे बनाएं

सामग्री:
1. 4 oz मैग्नीशियम ऑयल
2. 10 बूंद लैवेंडर एसेंशियल ऑयल
3. 10 बूंद रोमन कैमोमाइल एसेंशियल ऑयल

विधि: सबको काँच की 4-oz स्प्रे बोतल में मिलाकर अच्छे से हिलाएँ।

कैसे इस्तेमाल करें: हर पैर के तलवे पर 3–5 स्प्रे करें और पूरा भाग कवर करें।

बेहतर नींद के लिए अतिरिक्त सुझाव

1. पैर/पिंडली का एक पॉइंट मसाज करें तनाव कम होता है
2. वेटेड ब्लैंकेट का उपयोग
3. सोने से पहले शांत संगीत या ध्वनि सुनें,
4. हल्का-सा "गोल्ड पेस्ट" (हल्दी मिक्स) ले।

तिल, बादाम, सरसों और ओलिव तेल दिल और दिमाग को हेल्दी रखता है

हमें अपने दिल और दिमाग का खास ख्याल रखना ज़रूरी है। कुकिंग ऑयल में मौजूद फैटी एसिड दिल और दिमाग को हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं।

ओमेगा-3 फैटी एसिड वाले तेल कोलेस्ट्रॉल कम करने और ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।

तेलों का इस्तेमाल करके हम दिल और दिमाग को हेल्दी रख सकते है। आइए जानते हैं कि हमारे दिल और दिमाग के लिए कौन सा कुकिंग ऑयल सबसे अच्छा है।

कुकिंग ऑयल कैसे चुनें: एक्सपर्ट्स के अनुसार, कुकिंग ऑयल चुनते समय यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि वह हमारी सेहत के लिए फायदेमंद हो। अक्सर हम बाज़ार में मिलने वाले सस्ते तेल का इस्तेमाल करते हैं, बिना यह जाने कि वह कितना अनहेल्दी है।

1. कुकिंग ऑयल में मौजूद फैटी एसिड की क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत ज़रूरी है।

2. तेल में MUFA और PUFA जैसे अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा होने चाहिए,

3. खासकर ओमेगा-3 PUFA जो दिल की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं।

4. तेल को ज़्यादा गरम नहीं करना चाहिए वरना उसमें नुकसानदायक केमिकल बन सकते हैं।

अपनी सेहत के लिए फायदेमंद सही कुकिंग ऑयल चुनना बहुत ज़रूरी है। इस पर कीमत से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।

इन तेलों का इस्तेमाल करें...

1. ऑलिव ऑयल ऑलिव ऑयल में मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जो दिल और दिमाग के लिए फायदेमंद होते हैं।

2. बादाम का तेल बादाम के तेल में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड पाए जाते हैं जो दिल और दिमाग को हेल्दी रखने में मदद करते हैं।

3. सरसों का तेल सरसों के तेल में भी ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है जो दिल और दिमाग को हेल्दी रखने में मदद करता है।

7 हल्के-फुल्के बैलेंस व्यायाम जो सीनियर्स को पैरों में स्थिरता देते हैं

उम्र के साथ बैलेंस कम होता है, लेकिन रोज़ कुछ मिनट घर पर अभ्यास करके आप अपने पैरों की शक्ति और स्थिरता को आसानी से बढ़ा सकते हैं। ये 7 सरल और सुरक्षित व्यायाम मदद करेंगे:

1. एक पैर पर खड़े होना – सपोर्ट लेकर एक पैर उठाएँ और कुछ सेकंड संतुलन बनाएँ। दोनों पैरों पर दोहराएँ।

2. हील-टू-टो वॉक – सीधी लाइन में एड़ी को पंजे से लगाकर 10 कदम आगे-पीछे चलें।

3. सिट-टू-स्टैंड – कुर्सी से बिना हाथों का सहारा लेकर धीरे-धीरे खड़े हों। 10 बार करें।

4. हील और टो रेज़ – पंजों पर उठें, फिर एड़ियों पर आएँ। इससे टखने और पिंडलियाँ मजबूत होती हैं।

5. साइड लेग किक्स – सहारा लेकर पैर को बगल की ओर उठाएँ। हिप को न मोड़ें। दोनों तरफ करें।

6. मार्चिंग इन प्लेस – जगह पर खड़े होकर घुटने ऊपर उठाते हुए धीरे-धीरे मार्च करें।

7. क्लॉक रीच – एक जगह खड़े होकर पैर से "12, 3, 6, 9 बजे" की दिशा को टच करें और वापस आएँ। ध्यान रखें: हमेशा सुरक्षा को प्राथमिकता दें, ज़रूरत हो तो सपोर्ट लें, और रोज़ 3–5 मिनट अभ्यास करें। नियमितता से बैलेंस और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं।

Tea Tree Oil for Chronic Sinus Infection – 8 Benefits & How to Use

Benefits:
1. सूजन कम करे
2. बैक्टीरिया-फंगस को रोके
3. नाक खुलने में मदद
4. सिर/साइनस दबाव घटाए
5. दोबारा इंफेक्शन का खतरा कम
6. म्यूकस को ढीला करे
7. लोकल इम्युनिटी बढ़ाए
8. ठंडक व आराम दे

कैसे उपयोग करें (Safe):

Steam: गरम पानी में 2–3 drops डालकर 5–10 min भाप लें।

Diffuser: कमरे में 3–4 drops चलाएं।

Warm compress: 1 drop गर्म पानी में, कपड़ा भिगोकर माथे/गाल पर रखें।

Chest rub: 1 tbsp coconut oil + 1–2 drops tea tree oil मिलाकर छाती पर लगाएं।

Hot shower: बाथरूम के कोने में 2–3 drops डालें और भाप लें।

ध्यान रखें:
1. नाक के अंदर कभी न डालें
2. पीना नहीं है
3. हमेशा dilute करके ही प्रयोग करें

हृदय की धमनियों में कैल्शियम प्लाक रोकने के 8 तरीके

कोरोनरी धमनियों में कैल्शियम जमा होना वर्षों तक प्लाक (वसा + कोलेस्ट्रॉल) बनने के बाद होता है। इससे रक्त प्रवाह कम होता है और दिल के दौरे का खतरा बढ़ता है। इसे रोकने के 8 असरदार तरीके:

1. कोलेस्ट्रॉल, वसा और नमक कम करें सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, तली-भुनी और बहुत नमकीन चीजों से दूर रहें। फल, सब्जियाँ, साबुत अनाज, कम वसा वाला प्रोटीन और अच्छे फैट लें।

2. नियमित व्यायाम करें एरोबिक वर्कआउट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और स्ट्रेचिंग दिल को मजबूत करते हैं, रक्त प्रवाह सुधारते हैं और BP व वजन नियंत्रित रखते हैं।

3. धूम्रपान छोड़ें स्मोकिंग धमनियों को नुकसान पहुँचाती है, प्लाक बढ़ाती है, BP बढ़ाती है और दिल का रक्त प्रवाह घटाती है। छोड़ने से तुरंत लाभ मिलता है।

4. शराब सीमित रखें अधिक शराब BP बढ़ाती है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाती है और दिल की धड़कन व मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाती है।

5. स्वस्थ तरीके से वजन कम करें अधिक वजन BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और इंफ्लेमेशन बढ़ाता है। धीरे-धीरे वजन कम करें। क्रैश डाइट से बचें।

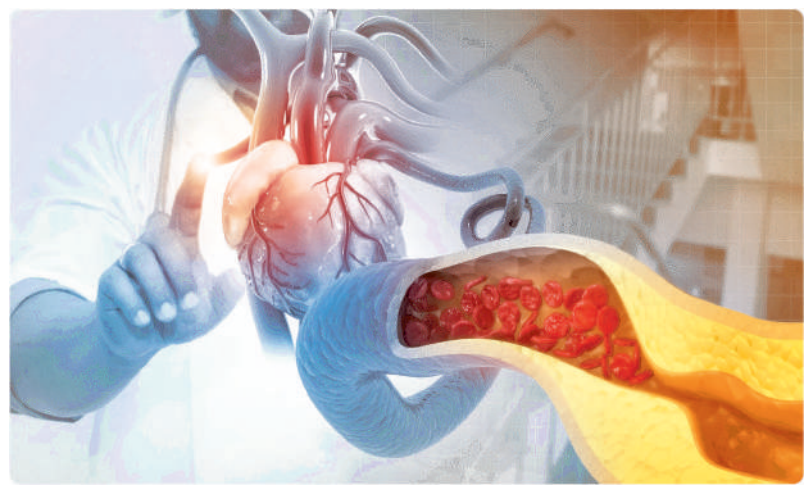

6. प्रकृति में समय बिताएँ टहलना, सैर, हाइकिंग या सिर्फ बाहर रहने से तनाव कम होता है, मूड और नींद बेहतर होती है और हृदय स्वास्थ्य मजबूत होता है।

7. तनाव नियंत्रण योग, ध्यान, गहरी साँस, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, अच्छा भोजन, सीमाएँ तय करना, सामाजिक समर्थन और जरूरत पड़ने पर काउंसलिंग लें।

8. डॉक्टर द्वारा बताए गए दवाएँ लें स्टैटिन्स, BP दवाएँ, एंटी-प्लेटलेट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आदि डॉक्टर निर्देशित हों। खुद से दवा न लें और नियमित फॉलो-अप करें।

निष्कर्ष: सही जीवनशैली + डॉक्टर की सलाह मिलकर कैल्शियम प्लाक को कम कर सकती है और दिल को सुरक्षित रखती है।

अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकरप्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य-सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहिं च पार्वति

पिंकी कुंडू
सदस्य उज्जवला योजना भाजपा दिल्ली प्रदेश
सदस्य बंगाली प्रकोष्ठ भाजपा दिल्ली प्रदेश

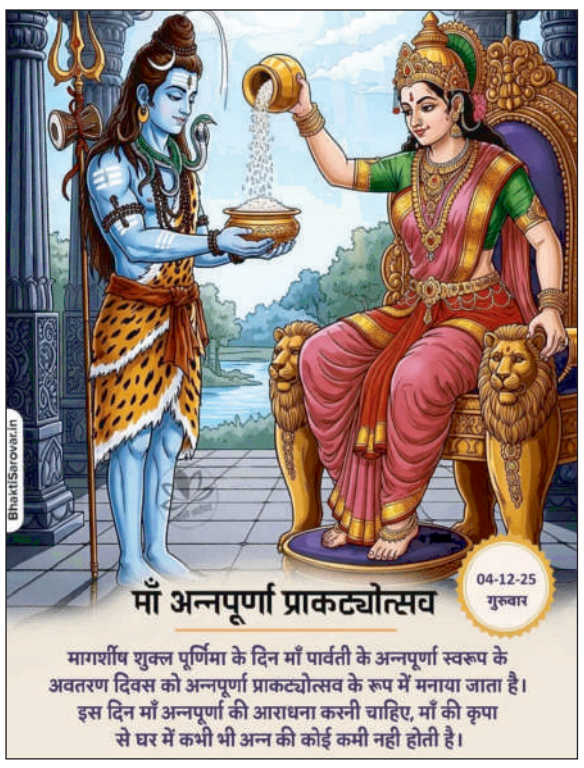

मागर्शीष शुक्ल पूर्णिमा के दिन माँ पार्वती के अन्नपूर्णा स्वरूप के अवतरण दिवस को अन्नपूर्णा प्राकट्योत्सव के रूप में मनाया जाता है, इसी दिन मां पार्वती ने अन्नपूर्णा रूप धारण किया था।

माता अन्नपूर्णा अन्न और समृद्धि की देवी हैं, इस दिन माँ अन्नपूर्णा की आराधना करनी चाहिए, माँ की कृपा से घर में कभी भी अन्न की कोई कमी नही होती है।

इस दिन रसोईघर को अच्छी तरह साफ कर, घर के चूल्हे की पूजा करनी चाहिए।

अन्नपूर्णा प्राकट्योत्सव के दिन मां अन्नपूर्णा की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, जिससे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है।

मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा तिथि 04 दिसंबर को सुबह 4 बजकर 37 मिनट पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 05 दिसंबर को सुबह 04 बजकर 43 मिनट पर होगा।

इस वर्ष माँ अन्नपूर्णा का प्राकट्योत्सव गुरुवार, 04 दिसंबर को मनाया जायेगा।

ऐसा मंदिर जहां भूख से दुबले हो जाते हैं श्रीकृष्ण

पिंकी कुंडू

यह विश्व का ऐसा अनोखा मंदिर है जो 24 घंटे में मात्र दो मिनट के लिए बंद होता है।

यहां तक कि ग्रहण काल में भी मंदिर बंद नहीं किया जाता है। कारण यह कि यहां विराजमान भगवान कृष्ण को हमेशा तीव्र भूख लगती है। भोग नहीं लगाया जाए तो उनका शरीर सूख जाता है। अतः उन्हें हमेशा भोग लगाया जाता है, ताकि उन्हें निरंतर भोजन मिलता रहे। साथ ही यहां आने वाले हर भक्त को भी प्रसादम् (प्रसाद) दिया जाता है। बिना प्रसाद लिये भक्त को यहां से जाने की अनुमति नहीं है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इसका प्रसाद जीभ पर रख लेता है, उसे जीवन भर भूखा नहीं रहना पड़ता है। श्रीकृष्ण हमेशा उसकी देखरेख करते हैं।

डेढ़ हजार वर्ष पुराना मंदिर केरल के कोट्टायम जिले के तिरुवरप्पु में स्थित यह मंदिर लगभग डेढ़ हजार साल पुराना है। लोक मान्यता के अनुसार कंस वध के बाद भगवान श्रीकृष्ण बुरी तरह से थक गए थे। भूख भी बहुत अधिक लगी हुई थी। उनका वही विग्रह इस मंदिर में है। इसलिए मंदिर सालों भर हर दिन मात्र खुला रहता है। मंदिर बंद करने का समय दिन में 11.58 बजे है। उसे दो मिनट बाद ही ठीक 12 बजे खोल दिया जाता है। पुजारी को मंदिर के ताले की चाबी के साथ कुल्हाड़ी भी दी गई है। उसे निर्देश है कि ताला खुलने में विलंब हो तो उसे कुल्हाड़ी से तोड़ दिया जाए। ताकि भगवान को भोग लगने में तनिक भी विलंब न हो। चूंकि यहां मौजूद भगवान के विग्रह को भूख बर्दाश्त नहीं है, इसलिए उनके भोग की विशेष व्यवस्था की गई है। उनको 10 बार नैवेद्यम (प्रसाद) अर्पित किया जाता है।

मंदिर खोले रखने की व्यवस्था आदि शंकराचार्य की ऐसा मंदिर जहां श्रीकृष्ण से भूख बर्दाश्त नहीं होता है। पहले यह आम मंदिरों की तरह बंद होता था। विशेष रूप से ग्रहण काल में इसे बंद रखा जाता था। तब ग्रहण खत्म होते-होते भूख से उनका विग्रह रूप पूरी तरह सूख जाता था। कमर की पट्टी नीचे खिसक जाती थी। एक बार उसी दौरान आदि शंकराचार्य मंदिर आए। उन्होंने भी यह स्थिति देखी। तब उन्होंने व्यवस्था दी कि ग्रहण काल में भी मंदिर को बंद नहीं किया जाए। तब से मंदिर बंद करने की परंपरा समाप्त हो गई। भूख और भगवान के विग्रह के संबंध को हर दिन अभिषेकम के दौरान देखा जा सकता है। अभिषेकम में थोड़ा समय लगता है। उस दौरान उन्हें नैवेद्य नहीं चढ़ाया जा सकता है। अतः नित्य उस समय विग्रह का पहले सिर और फिर पूरा शरीर सूख जाता है। यह दृश्य अद्भुत और अकल्पनीय सा प्रतीत होता है लेकिन है पूर्णतः सत्य।

प्रसादम् लेने वाले के भोजन की श्रीकृष्ण करते हैं चिंता इस मंदिर के साथ एक और मान्यता जुड़ी हुई है कि जो भक्त यहां पर प्रसादम चख लेता है, फिर जीवन भर श्रीकृष्ण उसके भोजन की चिंता करते हैं। यही नहीं उसकी अन्य आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। प्राचीन शैली के इस मंदिर के बंद होने से ठीक पहले 11.57 बजे प्रसादम् के लिए पुजारी जोर से आवाज लगाते हैं। इसका कारण मात्र यही है कि यहां आने वाला कोई भक्त प्रसाद से वंचित न हो जाए। यह अत्यंत रोचक है कि भूख से विह्वल भगवान अपने भक्तों के भोजन की जीवन भर चिंता करते हैं। उनके अपनी भूख की यह हालत है कि उसे देखते हुए मंदिर को नित्य दो मिनट बंद रखा जाता है। इसका कारण भगवान को सोने का समय देना है। अर्थात इस मंदिर में वे मात्र दो मिनट सोते हैं।

श्री राम और राममन्त्र

पिंकी कुंडू
सदस्य बंगाली प्रकोष्ठ भाजपा दिल्ली
सदस्य उज्जवला योजना भाजपा दिल्ली

तात्पर्य-

वास्तव में राम अनादि ब्रह्म ही हैं। अनेका नेक संतों ने निर्गुण राम को अपने आराध्य रूप में प्रतिष्ठित किया है। राम नाम के इस अत्यंत प्रभावी एवं विलक्षण दिव्य बीज मंत्र को सगुणोपासक मनुष्यों में प्रतिष्ठित करने के लिए दशरथी राम का पृथ्वी पर अवतरण हुआ है।

कबीरदास जी ने कहा है –

आत्मा और राम एक है-

' आतम राम अवर नहिं दूजा।'

राम नाम कबीर का बीज मंत्र है। राम नाम को उन्होंने अजपा जाप कहा है।

राम शब्द का अर्थ है

'रमंति इति रामः'

जो रोम-रोम में रहता है, जो समूचे ब्रह्मांड में रमण करता है वही राम हैं।

इसी तरह कहा गया है –

'रमन्ते योगिनो यस्मिन स रामः'

अर्थात योगीजन जिसमें रमण करते हैं वही राम हैं।

इसी तरह ब्रह्मवैवर्त पुराण

में कहा गया है –

' राम शब्दो विश्ववचनो, मश्वापीश्वर वाचकः'

अर्थात 'रा' शब्द परिपूर्णता का बोधक है और 'म' परमेश्वर वाचक है। चाहे निर्गुण ब्रह्म हो या दाशरथि राम हो, विशिष्ट तथ्य यह है कि राम शब्द एक महामंत्र है।

राम मन्त्र का अर्थ

' राम ' स्वतः मूलतः

अपने आप में पूर्ण मन्त्र है।

'र', 'अ' और 'म', इन तीनों अक्षरों के योग से 'राम' मंत्र बनता है। यही राम रसायन है।

'र' अग्निवाचक है।

'अ' बीज मंत्र है।

'म' का अर्थ है ज्ञान।

यह मंत्र पापों को जलाता है, किंतु पुण्य को सुरक्षित रखता है और ज्ञान प्रदान करता है। हम चाहते हैं कि पुण्य सुरक्षित रहें, सिर्फ पापों का नाश हो।

'अ' मंत्र जोड़ देने से अग्नि केवल पाप कर्मो का दहन कर पाती है और हमारे शुभ और सात्विक कर्मो को सुरक्षित करती है। 'म' का उच्चारण करने से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। हमें अपने स्वरूप का भान हो जाता है। इसलिए हम र, अ और म को जोड़कर एक मंत्र बना लेते हैं-राम। 'म' अभीष्ट होने पर भी यदि हम 'र' और 'अ' का उच्चारण नहीं करेंगे तो अभीष्ट की प्राप्ति नहीं होगी।

राम सिर्फ एक नाम नहीं अपितु एक मंत्र है, जिसका नित्य स्मरण करने से सभी दुःखों से मुक्ति मिल जाती है। राम शब्द का अर्थ है- मनोहर, विलक्षण, चमत्कारी, पापियों का नाश करने वाला व भवसागर से मुक्त करने वाला। रामचरित मानस के बालकांड में एक प्रसंग में लिखा है –

नहिं कलि करम न भगति बिबेकू।
राम नाम अवलंबन एकू।।

अर्थात कलयुग में न तो कर्म का भरोसा है, न भक्ति का और न ज्ञान का। सिर्फ राम नाम ही एकमात्र सहारा हैं।

स्कंदपुराण में भी राम नाम की महिमा का गुणगान किया गया है –

रामेति द्वयक्षरजपः सर्वपापापनोदकः।
गच्छन्तिष्ठन् शयनो वा मनुजो रामकीर्तनात्।।
इड निर्वर्तितो याति चान्ते हरिगणो भवेत्।

–स्कंदपुराण/नागरखंड

अर्थात यह दो अक्षरों का मंत्र (राम) जपे जाने पर समस्त पापों का नाश हो जाता है। चलते, बैठते, सोते या किसी भी अवस्था में जो मनुष्य राम नाम का कीर्तन करता है, और अंत में भगवान विष्णु का पार्षद बनता है।

"राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे।
सहस्र नाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने।।"

अयोध्या में अब 52 एकड़ में बनेगा वर्ल्ड-क्लास मंदिर संग्रहालय, टाटा ग्रुप करेगा निर्माण और संचालन

पिंकी कुंडू

योगी सरकार ने अयोध्या को विश्व स्तर पर एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गंतव्य के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने टाटा सन्स के सहयोग से अयोध्या में प्रस्तावित विश्व स्तरीय 'मंदिर संग्रहालय' का दायरा और बड़ा कर दिया है।

कैबिनेट में हुई चर्चा और उसके आधार पर लिए गये निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि टाटा सन्स ने अपने सीएसआर फंड से एक अत्याधुनिक मंदिर संग्रहालय विकसित करने और उसका संचालन करने की इच्छा व्यक्त की है। इसके लिए कम्पनी एक्ट 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर-लाभकारी एसपीवी बनाया जाएगा, जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। परियोजना हेतु भूमि आवंटन के लिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और टाटा सन्स के बीच त्रिपक्षीय एमओयू बीते 3 सितंबर 2024 को हस्ताक्षरित हो चुका है।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि पूर्व में प्रदेश सरकार ने अयोध्या के मांझा जमथरा गांव में 25 एकड़ नजूल भूमि टाटा सन्स को 90 वर्षों के लिए उपलब्ध कराने की अनुमति दी थी, लेकिन टाटा संस ने संग्रहालय की भव्यता के दृष्टिगत अधिक भूमि की अपेक्षा की थी। ऐसे में अब इस भूमि के अतिरिक्त 27.102 एकड़ और मिलाकर कुल 52.102 एकड़ भूमि का निःशुल्क हस्तांतरण आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से पर्यटन विभाग के पक्ष में किया जाएगा, ताकि परियोजना का दायरा और बड़ा किया जा सके।

वर्ल्ड-क्लास मंदिर संग्रहालय तैयार होने के बाद अयोध्या को न सिर्फ एक नया सांस्कृतिक पहचान चिन्ह मिलेगा, बल्कि बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा होंगे। साथ ही, बढ़ते पर्यटन से सरकार को राजस्व में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी भी होगी। बता दें कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और अब ध्वजारोहण समारोह के बाद अयोध्या में पर्यटकों का प्रवाह कई गुना बढ़ चुका हैअब रोजाना लगभग 2 से 4 लाख पर्यटक अयोध्याधाम पहुंच रहे हैं। युवा पीढ़ी, विदेशी सैलानियों और भारतीय संस्कृति में रुचि रखने वाले आगंतुकों को ध्यान में रखते हुए अयोध्या में सांस्कृतिक आकर्षणों को बढाने की दिशा में यह संग्रहालय महत्वपूर्ण होगा।

तीन ऋण जो चुकाना हमारी ज़िम्मेदारी

पिंकी कुंडू

कहते है, जब एक आत्मा धरती पर जन्म लेती है, तो उसके हाथ में खिलौने नहीं, तीन अदृश्य धागे बाँधकर भेजे जाते हैं— धर्म के, प्रेम के और कर्तव्य के

शास्त्र उन्हें "त्रि-ऋण" कहते हैं। और रामायण उन्हें जीकर दिखाती है।

1. देव-ऋण — प्रकृति से मिला हर श्वास एक आशीर्वाद है। वन में प्रवेश करते ही राम रुके। उन्होंने सबसे पहले किसी योद्धा को नहीं, किसी गुरु को नहीं पेड़ों को प्रणाम किया। कितनी अद्भुत बात है कि जिस धरती पर हम चल रहे हैं, जिस वायु से हम सांस ले रहे हैं, जिस आकाश को हम देखते भी नहीं। उसी को हमने सबसे कम "धन्यवाद" दिया है।

रामायण कहती है कि प्रकृति को सम्मान दो, यह देव-ऋण चुकाने का पहला कदम है।

2. ऋषि-ऋण — जो ज्ञान मिला है, उसे दुनिया तक पहुँचाना तुम्हारा धर्म है। जब विश्वामित्र जी ने धनुष-विज्ञान राम को सौंपा, उन्होंने पूछा नहीं— "इसका पुरस्कार क्या है?" राम ने बस कहा—"यह मेरे हाथ नहीं, मेरी नियति को सौंपा गया है।" आधुनिक भाषा में— ज्ञान सिर्फ "स्किल" नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। अगर आपकी सीख किसी और के अंधेरे में एक दीपक नहीं बनती, तो ऋषि-ऋण अधूरा है।

रामायण कहती है— ज्ञान का असली सम्मान उसे आगे देना है।

3. पितृ-ऋण — अपने माता-पिता और वंश का सम्मान तुमसे शुरू होता है। रामायण की सबसे भव्य घटना न राज्याभिषेक थी, न पुल निर्माण, न लंका विजय। सबसे भव्य था— राम का मुस्कुराते हुए वनवास स्वीकार करना। वह मुस्कान त्याग की नहीं, वह कर्तव्य की थी। "मेरे पिता ने मुझे जीवन दिया है, उनकी इच्छा मेरे लिए आदेश नहीं, आशीर्वाद है।" यहीं पितृ-ऋण का सार है— अपने कर्मों से अपने घर, अपने नाम, अपने पूर्वजों की मर्यादा बढ़ाओ।

रामायण फुसफुसाती है कि "अच्छा पुत्र बनना ही सबसे बड़ा धर्म है।"

याद रखिए तीन ऋण हैं-3 debts, one purpose

हम सब जीवन में बहुत भाग रहे हैं— काम, पैसा, रिश्ते, सपने। पर असल में हम बस तीन ऋणों को चुकाने के लिए ही पैदा हुए हैं:

"प्रकृति को सम्मान—देव-ऋण
"ज्ञान को आगे ले जाना—ऋषि-ऋण
"अपने वंश का मान रखना—पितृ-ऋण

यही "त्रि-ऋण" एक साधारण इंसान को मर्यादा-पुरुषोत्तम बना देता है।

राम जैसे बनने के लिए लड़ाइयाँ जीतना जरूरी नहीं, अपना हृदय जीतना ज़रूरी है।

कितने हुए श्री राम ? क्या आप जानते हैं, जाने

पिंकी कुंडू

एक दिन श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे तभी उनकी अंगूठी गिर गई। गिरते ही वह भूमि के एक छेद में चली गई।

हनुमान ने यह देखा तो उन्होंने लघु रूप धरा और उस छेद में से अंगूठी निकालने के लिए घुस गए।

हनुमान तो ऐसे हैं कि वे किसी भी छिद्र में घुस सकते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो।

छेद में चलते गए, लेकिन उसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था तभी अचानक वे पाताल लोक में गिर पड़े। पाताल लोक की स्त्रियां कोलाहल करने लगीं- 'अरे, देखो-देखो, ऊपर से एक छोटा-सा बंदर गिरा है।' उन्होंने हनुमान को पकड़ा और एक थाली में सजा दिया।

पाताल लोक में रहने वाले भूतों के राजा को जीव-जंतु खाना पसंद था इसलिए छोटे-से हनुमानजी को बंदर समझकर उनके भोजन की थाली में सजा दिया। थाली पर बैठे हनुमान पसोपेश में थे कि अब क्या करें।

उधर, श्री रामजी हनुमानजी के छिद्र से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे।

तभी महर्षि वशिष्ठ और भगवान ब्रह्मा उनसे मिलने आए।

उन्होंने श्री राम से कहा- 'हम आपसे एकांत में वार्ता करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई हमारी बात सुने या उसमें बाधा डाले। क्या आपको यह स्वीकार है?'

प्रभु श्री राम ने कहा- 'स्वीकार है।'

इस पर ब्रह्माजी बोले, 'तो फिर एक नियम बनाएं। अगर हमारी वार्ता के समय कोई यहां आएगा तो उसका शिरोच्छेद कर दिया जाएगा।'

प्रभु श्री राम ने कहा- 'जैसी आपकी इच्छा।'

अब सवाल यह था कि सबसे विश्वसनीय द्वारपाल कौन होगा, जो किसी को भीतर न आने दे?

हनुमानजी तो अंगूठी लेने गए थे। ऐसे में श्री राम ने लक्ष्मण को बुलाया और कहा कि तुम जाओ और किसी को भी भीतर मत आने देना। लक्ष्मणजी को भली-भांति समझाकर श्री राम ने द्वारपाल बना दिया।

लक्ष्मण द्वार पर खड़े थे, तभी महर्षि विश्वामित्र वहां आए और कहने लगे- 'मुझे श्री राम से शीघ्र मिलना अत्यावश्यक है। बताओ, वे कहां हैं?'

लक्ष्मण ने कहा- 'आदरणीय ऋषिवर अभी अंदर न जाएं। वे कुछ और लोगों के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण वार्ता कर रहे हैं।'

विश्वामित्र ने कहा- 'ऐसी कौन-सी बात है, जो श्री राम मुझसे छुपाएं?'

विश्वामित्र ने पुनः कहा- 'मुझे अभी के अभी अंदर जाना है।'

लक्ष्मण ने कहा- 'आपको अंदर जाने देने से पहले मुझे उनकी अनुमति लेनी होगी।'

विश्वामित्र ने कहा- 'तो जाओ और पूछो।'

तब लक्ष्मण ने कहा- 'मैं तब तक अंदर नहीं जा सकता, जब तक कि श्री राम बाहर नहीं आते। आपको प्रतीक्षा करनी होगी।'

विश्वामित्र क्रोधित हो गए और कहने लगे- 'अगर तुम अंदर जाकर मेरी उपस्थिति की सूचना नहीं देते हो, तो मैं अपने अभिशाप से अभी पूरी अयोध्या को भस्म कर दूंगा।'

लक्ष्मण के समक्ष धर्मसंकट उपस्थित हो गया। वे सोचने लगे कि अगर अभी अंदर जाता हूं तो मैं मरूंगा और अगर नहीं जाता हूं तो यह ऋषि अपने कोप में पूरे राज्य को भस्म कर डालेंगे।

फिर लक्ष्मण ने सोचा कि ऐसे में बेहतर है कि मैं ही अकेला मरूं इसलिए वे अंदर चले गए।

श्री राम ने पूछा- 'क्या बात है?'

लक्ष्मण ने कहा- 'महर्षि विश्वामित्र आए हैं।'

श्री राम ने कहा- 'अंदर भेज दो।'

विश्वामित्र अंदर गए। एकांत वार्ता तब तक समाप्त हो चुकी थी।

ब्रह्मा और वशिष्ठ जी श्री राम से मिलकर यह कहने आए थे कि 'मृत्युलोक में आपका कार्य संपन्न हो चुका है। अब आप अपने श्री राम अवतार रूप को त्यागकर यह शरीर छोड़ दें और पुनः ईश्वर रूप धारण करें।' ब्रह्मा और वशिष्ठ ऋषि को यही कुल मिलाकर उन्हें कहना था।

लेकिन लक्ष्मण ने श्री राम से कहा- 'भ्राताश्री, आपको मेरा शिरोच्छेद कर देना चाहिए।'

श्री राम ने कहा- 'क्यों? अब हमें कोई और बात करनी ही नहीं थी, तो मैं तुम्हारा शिरोच्छेद क्यों करूं?'

लक्ष्मण ने कहा- 'नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझे सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ सकते कि मैं आपका भाई हूं। यह श्री राम के नाम पर एक कलंक होगा। मुझे दंड मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने आपके एकांत वार्तालाप में विघ्न डाला है। यदि आप दंड नहीं देंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा।'

लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे जिन पर विष्णु शयन करते हैं। उनका भी समय पूरा हो चुका था। वे सीधे सरयू नदी तक गए और उसके प्रवाह में विलुप्त हो गए। जब लक्ष्मण ने अपना शरीर त्याग दिया तो श्री राम ने अपने सभी अनुयायियों, विभीषण, सुग्रीव और दूसरों को बुलाया और अपने जुड़वां पुत्रों लव और कुश के राज्याभिषेक की व्यवस्था की। इसके बाद श्री राम भी सरयू नदी में प्रवेश कर गए।

उधर, इस दौरान हनुमान पाताललोक में थे। उन्हें अंततः भूतों के राजा के पास ले जाया गया। उस समय वे लगातार श्री राम का नाम दुहरा रहे थे, 'श्री राम..., श्री राम..., श्री राम...।'

भूतों के राजा ने पूछा- 'तुम कौन हो?'

हनुमानजी ने कहा- 'मैं हनुमान।'

भूतराज ने पूछा, 'हनुमान? यहां क्यों आए हो?'

हनुमानजी ने कहा- 'श्री राम की अंगूठी एक छिद्र में गिर गई थी। मैं उसे लेने आया हूं।'

भूतों के राजा हंसने लगे और फिर उन्होंने इधर-उधर देखा और हनुमानजी को अंगूठियों से भरी एक थाली दिखाई।

थाली दिखाते हुए कहा- 'तुम अपने श्री राम की अंगूठी उठा लो। मैं नहीं जानता कि कौन-सी अंगूठी तुम्हारे श्री राम की है।'

हनुमान ने सभी अंगूठियों को गौर से देखा और सिर को हिलाते हुए बोले- 'मैं भी नहीं जानता कि इनमें से कौन-सी श्री राम की अंगूठी है, सारी अंगूठियां एक जैसी दिखाई दे रही हैं।'

भूतों के राजा ने कहा कि इस थाली में जितनी भी अंगूठियां हैं सभी श्री राम की ही हैं, लेकिन तुम्हारे श्री राम की इनमें से कौन-सी है, यह तो तुम्हें ही जानना होगा।इस थाली में जितनी अंगूठियां हैं, उतने ही श्री राम अब तक हो चुके हैं।

और सुनो हनुमान, जब तुम धरती पर लौटोगे तो तुम्हें श्री राम नहीं मिलेंगे। श्री राम का यह अवतार अपनी अवधि पूरी कर चुका है।जब भी श्री राम के किसी अवतार की अवधि पूरी होने वाली होती है, उनकी अंगूठी गिर जाती है। मैं उन्हें उठाकर रख लेता हूं। अब तुम जा सकते हो।'

हनुमान आश्चर्यचकित होकर वापस लौट गए..!!

दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में सभी 12 वार्डों के नतीजे आए सामने, 7 पर बीजेपी तो 3 पर आप की जीत

दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में उपचुनाव के नतीजे फाइनल हो गए हैं. बीजेपी ने सात वार्ड पर तो AAP ने तीन पर जीत हासिल की. कांग्रेस को एक वार्ड मिला है.

दिल्ली नगर निगम (MCD) उपचुनाव में सभी 12 वार्डों के नतीजे सामने आ गए हैं. भारतीय जनता पार्टी (BJP) की उम्मीदवार सुमन कुमार गुप्ता ने चांदनी चौक वार्ड, अनीता जैन ने शालीमार बाग बी वार्ड और कांग्रेस उम्मीदवार ने संगम विहार ए वार्ड से जीत हासिल की. एमसीडी के 12 वार्ड में हुए उपचुनाव के लिए सुबह आठ बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 10 मतगणना केंद्रों पर मतों की गिनती शुरू हुई. सुमन कुमार गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हर्ष शर्मा को 1,182 मतों के अंतर से हराया. अनीता जैन ने शालीमार बाग बी वार्ड से जीत हासिल की, जहां से पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता निगम पार्षद थीं.

30 नवंबर को हुआ था मतदान

उपचुनाव के लिए 30 नवंबर को जिन 12 वार्ड में मतदान हुआ था, उनमें से नौ पर पहले भाजपा और बाकी पर आप के निगम पार्षद थे. दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए सभी व्यवस्थाएं की हैं. मतगणना के लिए कंझावला, पीतमपुरा, भरत नगर, सिविल लाइंस, राउज एवेन्यू, द्वारका, नजफगढ़, गोल मार्केट, पुष्प विहार और मंडावली में 10 केंद्र बनाए गए हैं.

दिल्ली पुलिस के करीब 1,800 कर्मियों और अर्द्धसैनिक बलों की 10 कंपनियों को मतगणना के लिए तैनात किया गया है. लगभग 700 कर्मियों को मतगणना के लिए तैनात किया गया है और उम्मीदवारों व उनके अधिकृत मतगणना एजेंट के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. उपचुनावों में मतदान 38.51 प्रतिशत रहा था, जबकि 2022 में एमसीडी के 250 वार्ड पर हुए चुनाव में मतदान प्रतिशत 50.47 था.

MCD के 12 वार्डों के उपचुनाव में बीजेपी ने 7 सीटें जीती हैं जबकि आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है. 1 वार्ड कांग्रेस को मिला है. वहीं, एक सीट निर्दलीय प्रत्याशी के पास है.

1. विनोद नगर—सरला चौधरी बीजेपी
1769 वोटों से जीती

2.द्वारका बी—बीजेपी
मनीषा देवी ने 9100 वोटों से जीत दर्ज की

3. अशोक विहार—बीजेपी
वीना असीजा 405 मतों से जीतीं

4. ग्रेटर कैलाश—बीजेपी
अंजुम मंडल ने 4165 मतों से जीत दर्ज कीॉ

5. दिंचाऊं कला—बीजेपी
रेखा रानी ने 5637 मतों से जीत दर्ज की

6. चांदनी महल—निर्दलीय
मोहम्मद इमरान 4592 वोटों से जीते

7. मुंडका—आम आदमी पार्टी
अनिल ने 1577 मतों से जीत दर्ज की

8. संगम विहार ए—कांग्रेस
सुरेश चौधरी ने 3628 मतों से जीत दर्ज की

9. शालीमार बाग बी—बीजेपी
अनीता जैन ने सबसे ज्यादा 10101 मतों से जीत दर्ज की.

10. दक्षिण पुरी—आम आदमी पार्टी
राम स्वरूप कनौजिया ने 2262 मतों से जीत दर्ज की

11. चांदनी चौक—बीजेपी
सुमन कुमार गुप्ता ने 1182 मतों से जीत हासिल की

12. नारायणा—आम आदमी पार्टी
राजन अरोड़ा ने 148 मतों से जीत दर्ज की.

रोहिणी सेक्टर-7, निर्माणाधीन बिल्डिंग में आए जोरदार धमाके के 24 घंटे बाद भी कोई कार्रवाई नहीं! नवदीप सिंह

मेरठ में प्रकृति फाउंडेशन के द्वारा एक ही मंच पर सम्मानित हुईं माँ और बेटी

(डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)

मथुरा/मेरठ। P-3 स्टूडियो (मेरठ) में प्रकृति फाउंडेशन के द्वारा राष्ट्रीय सेमिनार एवं सम्मान समारोह का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ संपन्न हुआ।जिसके अंतर्गत मथुरा की मेमोरी गर्ल डाक्टर प्रेरणा शर्मा और उनकी माँ वरिष्ठ साहित्यकार उषा शर्मा 'प्रिया' का सम्मान किया गया। उन्हें यह सम्मान समारोह की अध्यक्षता प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर ममता नौगरिया (बदायूं) एवं मुख्य अतिथि प्रख्यात साहित्यकार डॉ. मिथिलेश दीक्षित (लखनऊ) तथा मुख्य वक्ता के रूप में सतीश 'सहज' (मेरठ) के द्वारा संयुक्त रूप से प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्र एवं ठाकुरजी का पटुका-प्रसादी-माला आदि भेंट करके दिया गया।सम्मान समारोह के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 31 महान विभूतियों को भी सम्मानित किया गया।

मुख्य वक्ता सतीश 'सहज' (मेरठ) ने कहा कि मेमोरी गर्ल प्रेरणा शर्मा ने अपनी प्रतिभा के बल पर भारत ही नहीं विदेशों में भी अपने नाम का परचम लहराया है। उन्होंने अपने 8 राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ 45 बच्चों के रिकॉर्ड भी बनवाए हैं।

इस अवसर पर डॉ. सुबोध, आर.के. भटनागर, उमेश वर्मा, चरण सिंह स्वामी, रीना मित्तल, निशा वर्मा, आयुष वर्मा, डॉ. नीलम मिश्रा आदि की उपस्थिति विशेष रही।

संस्था की अध्यक्षा निरुपमा वर्मा एवं सचिव मुकेश नादान के द्वारा सभी आगंतुक अतिथियों तथा अलंकृत विभूतियों का आभार व्यक्त किया गया।

ब्रज साहित्य सेवा मंडल के अध्यक्ष "यूपी रत्न" डॉक्टर गोपाल चतुर्वेदी ने दोनों के सम्मान पर हर्ष व्यक्त करते हुए उनके उज्ज्वल, सुखद, समृद्ध एवं सुदीर्घ जीवन की मंगल कामना की है।

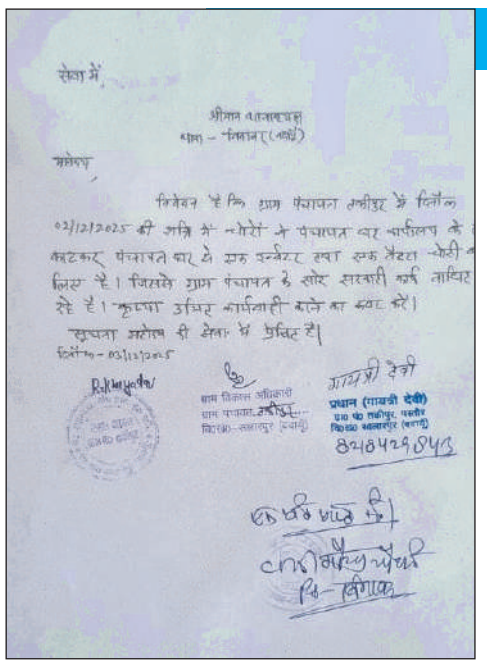

थाना बिनावर क्षेत्र में लगातार बढ़ती जा रही चोरी की घटनाएं

परिवहन विशेष न्यूज

बदायूं: थाना बिनावर क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तकीपुर, रसूलपुर, तिसंगा और बगुली नगर गांव में सपा के पूर्व नेता मोद प्रकाश पाल के घर हुई 50 लाख की चोरी की घटना का अभी तक नहीं हुआ है खुलासा हैं, अज्ञात चोरों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर आए दिन सवाल उठ रहे हैं।

थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन पुलिस अभी तक किसी भी बड़ी वारदात का खुलासा नहीं कर सकी है। बीते एक माह में तकीपुर, रसूलपुर, नरखेड़ा, तिसंगा, निजामपुर, ददमई, बगुली नगर,

निजामपुर पश्तौर, ईशवनगर, भिन्दुलिया, नौसाना जैसे आदि गांवों दर्जनों पंचायत घर में चोरी और डकैती की कई घटनाएं हुईं, जिनका आज तक थाना बिनावर पुलिस कोई सुराग नहीं लगा सकी। जिससे ग्रामीणों में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर गहरा रोष है। करीब चार दिन पहले बरेली - बदायूं हाईवे मार्ग स्थित पंचायत घर में रखा लाखों का सामान के साथ बैटरी तक चोरी कर ली गई थी। वहीं, थाना बिनावर क्षेत्र के बिलहैत रोड स्थित गांव बगुलीनगर के पूर्व सपा नेता मोद प्रकाश पाल के यहां भी लाखों रुपये एवं नगदी जेवर की चोरी हुई, लेकिन पुलिस अभी तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है।

इस संबंध में शिव कुमार सहायक विकास अधिकारी पंचायत सालारपुर का कहना है कि अब तक दर्जनों पंचायत घरों से चोरी हो चुकी है लेकिन अभी तक थाना बिनावर पुलिस ने किसी भी चोरी की घटना का खुलासा नहीं किया है। जिसको लेकर क्षेत्र में व्यापक चर्चा का विषय बना हुआ है।

इस संबंध में ग्राम प्रधान नौसाना गिरीश पाल शाक्य का कहना है कि उनके यहां पंचायत घर से हुई चोरी की घटना का थाना बिनावर पुलिस ने बताया कि खुलासा हो गया है लेकिन चोरी हुए सामान को नहीं सौपा गया है।

इस संबंध में पूर्व सपा नेता मोद प्रकाश पाल का कहना है कि उनके घर से हुई लाखों की चोरी की घटना का पुलिस ने नहीं किया कोई खुलासा। उन्होंने मजबूर होकर आईजी, डीआईजी, एडीजी जॉन बरेली को शिकायत प्रार्थना पत्र देकर अपनी समस्या अवगत कराई है।

लापता

नाम=सुरेन्द्र प्रसाद गुप्ता
पता=मीठापुर बदरपुर
मीठापुर बदरपुर से दिनांक 27/11/2025 को सुबह 7 बजे से लापता है|
अगर किन्हीं को दिखे तो प्लीज़ हमे इस मोबाइल नंबर पे संपर्क करें|
मोबाइल नंबर =96613 33439

भारतीय रुपए की अंतरराष्ट्रीय स्थिति,वैश्विक मुद्राओं में मूल्यांकन और विज़न 2047 का रोडमैप -एक विस्तृत विश्लेषण

भारतीय रुपए की अंतरराष्ट्रीय स्थिति सदैव भारत की आर्थिक संरचना,विकास दर, निर्यात- आयात संतुलन और वैश्विक आर्थिक घटनाओं से गहराई से प्रभावित होती रही है

डॉलर-निर्भर वैश्विक व्यापार प्रणाली में आईएनआर की भूमिका बढ़ रही है,लेकिन उतनी दृढ़ नहीं हो सकी है कि उसे विश्व व्यापार की प्राथमिक मुद्राओं में शामिल किया जा सके-एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तरपर दुनियाँ में 195 से अधिक देश हैं, और हर देश अपनी अलग मुद्रा का इस्तेमाल करता है।दुनियाँ में सबसे लोकप्रिय मुद्राएँ डॉलर, यूरो,पाउंड, दीनार रियाल, येन आदि हैं। एक देश से दूसरे देश की यात्रा करते समय,उस देश में लेन-देन करने के लिए मुद्रा विनिमय की आवश्यकता होती है ।सरकार मुद्रा जारी करती है;इसे वैध मुद्रा भी कहा जाता है। मुद्रा का मूल्य स्थिर नहीं रहता और हर दिन बदलता रहता है। मुद्रा का मूल्य विभिन्न देशों में अलग- अलग होता है।पिछले सप्ताह के दौरान,अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपये की विनिमय दर 02-12-2025 को 89.755 के उच्चतम स्तर और 25-11- 2025 को 89.0625 के निम्नतम स्तर के बीच उतार- चढ़ाव करती रही।24 घंटे में सबसे बड़ा मूल्य परिवर्तन 01-12-2025 को हुआ, जिसमें मूल्य में 0.235 प्रतिशत की वृद्धि हुई।भारतीय रुपए (आईएनआर) की अंतरराष्ट्रीय स्थिति सदैव भारत की आर्थिक संरचना,विकास दर, निर्यात- आयात संतुलन और वैश्विक आर्थिक घटनाओं से गहराई से प्रभावित होती रही है। वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिवेश, जहाँ अमेरिका और यूरोप जैसी अर्थव्यवस्थाएँ अपनी मौद्रिक नीतियों को लगातार सख्त कर रही हैं, वहीं भारत जैसे उभरते देशों की मुद्राएँ प्रत्यक्ष रूप से डॉलर के उतार-चढ़ाव से प्रभावित हो रही हैं। इस स्थिति में भारतीय रुपया एक संक्रमणकाल में खड़ा है।एक ओर वह विश्व की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था की मुद्रा है, वहीं दूसरी ओर उसकी अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता और मूल्यांकन अभी भी सीमित है।डॉलर-निर्भर वैश्विक व्यापार प्रणाली में आईएनआर की भूमिका बढ़ रही है लेकिन वह अभी भी उतनी दृढ़ नहीं हो सकी है कि उसे विश्व व्यापार की प्राथमिक मुद्राओं में शामिल किया जा सके। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं क़ि अंतरराष्ट्रीय स्तरपर भारतीय रुपया इस समय एक ऐसी मुद्रा के रूप में देखा जाता है जो स्थिर भी है और चुनौतीपूर्ण भी। स्थिर इसलिए कि भारत का वित्तीय तंत्र मजबूत है, विदेशी मुद्रा भंडार विश्व के शीर्ष देशों में आता है, और आर्थिक विकास दर दुनियाँ में सबसे तेजों में है। लेकिन चुनौती इसलिए कि रुपये की विनिमय दर अभी भी बाहरी कारकों विशेषकर अमेरिकी डॉलर पर अत्यधिक निर्भर है। डॉलर के मजबूत होने से भारत जैसे देशों की मुद्राओं पर स्वतः दबाव आता है और यह दबाव बढ़ते विदेशी निवेश बहिर्वाह, अस्थिर वैश्विक बाजार और तेल-कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण और भी घना हो जाता है। इसी वजह से भारतीय रुपये की अंतरराष्ट्रीय मजबूती अक्सर वैश्विक परिस्थितियों से निर्धारित होती है, न कि केवल भारत की घरेलू आर्थिक क्षमता से जो महत्वपूर्ण कारक है।

साथियों बात अगर हम वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) के नज़रिए से देखनें की करें तो तस्वीर अपेक्षाकृत संतुलित दिखाई देती है। यह दर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, मुद्रास्फीति और क्रय-शक्ति के आधार पर तय होती है। कई वर्षों के विश्लेषण से पता चलता है कि रुपया नाममात्र गिरता हुआ दिखता है, लेकिन वास्तविक प्रतिस्पर्धात्मकता उतनी खराब नहीं होती जितनी यूएसडी/आईएनआर दर को देखकर समझा जाता है। इसका एक कारण यह भी है कि भारत का निर्यात आधार विस्तार कर रहा है, सेवा-क्षेत्र वैश्विक स्तर पर प्रमुख है, और घरेलू बाजार की स्थिरता बाहरी दबावों को किसी हद तक संतुलित करती है।

साथियों बात अगर हम अब यदि हम भारतीय रुपये की तुलना अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं से करें, विशेषकर विकसित और विकासशील देशों की प्रमुख मुद्राओं से,तो वर्तमान स्थिति इस प्रकार उभरती है कि आईएनआर अधिकांश अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं के मुकाबले कमजोर है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 89- 90 रुपये का मूल्य बताता है कि पिछले एक दशक में रुपये ने धीरे-धीरे कमजोरी दिखाई है। यूरो, ब्रिटिश पाउंड और जापानी येन जैसी स्थिर मुद्राओं के मुकाबले भी आईएनआर का मूल्यांकन दर्शाता है कि भारत को अभी भी वैश्विक आर्थिक धारा में अधिक स्थिरता प्राप्त करने की आवश्यकता है।हालांकि यह भी ध्यान देने योग्य है कि मुद्रा की कमजोरी हमेशा नकारात्मक संकेत नहीं होती,कई देश जानबूझकर अपनी मुद्रा को प्रतिस्पर्धी बनाए रखते हैं ताकि निर्यात को बढ़ावा मिले और घरेलू उद्योगों को लाभ हो। भारत की परिस्थिति मिश्रित है:कमजोर मुद्रा से निर्यात को कुछ हद तक सहारा मिलता है,लेकिन ऊर्जा- आयात पर भारी निर्भरता भारतीय अर्थव्यवस्था पर महंगा प्रभाव डालती है।यदि मध्य एशियाई देशों,जैसे कज़ाख़स्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा के मुकाबले आईएनआरकी स्थिति का आकलन किया जाए,तो स्पष्ट होता है कि यहाँ आईएनआर कुछ मामलों में अधिक स्थिर दिखाई देता है। कई मध्य एशियाई देशों की मुद्रा राजनीतिक अस्थिरता, राजकोषीय सीमाओं और व्यापारिक निर्भरता के कारण अधिक उतार-चढ़ाव का सामना करती है। ऐसे में आईएनआर अपेक्षाकृत स्थिर मुद्रा है, जिससे भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापारिक संबंधों में सकारात्मक अवसर बनते हैं।चूंकि भारत इन देशों के साथ ऊर्जा, रक्षा, शिक्षा, फार्मास्यूटिकल और तकनीकी सहयोग बढ़ा रहा है, इसलिए आईएनआर का इन क्षेत्रों में लेन-देन मूल्य धीरे-धीरे बढ़ सकता है।

साथियों बात अगर कर हम अब भारतीय रुपये के भविष्य की बात करें तो विशेषकर विज़न 2047 के संदर्भ में, तो तस्वीर अत्यंत रोचक और बहुआयामी है। भारत का लक्ष्य 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का है। यदि यह लक्ष्य आर्थिक संरचना, नीति-निर्माण, उद्योग-विकास, अवसंरचना विस्तार और तकनीकी शक्ति के आधार पर पूरा होता है,तो निश्चित ही आईएनआर की वैश्विक स्थिति आज की तुलना में कहीं अधिक मजबूत होगी। भारत 2047 तक 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के अनुमान के साथ चलता है, जहाँ प्रति व्यक्ति आय में भी कई गुना वृद्धि होगी। इस तरह की विशाल आर्थिक क्षमता मुद्रा की अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता को स्वाभाविक तौर पर बढ़ाएगी।

साथियों बात अगर हम 2047 के भारत में रुपया कैसा होगा, इसको समझने की करें तो यह सवाल आर्थिक नीति-निर्माताओं, बाज़ार विशेषज्ञों और वैश्विक निवेशकों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। यदि भारत वर्तमान विकास दर को बनाए रखता है, ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाता है, विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत करता है, व्यापार- घाटा नियंत्रित रखता है, और अधिक देशों के साथ रुपये में व्यापार शुरू करता है,तो यह संभव है कि आने वाले वर्षों में आईएनआर अधिक स्थिर और मजबूत मुद्रा के रूप में उभरे। इसके अलावा, डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी,सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी), फिनटेक, डिजिटल भुगतान, और वैश्विक मुद्रा- विनिमय नेटवर्क में भारत की सक्रियता रुपये की स्वीकार्यता बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएगी।2047 में आईएनआर की संभावित विनिमय दर का अनुमान लगाना कई अनिश्चितताओं के कारण कठिन है। परंतु विकासशील और विकसित होने की दिशा में बढ़ रहे भारत की आर्थिक संरचना बताती है कि रुपये का अंतरराष्ट्रीय मूल्यांकन आज जैसा नहीं रहेगा। यह मजबूत भी हो सकता है, स्थिर भी हो सकता है, और वैश्विक मुद्रा-प्रणाली में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकता है। यदि भारतीय अर्थव्यवस्था निर्यात-प्रधान बनती है तो आईएनआर की मजबूती बढ़ेगी। यदि भारत ऊर्जा -आयात पर निर्भरता कम करता है और रक्षा, तकनीक, एआई, फार्मा, अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में अग्रणी बनता है, तो आईएनआर का मूल्यांकन आज की तुलना में कहीं अधिक अनुकूल हो सकता है।रुपये की मज़बूती केवल डॉलर की तुलना से नहीं मापी जाती। किसी भी मुद्रा की प्रभावशाली स्थिति उसके क्रय-शक्ति, स्थिरता, वैश्विक उपयोग, व्यापार-संतुलन और निवेशकों के भरोसे से तय होती है। भारत आज यह भरोसा लगातार बढ़ा रहा है, और यदि यह यात्रा 2047 तक सही दिशा में चलती रही, तो आईएनआर एक ऐसी मुद्रा हो सकती है जिसे दुनिया केवल उभरती अर्थव्यवस्था की मुद्रा के रूप में नहीं, बल्कि विकसित और स्थिर आर्थिक शक्ति के रूप में पहचानेगी।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे क़ि,भारतीय रुपये का भविष्य बेहद हद तक भारत की आर्थिक नीतियों, वैश्विक परिदृश्य, राजनीतिक स्थिरता,तकनीकी नवाचार और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों पर निर्भर करेगा। यदि भारत वैश्विक व्यापार में बड़े पैमाने पर रूपये-आधारित लेन-देन की दिशा में सफल कदम उठाता है, डॉलर पर निर्भरता घटाता है,और डिजिटल- वित्तीय व्यवस्था में नेतृत्व भूमिका निभाता है, तो 2047 में आईएनआर उस स्थिति में हो सकता है जिसकी आज केवल कल्पना की जा रही है, एक स्थिर, मजबूत, विश्वसनीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में स्वीकार्य मुद्रा।

2030 राष्ट्रमंडल खेल और 2036 विश्व-ओलंपिक : भारत की सांस्कृतिक-शक्ति रणनीति का अवसर

--- डॉ सत्यवान सौरभ

सन 2030 के राष्ट्रमंडल खेल भारत के लिए केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि सन 2036 के विश्व-ओलंपिक प्रस्ताव का निर्णायक "अग्रदूत" है। यह आयोजन भारत की सांस्कृतिक-शक्ति (सॉफ्ट पावर) को नई ऊँचाई दे सकता है, परन्तु किसी भी प्रकार की प्रशासनिक कमी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को आघात पहुँचा सकती है।

विशाल खेल आयोजन किसी भी राष्ट्र के लिए मात्र खेल-प्रतियोगिताएँ नहीं होते, बल्कि वे उस देश की राजनीतिक इच्छा-शक्ति, आर्थिक सामर्थ्य, सांस्कृतिक पहचान और प्रशासनिक परिपक्वता का सार्वजनिक प्रदर्शन भी होते हैं। आधुनिक समय में खेल कूटनीति एक प्रकार की सांस्कृतिक-शक्ति बन चुकी है—ऐसी शक्ति जो बिना किसी सैन्य बल के, विश्व समुदाय को अपने अनुकूल प्रभावित कर सकती है। भारत लंबे समय से अपनी प्रतिष्ठा के विविध आयामों को सुदृढ़ करने का प्रयास करता आया है, और सन 2036 के विश्व-ओलंपिक आयोजन की महत्वाकांक्षा इसी दिशा का एक स्वाभाविक कदम है।

परंतु ओलंपिक जैसे विराट आयोजन से पहले सन 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी को भारत एक प्रकार के "पूर्वाभ्यास", "पूर्व-ओलंपिक नमूने" और "वैश्विक विश्वास की परीक्षा" के रूप में देख रहा है। यह रणनीति जितनी आकर्षक संभावनाएँ प्रदान करती है, उतनी ही गंभीर आर्थिक, प्रशासनिक और सामाजिक चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करती है।

भारत जैसे विविधतापूर्ण लोकतंत्र में इस प्रकार के आयोजनों की तैयारी केवल खेल मंत्रालय का नहीं, बल्कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, नगर निकायों, सुरक्षा संस्थाओं, निजी क्षेत्र, तकनीकी विशेषज्ञों, खेल संघों और व्यापक समाज—सभी का संयुक्त प्रयास मांगती है। यदि भारत 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों को सफलतापूर्वक आयोजित कर लेता है, तो यह विश्व स्तर पर यह संदेश जाएगा कि देश 2036 के विश्व-ओलंपिक जैसे महाकाय आयोजन को संभालने में सक्षम है। यही कारण है कि यह आयोजन भारत की विश्वसनीयता के लिए एक निर्णायक पड़ाव साबित हो सकता है।

भारत की सबसे बड़ी प्रेरणा सांस्कृतिक-शक्ति को सुदृढ़ करना है। आज वैश्विक राजनीति में खेल आयोजन एक सांस्कृतिक प्रसार से आगे बढ़कर राष्ट्र की क्षमताओं की खुली परीक्षा बन चुके हैं। राष्ट्र अपनी तकनीकी दक्षता, शहर-प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, सामाजिक समावेशन, पर्यावरण-जागरूकता और सांस्कृतिक आत्मविश्वास का विश्व मंच पर प्रदर्शन करते हैं। भारत यदि सन 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों को उच्च स्तर पर सम्पन्न करता है, तो यह निःसंदेह भारत की प्रतिष्ठा को नई ऊँचाई प्रदान करेगा।

किन्तु इस प्रतिष्ठा की कीमत क्या होगी? यह वह कठिन प्रश्न है जिसे अनदेखा करना भारत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। विशाल खेल आयोजनों का सबसे विवादास्पद पहलू उनकी भारी आर्थिक लागत है। सन 2010 के राष्ट्रमंडल खेल अभी तक भारत की प्रशासनिक छवि पर एक दाग की तरह मौजूद हैं—अत्यधिक खर्च, भ्रष्टाचार, समय पर कार्य न होना, और आयोजन स्थल की कमज़ोर गुणवत्ता ने भारत की छवि को काफी प्रभावित किया था। यदि वर्ष 2030 में फिर ऐसी ही कोई कमी सामने आती है, तो 2036 विश्व-ओलंपिक का सपना लगभग असंभव हो सकता है। इसलिए आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता, बहु-स्तरीय जाँच, और जवाबदेही-व्यवस्था को आज से ही प्राथमिकता देनी होगी। इन सबके साथ-साथ 2030 का आयोजन भारत के लिए एक प्रयोगशाला भी सिद्ध हो सकता है। यह अवसर होगा—शहरी अधोसंरचना, यातायात प्रबंधन, आपदा-प्रतिक्रिया, हरित ऊर्जा, जल-निकास प्रणाली, स्वास्थ्य सेवाओं, सार्वजनिक सुरक्षा, और खेल विज्ञान को अंतरराष्ट्रीय मानक पर परखने का। इस स्तर के आयोजनों में क्षण भर की चूक भी बड़े संकट उत्पन्न कर सकती है। इसलिए वर्ष 2030 का आयोजन भारत के लिए पूर्ण स्तर वाला अभ्यास सिद्ध हो सकता है, जिसमें न केवल खेल प्रबंधन बल्कि सम्पूर्ण शासन प्रणाली की परीक्षा होगी।

इसके अतिरिक्त, शहरी प्रशासन को सबसे कठिन परीक्षा से गुज़रना होगा। कोई भी विशाल खेल आयोजन केवल खेल-स्थल और खिलाड़ियों की आवास-सुविधा तक सीमित नहीं रहता। यह पूरे नगर के परिवहन, मार्ग-संरचना, हवाई अड्डों की क्षमता, स्वच्छता प्रणाली, जल प्रबंधन, रात्रिकालीन प्रकाश व्यवस्था, अस्पतालों की तैयारी, भीड़ नियंत्रण, पर्यावरणीय संवेदनशीलता और आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग का तनाव परीक्षण बन जाता है। संभावित मेज़बान नगर—दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई या किसी बहु-नगर मॉडल—सभी पर भारी तैयारी का दबाव होगा।

यह तैयारी अवसर भी है और चुनौती भी। अवसर इसलिए कि इससे नगरों का बुनियादी ढाँचा विश्व-स्तर पर पहुँच सकता है। चुनौती इसलिए कि यदि ऐसा न हो तो यह निवेश केवल "दिखावे की अधोसंरचना" में बदल जाए, जो आयोजन—उपरांत उपयोगहीन रह जाए। दुनिया में अनेक उदाहरण हैं जहाँ खेल आयोजनों में बनाए गए स्टेडियम और भवन बाद में "मरे हुए ढाँचे" बन गए। भारत में भी यह समस्या पहले देखी जा चुकी है। इसलिए यह अनिवार्य है कि जो भी अवसंरचना बनाई जाए, वह आयोजन के बाद भी जनसाधारण, खेल प्रशिक्षण संस्थानों और नगर-विकास के लिए उपयोगी बनी रहे।

भारत को पर्यटन, आतिथ्य, सांस्कृतिक प्रदर्शनों, कला एवं हस्तशिल्प, पारंपरिक संगीत, खानपान और जातीय विविधता जैसे क्षेत्रों में अपार लाभ प्राप्त होने की संभावना है। विश्व भर से लाखों दर्शक और प्रतिनिधि भारत आएँगे, जिससे सेवा क्षेत्र, व्यापार, परिवहन, कृषि-आधारित उद्योग और सूक्ष्म उद्योगों को व्यापक लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त, डिजिटल भारत की अवधारणा—जैसे पूर्णतः डिजिटल प्रवेश-प्रणाली, दूर-संवेदन सुरक्षा व्यवस्था, तेज़ संचार तंत्र—विश्व के सामने भारत की प्रौद्योगिकी क्षमता का अत्यंत प्रभावशाली प्रदर्शन कर सकती है।

फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि विश्व-ओलंपिक जैसी प्रतियोगिताओं की लागत बहुत भारी होती है। वर्तमान वैश्विक औसत के आधार पर यह लागत अत्यधिक बढ़ जाती है। ऐसे में भारत के लिए यह आवश्यक है कि 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों को एक वित्तीय प्रयोगशाला की तरह उपयोग किया जाए, जहाँ सार्वजनिक-निजी सहभागिता, सामाजिक उत्तरदायित्व निधि, पर्यटन आधारित आय, और भागीदारी मॉडल जैसे उपायों की पहले से जाँच हो सके। यह देखा जा सके कि कौन-सा मॉडल भारत की सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अधिक स्थायी और सफल हो सकता है।

परंतु आलोचना का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि क्या भारत जैसे विकासशील राष्ट्र को इतने बड़े आयोजनों पर अत्यधिक धन व्यय करना उचित है? क्या यह धन विद्यालयों, स्वास्थ्य सेवाओं, ग्रामीण खेलों, महिला खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, खेल विज्ञान प्रयोगशालाओं और खेल अकादमियों जैसे बुनियादी क्षेत्रों में अधिक प्रभावी रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता? यह प्रश्न अत्यंत तर्कसंगत है। किसी भी खेल आयोजन का मूल उद्देश्य "राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की चमक" नहीं, बल्कि "राष्ट्रीय प्रतिभा का विकास" होना चाहिए। यदि आयोजन पर खर्च किए गए संसाधन जमीनी स्तर के खेल ढांचे से ध्यान हटाकर केवल भव्यता के निर्माण में लग जाएँ, तो यह राष्ट्रहित के प्रतिकूल होगा।

इसके अतिरिक्त, यह आयोजन भारत की अंतरराष्ट्रीय कूटनीति को भी नया आयाम प्रदान कर सकता है। भारत पहले से विश्व-दक्षिण समूह का अग्रणी प्रतिनिधि बन रहा है, और वैश्विक संस्थाओं में उसका योगदान निरंतर बढ़ रहा है। ऐसे में सफल खेल मेज़बानी भारत की बहुआयामी नेतृत्व क्षमता को और सुदृढ़ करेगी। इससे यह संदेश जाएगा कि भारत अब केवल उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक ज़िम्मेदार, सक्षम और विश्वसनीय आयोजक राष्ट्र बन चुका है।

फिर भी अंतिम प्रश्न यही है—क्या भारत संस्थागत रूप से तैयार है? खेल संघों में आंतरिक राजनीति, पारदर्शिता का अभाव, भ्रष्टाचार, चयन प्रक्रियाओं की कमज़ोरी और प्रशासनिक अनिश्चितता—ये समस्याएँ अभी भी भारतीय खेल तंत्र को कमज़ोर बनाती हैं। यदि इन कमियों को दूर न किया गया तो 2030 और 2036 दोनों आयोजनों की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।

अंततः, 2030 के राष्ट्रमंडल खेल भारत के लिए एक विशाल अवसर और उतनी ही बड़ी ज़िम्मेदारी हैं। यह आयोजन भारत की सांस्कृतिक-शक्ति, तकनीकी क्षमता, सांस्कृतिक विविधता और प्रशासनिक दक्षता का विश्वव्यापी प्रदर्शन हो सकता है। यह 2036 विश्व-ओलंपिक के प्रस्ताव का निर्णायक पथ भी साबित हो सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब भारत इसे केवल दिखावे का आयोजन न समझकर, इसे दीर्घकालिक राष्ट्रहित से जोड़कर देखे। यदि निवेश टिकाऊ हो, नीतियाँ पारदर्शी हों, प्रशासन उत्तरदायी हो, और अधोसंरचना जनता के उपयोग में बनी रहे, तो यह दोनों आयोजन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय खोल सकते हैं।

स्पष्ट है—2030 राष्ट्रमंडल खेल केवल "एक आयोजन" नहीं, बल्कि भारत की वैश्विक पहचान, आर्थिक भविष्य और कूटनीतिक शक्ति का एक विस्तृत परीक्षण है। यह वह मोड़ है जहाँ सफलता भारत को विश्व खेल-पटल के केंद्र में स्थापित कर सकती है, और किसी भी प्रकार की विफलता उसे वर्षों पीछे धकेल सकती है। इसलिए भारत को इस यात्रा में संकल्प, सावधानी और दूरदृष्टि—तीनों का संतुलन बनाए रखना होगा।

पर्यावरण पाठशाला – वृक्षो रक्षति रक्षितः

- डॉ. अंकुर शरण

प्रिय पाठको,

"वृक्षो रक्षति रक्षितः, तस्मात् वृक्षान् रक्षतु वृक्षकः।
यः वृक्षान्न रक्षति, तं हन्ति प्रकृतिः स्वयं॥"

इस श्लोक का भाव केवल शब्द नहीं है — यह हमारी आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुका है। जो वृक्षों की रक्षा करता है, वही जीवन की रक्षा करता है। और जो प्रकृति से विमुख हो जाता है, प्रकृति स्वयं उससे विमुख हो जाती है।

बुधवार को वृक्षारोपण का विशेष महत्व माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध ग्रह हरितिमा, बुद्धि, विवेक और संवेदनशीलता से जुड़ा है। पौधा लगाना केवल एक धार्मिक या ज्योतिषीय कर्म नहीं, बल्कि मनुष्यता को सशक्त करने वाला कर्म है। जब हम वृक्ष लगाते हैं, तो हम केवल हरियाली नहीं उगाते — हम आने वाली पीढ़ियों के लिए, आशा का बीज बोते हैं।

स्प्रिंगफील्ड, फरीदाबाद के RWA एवं स्थानीय निवासियों को नमन। सामूहिक सहभागिता से आपने यह सिद्ध कर दिया कि जब समाज एकजुट होकर सकारात्मक भाव से कार्य करता है, तो परिवर्तन स्वयं रास्ता बना लेता है। पिछले दो दशकों में इस सोसाइटी की हरियाली और सुंदर पार्कों की अविश्वसनीय यात्रा मैंने स्वयं देखी है — यह एकता, समर्पण और खुशमिज़ाजी की सजीव मिसाल है।

हम जीवन भर अपने लिए तन, मन और धन कमाते हैं — पर क्या कभी हमने प्रकृति को लौटाने का संकल्प लिया है?

आइए, अपने जीते-जी कुछ ऐसा कर जाएँ कि हमारे बाद भी हमारी साँसें इन वृक्षों की हरियाली में बहती रहें।

एक पौधा लगाना — किसी अनजाने चेहरे के जीवन को बचाने जैसा है।

एक पेड़ को सींचना — भविष्य की मुस्कान को आकार देना है।

आज संकल्प लें —

पेड़ लगाएँगे, पेड़ बचाएँगे, और हरियाली को अपनी विरासत बनाएँगे।

प्रकृति को धन्यवाद कहने का सबसे सुंदर तरीका यही है —

उसे संवारना, सहेजना और आगे बढ़ाना।

हरित शुभकामनाओं के साथ,

सिपरी रिपोर्ट: हथियारों की बढ़ती बिक्री और मानवता पर खतरा

दुनिया में हथियारों की बिक्री लगातार बढ़ रही है। वास्तव में, आज के समय में दुनिया भर में बढ़ते हथियारों का जखीरा केवल सुरक्षा का ही सवाल नहीं है, बल्कि यह मानवता के भविष्य पर एक गंभीर खतरा भी है। कोई भी देश हथियार इसलिए खरीदते हैं, ताकि वे अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकें, रणनीतिक बढ़त बनाए रख सकें और बदलते भू-राजनीतिक हालात में खुद को एक मज़बूत राष्ट्र दिखा सकें, लेकिन यही हथियारों की दौड़ कई बार तनाव बढ़ाकर युद्धों की जमीन तैयार करती है,जो कि ठीक नहीं है। कहना ग़लत नहीं होगा कि हथियारों पर होने वाला भारी खर्च शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पानी, जलवायु संरक्षण और रोजगार जैसे बुनियादी क्षेत्रों से धन को खींच लेता है, और इसका असर कहीं न कहीं देश के विकास और अर्थव्यवस्था व इसके निवासियों पर भी पड़ता है। क्या यह बड़ी बात नहीं है कि आज के समय में दुनिया के विभिन्न शक्तिशाली व संपन्न देश इसका इस्तेमाल अपने आर्थिक लाभ, वैश्विक प्रभाव दिखाने और उद्योगों में बढ़त के लिए करते हैं, जबकि छोटे देश किसी दबाव में आकर या सुरक्षा के डर से हथियारों की इस अंधी दौड़ में शामिल हो जाते हैं।इसका नतीजा यह है कि दुनिया एक ऐसी दिशा में बढ़ रही है जहां भरोसा कम और अविश्वास ज्यादा है। वास्तव में, यह बात ठीक है कि हथियार किसी देश को सुरक्षा दे सकते हैं, लेकिन स्थायी शांति नहीं। असली सुरक्षा संवाद, विश्वास, सहयोग और संतुलित विकास से मिलती है न कि विनाशकारी हथियारों की बढ़ती संख्या से। वास्तव में, यह इसलिए दुनिया का खतरनाक कदम है, क्योंकि यह मानवता को सुरक्षा नहीं, बल्कि असुरक्षा की ओर धकेल रहा है।हथियारों की होड़ अंततः दुनिया में असंतुलन पैदा करती है। यहां पाठकों को बताता चलूं कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिपरी) की नई रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में हथियारों की बिक्री लगातार बढ़ रही है।सरल शब्दों में कहें तो दुनिया भर में हथियारों की खरीद-फरोख्त लगातार बढ़ रही है, और यह कोई अच्छी खबर नहीं है। रिपोर्ट बताती है कि कई देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है।कहीं सीमा विवाद है, कहीं शक्ति दिखाने की होड़, तो कहीं सुरक्षा का डर। पाठक जानते होंगे कि दुनिया में इस समय कई देशों के बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा है। एशिया में भारत-चीन के बीच एवं एसी पर लंबे समय से सीमा विवाद बना हुआ है, जो समय-समय पर सैनिक तैनाती और गश्त के कारण फिर उभर जाता है। भारत-पाकिस्तान के बीच कश्मीर और सीमा पार आतंकवाद को लेकर रिश्ते लगातार तनावपूर्ण रहते हैं और कूटनीतिक संबंधों में उतार-चढ़ाव चलता रहता है। चीन-ताइवान के बीच स्थिति सबसे संवेदनशील है, जहाँ चीन ताइवान पर दबाव बढ़ाने के लिए सैन्य अभ्यास और शक्ति-प्रदर्शन कर रहा है, जबकि ताइवान अपनी रक्षा क्षमता बढ़ा रहा है। ईरान-इज़राइल के बीच हमलों और जवाबी हमलों के कारण पश्चिम एशिया में अस्थिरता बढ़ी हुई है। वहीं आर्मेनिया-अज़रबैजान के बीच नगार्नो-काराबाख को लेकर पुराना सीमा विवाद अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ। मध्य एशिया में भी अफगानिस्तान की सीमा को लेकर ताजिकिस्तान और रूस मिलकर सुरक्षा मजबूत करने की बात कर रहे हैं। इधर, रूस-यूक्रेन तनाव आज भी बेहद गंभीर रूप में बना हुआ है। रूस लगातार यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में हमले कर रहा है, जबकि यूक्रेन अपने सहयोगी देशों की मदद से जवाबी कार्रवाई कर रहा है। हाल की शांति-वार्ताएँ भी किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाई हैं, क्योंकि रूस अपनी शर्तों पर अड़ा है और पश्चिमी देश यूक्रेन की संप्रभुता पर समझौता नहीं करना चाहते। इसी बीच मिसाइल हमलों, भू-भाग पर कब्जे की कोशिशों और कूटनीतिक आरोप-प्रत्यारोप ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। यह संघर्ष न केवल यूरोप बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर असर डाल रहा है।कुल मिलाकर, सीमा विवादों, सैन्य तैयारियों, शक्ति दिखाने की होड़ और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ने कई क्षेत्रों को बेहद संवेदनशील और अस्थिर बना दिया है।यही कारण है कि आज विभिन्न देश आधुनिक और महंगे हथियार खरीदने में बड़ी रकम लगा रहे हैं। इससे हथियार बनाने वाली कंपनियों का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन दुनिया के लिए खतरे भी बढ़ रहे हैं।समस्या यह है कि जितने ज्यादा हथियार जुटाए जाते हैं, उतनी ही ज्यादा टकराव या युद्ध की आशंका पैदा होती है। साथ ही सरकारों का पैसा रक्षा खरीद में खर्च होने लगता है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक विकास जैसे जरूरी क्षेत्रों पर कम ध्यान जाता है। यानी सुरक्षा के नाम पर खर्च तो बढ़ता है, लेकिन असुरक्षा भी कम नहीं होती। रिपोर्ट हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हथियारों पर बढ़ती निर्भरता वास्तव में शांति लाएगी या दुनिया को और ज्यादा तनाव और खतरे की ओर धकेल देगी। हाल फिलहाल यदि हम यहां सरल शब्दों में कहें तो

दुनिया की सबसे बड़ी 100 हथियार बनाने वाली कंपनियों ने पिछले साल से लगभग 6% ज्यादा पैसा कमाया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हाल के समय में कई जगह लड़ाइयाँ और तनाव लगातार बढ़े हैं, जैसे यूक्रेन युद्ध और गाजा संघर्ष। जब कहीं युद्ध होता है या किसी देश को खतरा महसूस होता है, तो वे अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए ज्यादा हथियार खरीदते हैं। इसी वजह से हथियारों की मांग तेजी से बढ़ गई और कंपनियों की बिक्री भी बढ़ी।सीधे शब्दों में कहें तो जितना ज्यादा तनाव और युद्ध, उतनी ही ज्यादा हथियारों की खरीद, और उतनी ही ज्यादा कंपनियों की कमाई। पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि सिपरी की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि दुनिया की 100 सबसे बड़ी रक्षा कंपनियों ने 2024 में कुल 679 अरब डॉलर कमाए, जो यह दिखाता है कि वैश्विक स्तर पर युद्ध और तनाव अब एक भारी-भरकम कारोबार बन चुके हैं। यूक्रेन, गाजा और पूर्वी एशिया में बढ़ते संघर्षों ने हथियारों की मांग को तेजी से बढ़ाया है, जिसके चलते युद्धों का व्यावसायीकरण और कॉरपोरेट कंपनियों की भूमिका और मजबूत हो रही है। रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि पश्चिम एशिया अब एक नया हथियार उत्पादक क्षेत्र बनकर उभर रहा है, जिससे वैश्विक सैन्य उत्पादन में विविधता आई है। भारत की तीन कंपनियाँ क्रमशः हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स भी इस सूची में शामिल हैं, और घरेलू मांग के कारण इनकी संयुक्त आयुध कमाई 8.2% बढ़कर 7.5 अरब डॉलर हो गई है। सिपरी का आकलन बताता है कि भविष्य में हथियारों की बिक्री और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय तनाव कम होने के बजाय बढ़ रहा है, और देश ड्रोन व अत्याधुनिक रक्षा तकनीकों पर भारी निवेश कर रहे हैं। यह बढ़ती सैन्य होड़ न केवल शांति के लिए खतरा है, बल्कि विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संसाधन हटाकर वैश्विक असमानताओं, भुखमरी, जलवायु संकट और अस्थिरता को भी बढ़ावा दे रही है। युद्धों और संघर्षों के कारण लाखों लोग विस्थापन, अकाल और मानवीय त्रासदियों का सामना कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आज युद्धों और संघर्षों के कारण दुनिया भर में लाखों लोग अपने घर, जमीन और रोज़गार से बेदखल हो रहे हैं। इससे बड़े पैमाने पर विस्थापन, भूख और मानवीय संकट पैदा हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, रूस-यूक्रेन युद्ध ने यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा शरणार्थी संकट खड़ा कर दिया, जहाँ करोड़ों लोग अपने घर छोड़कर पड़ोसी देशों में शरण लेने को मजबूर हुए। गौरतलब है कि रूस यूक्रेन युद्ध, जो फरवरी 2022 में शुरू हुआ, अब तक मानवीय और आर्थिक दोनों रूपों में भारी नुकसान पहुँचा चुका है। इस युद्ध से यूक्रेन को लगभग 1 खरब डॉलर का कुल आर्थिक नुकसान हुआ है, जिसमें आवास, परिवहन, ऊर्जा, उद्योग और अन्य बुनियादी ढांचे का विनाश शामिल है। कितनी बड़ी बात है कि अकेले आवासीय भवनों के रूप में लगभग 2.36 लाख घर नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए हैं। युद्ध के कारण यूक्रेन के लगभग 10.6 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं, जिनमें से 3.7 मिलियन अपने देश के भीतर और 6.9 मिलियन लोग विदेशों में शरणार्थी बने हैं। इसके साथ ही, देश की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) लगभग 22.6% तक घट गई, बजट घाटा बढ़कर जीडीपी का 20.4% हो गया, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर असर पड़ा। वास्तव में, युद्ध का नुकसान केवल कुछ ही चीज़ों में मापा जा सका है, जैसे बुनियादी आर्थिक नुकसान। लेकिन युद्ध के कारण लोगों की मानसिक पीड़ा, समाज में अस्थिरता और जीवन की गुणवत्ता पर असर अब भी बहुत बड़ा है। भविष्य में युद्ध प्रभावित इलाकों को फिर से ठीक करने और लोगों की मदद करने के लिए लगभग 524 अरब डॉलर की जरूरत होगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि युद्ध का असर सिर्फ अभी नहीं, बल्कि आने वाले कई सालों तक आर्थिक और सामाजिक तौर पर महसूस किया जाएगा। उसी तरह, गाजा में जारी संघर्ष ने स्वास्थ्य सेवाओं, भोजन, पानी और आश्रय सभी को लगभग समाप्त कर दिया, जिससे बच्चों और महिलाओं पर सबसे ज्यादा असर पड़ा। गाज़ा में हाल के संघर्षों ने भारी तबाही मचाई है। अब तक लगभग 70,000 लोग मारे जा चुके हैं और लगभग 1.9मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं। करीब 62% घर और बुनियादी ढांचा नष्ट या क्षतिग्रस्त हो चुका है। स्कूल, अस्पताल, पानी और स्वास्थ्य सेवाएँ बाधित हैं, जिससे मानवीय संकट गहरा गया है। आर्थिक नुकसान और पुनर्निर्माण की आवश्यकता लगभग 53बिलियन डॉलर आंकी गई है। बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों पर सबसे अधिक असर पड़ा है, और संकट के मानसिक और सामाजिक प्रभाव अभी भी व्यापक हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सूडान के गृहयुद्ध में भी लाखों लोग भूख और हिंसा से बचने के लिए रेगिस्तानों और सरहदी इलाकों में भटक रहे हैं। इन उदाहरणों से साफ है कि संघर्ष सिर्फ गोलियों और बमों तक सीमित नहीं होते, अपितु वे समाज की पूरी संरचना तोड़ देते हैं और मानवता को गहरी पीड़ा और असुरक्षा में धकेल देते हैं।इसलिए रिपोर्ट यह संकेत देती है कि विश्व समुदाय को हथियारों की इस अंधाधुंध दौड़ को रोकने के लिए गंभीर प्रयास करने होंगे, ताकि मानवता को बड़े संकट से बचाया जा सके।

सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कालमिस्ट

केंद्रीय-सूबाई सत्ता में सनातनी संस्कार-व्यवहार प्रतिरोपित करने के लिए मोदी सरकार का आभारी रहेगा देश-देशवासी

कमलेश पांडेय

केंद्र में विगत तीन आम-चुनावों से सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी सरकार ने अब तक जो कई महत्वपूर्ण सरकारी परिसरों और संस्थानों के नाम बदले दिए हैं, उनका एकमात्र मकसद प्रशासनिक और सांस्कृतिक सोच-समझ में बदलाव लाना है। साथ ही उन सभी को और अधिक जनहितैषी बनाना है। चूंकि शब्दों के मंत्रमय असर और व्यवहार से हम भारतीय वाकिफ हैं, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले की सर्वत्र सराहना हो रही है। खासकर आरएसएस-भाजपा के लोग तो इसे सांस्कृतिक सपनों के सच होने जैसा मान रहे हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि केंद्रीय-सूबाई सत्ता में सनातनी संस्कार-व्यवहार प्रतिरोपित करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार का देश-देशवासी सदैव आभारी रहेगा।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, अब तक हुआ प्रमुख नाम परिवर्तन इस प्रकार हैं:- पहला, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) का नाम बदलकर अब "सेवा तीर्थ" कर दिया गया है। इसमें पीएमओ के साथ-साथ मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और इंडिया हाउस शामिल हैं। यह बदलाव सत्ता से सेवा की ओर शासन की प्राथमिकताओं को दर्शाता है।

दूसरा, देश के सभी राजभवनों के नाम बदलकर "लोकभवन" कर दिए गए हैं। इसके पीछे औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति का मकसद बताया गया है। इसके साथ ही उपराज्यपालों के कार्यालय को "लोक निवास" कहा जाएगा।

तीसरा, केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर "कर्तव्य भवन" किया गया है जो शासन की जिम्मेदारी और कर्तव्य केंद्रित सोच को दर्शाता है।

इसके अलावा, पहले भी "राजपथ" का नाम बदलकर "कर्तव्य पथ" और प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पथ, सेवन रेसकोर्स रोड का नाम बदलकर "लोक कल्याण मार्ग" रखा गया। यह सारे नाम परिवर्तन प्रशासनिक ढांचे में सेवा और उत्तरदायित्व की भावना को प्रमुखता देने के लिए किए गए हैं, न कि केवल संरचनात्मक सुधार के रूप में।

इसी कड़ी में सबसे बड़ा बदलाव तो यह है कि अब रिपब्लिक ऑफ इंडिया को रिपब्लिक ऑफ भारत/भारत गणतंत्र कहा व लिखा जाने लगे। स्पष्ट है कि शहरों का नाम बदलने की जो शुरुआत मुगलकाल में शुरू हुई थी, और ब्रिटिश काल में भी जारी रही, उस विदेशी संस्कृति को बढ़ावा देने वाली सोच की देशी काट और कर्तव्यनिष्ठ पालन अब दिखाई दे रहा है जो सराहनीय है। इससे भारत माता के अरमान पूरे होने के आसार बढ़े हैं।

दरअसल, आरएसएस पृष्ठभूमि से आने वाले कौशांबी पार्षद मनोज गोयल का कहना है कि इन अहम बदलावों के पीछे सरकारी तर्क और उद्देश्य यह है कि सेवातीर्थ, लोकभवन, कर्तव्य भवन, लोककल्याण मार्ग, कर्तव्य पथ जैसे नाम से पुराने नाम बदले जाएं ताकि वे शासन और प्रशासन की औपनिवेशिक और शाही छवि से दूर होकर लोकतंत्र और सेवा की भावना को प्रतिबिंबित करें।

यही वजह है कि लोकभवन नाम राजभवन के स्थान पर अपनाया गया है क्योंकि राजभवन के "राज" शब्द में शासन या राज करने की औपनिवेशिक मानसिकता झलकती है। वहीं, लोकभवन का अर्थ "जनता का भवन" है जो यह संदेश देता है कि अब सत्ता राजा या गवर्नर के लिए नहीं बल्कि पूरी जनता के लिए है। यह नाम यह दर्शाता है कि ये इमारतें जनता के और ज्यादा करीब आएंगी और प्रशासन जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध होगा।

वहीं, वैश्विक कूटनीति की धुरी बन चुके प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) का नया नाम "सेवातीर्थ" रखा गया है जिसका अर्थ है "सेवा का पवित्र स्थान"। यह नाम इस बात को दर्शाता है कि यह स्थान सत्ता के प्रदर्शन का नहीं, बल्कि भारत समेत दुनिया की जनसेवा और समर्पण का प्रतीक होगा। वहीं, केंद्रीय सचिवालय को "कर्तव्य भवन" नाम दिया गया है ताकि यह दिखाया जा सके कि सरकारी पद और प्रशासनिक काम जनता की सेवा का कर्तव्य है, न कि सम्मान या सत्ता का साधन।

समझा जाता है कि इसके पीछे सरकार का उद्देश्य नामों के माध्यम से सोच और दृष्टिकोण में बदलाव लाना है, जहां शक्ति और सत्ता से अधिक जिम्मेदारी और सेवा की प्राथमिकता हो। यह बदलाव प्रशासन को लोगों के ज्यादा करीब लाने और लोकतंत्र की भावना को मजबूती देने के लिए भी किया गया है। साथ ही, वेबसाइट, सरकारी दस्तावेजों, साइनबोर्ड आदि में भी ये नए नाम लागू किए जाएंगे ताकि संदेश व्यापक रूप से पहुंच सके।

बहरहाल, इन नए नामों का कानूनी और प्रशासनिक प्रभाव यह होगा कि इन नामों को आधिकारिक रूप से मान्यता देने के लिए सरकारी गजट में प्रकाशन जरूरी होगा। जहां तक इनके कानूनी प्रभाव की बात है तो इन नामों में यह बदलाव तब तक पूर्ण और वैध नहीं माना जाएगा जब तक इसे भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया जाता। ऐसा इसलिए कि गजट नोटिफिकेशन एक वैधानिक दस्तावेज होता है, जो नाम परिवर्तन को सभी सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों के लिए बाध्यकारी बनाता है। इससे सरकारी दस्तावेज़, आदेश, और डिजिटल रजिस्टर में नए नामों का उपयोग शुरू होगा और पुरानी नामावली समाप्त मानी जाएगी।

जहां तक इन नामों के प्रशासनिक प्रभाव की बात है तो इन नए नामों के अनुसार सभी संबंधित सरकारी फॉर्म, वेबसाइट, नोटिस बोर्ड, और प्रशासनिक दस्तावेजों को अपडेट करना होगा। इससे प्रशासन में एक नई सेवा और कर्तव्य की भावना को बढ़ावा मिलेगा। कर्मचारी और अधिकारी नए नामों के अनुरूप अपनी पदस्थापना और कार्यप्रणाली को धयान में रखेंगे।

जहां तक इन नामों के सार्वजनिक और संवैधानिक पहचान की बात है तो ये नाम बदलाव शासन को अधिक लोकतांत्रिक और सेवा-केंद्रित बनाते हैं। इससे नियम और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और नागरिकों के साथ सरकारी संस्थाओं का रिश्ता मजबूत होगा। इस प्रकार, नामों के आधिकारिक और कानूनी रूप से बदले जाने के बाद प्रशासनिक-प्रक्रियाओं में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे और सभी सरकारी संस्थान इन नए नामों को प्राथमिकता से अपनाएंगे। यह बदलाव शासन व्यवस्था के दृष्टिकोण में एक प्रतीकात्मक और वास्तविक परिवर्तन होगा जिसका प्रभाव रोजमर्रा के सरकारी संचालन और नीति निर्माण पर भी पड़ेगा।

चूंकि शब्दों का प्रभाव हमारे सोचने और अनुभव करने के तरीके को भी बदल देता है। इसलिए इन बदलावों को ऐतिहासिक कदम कहना ज्यादा तर्कसंगत होगा।क्योंकि सकारात्मक शब्द हमारी सोच को सकारात्मक दिशा देते हैं और जीवन में सफलता और खुशहाली लाने में मदद करते हैं। इसलिए शब्दों का संयोजन बुद्धिमत्ता और विवेक से करना चाहिए, क्योंकि वे मनोस्थिति, आत्मविश्वास और भविष्य को आकार देने में सक्षम होते हैं। मोदी प्रशासन ने यही किया है, जिसके लिए वह बधाई की पात्र है।

मदनी ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों की सबसे बड़ी समस्या बता दी

राजेश कुमार पासी

मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी समस्या कट्टरवाद है, क्योंकि कट्टरवाद से ही आतंकवाद पैदा होता है। मुस्लिम बुद्धिजीवी आतंकवाद के लिए मुस्लिमों के उत्पीड़न को जिम्मेदार ठहराते हैं लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है कि उत्पीड़न किस समुदाय का नहीं हो रहा है। हर समुदाय कहीं न कहीं उत्पीड़न का शिकार हो रहा है, लेकिन आतंकवादी बनने का एकाधिकार सिर्फ मुस्लिम समाज को कैसे हासिल हो गया है। हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता लेकिन हर आतंकवादी मुस्लिम होता है, इस सच से इंकार नहीं किया जा सकता। अगर दूसरे समुदाय का कोई व्यक्ति आतंकवादी बनता है तो उसके पीछे भी इस्लामिक कट्टरवाद की सोच होती है।

मुस्लिम कट्टरवाद और आतंकवाद के कारण मुस्लिम समाज में सामाजिक सुधार नहीं हो पाया है। मुस्लिम बुद्धिजीवी सामाजिक सुधार के पक्ष में नहीं हैं बल्कि उन्होंने सामाजिक बुराइओं को धार्मिक छतरी प्रदान कर दी है। हर सामाजिक बुराई को धर्म के साथ जोड़ दिया गया है। देश के बड़े मुस्लिम संगठन जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने शनिवार को एक बड़ा भड़काऊ भाषण दिया है जो देश का माहौल बिगाड़ने वाला है। वो जानते हैं कि उन्होंने क्या बोला है, इसलिए सरकार को गिरफ्तार करने की चुनौती दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि सरकार उन्हें जेल भेजे ताकि मुस्लिम उत्पीड़न का उनका विमर्श सही साबित हो जाए। उन्होंने इस्लाम को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया है और कहा है कि सरकारें धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट पर भी उन्होंने गंभीर सवाल उठा दिए हैं। जिहाद को पवित्र इस्लामी अवधारणा बताया और कहा कि जिहाद का अर्थ जुल्म के खिलाफ लड़ना है। उनका कहना है कि जब-जब जुल्म होगा, जिहाद होगा।

मदनी का कहना है कि इस्लाम और मुस्लिमों के खिलाफ घृणा फैलाने की कोशिशें बढ़ गई हैं। जिहाद को आतंक और हिंसा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लव जिहाद, थूक जिहाद और लैंड जिहाद जैसे शब्दों से मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बाबरी मस्जिद और तीन तलाक जैसे फैसलों को लेकर उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका सरकार के दबाव में काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट तभी सुप्रीम कहला सकता है जब वो संविधान का पालन करे और कानून बनाये रखे। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुसार फैसले दे रहा है या नहीं, इसका फैसला मदनी कैसे कर सकते हैं।

मदनी कहते हैं कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को मजबूर करके बहुसंख्यक समुदाय में शामिल किया जा रहा है। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है, ये कहां हो रहा है और कब हुआ है, ये भी उन्हें बताना चाहिए था। वास्तव में देखा जाए तो भारत में इसके विपरीत काम हो रहा है। बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को लालच और धोखे से मुस्लिम समाज में धर्मांतरित किया जा रहा है। अगर मदनी को अपनी बात सही लगती है तो उन्हें धर्मपरिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने के लिए मोदी सरकार से मांग करनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि मुस्लिम संगठन कई राज्यों में बनाए गए धर्मपरिवर्तन विरोधी कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हलाल को बदनाम किया जा रहा है. हलाल का मतलब ईमानदारी की कमाई है, किसी को धोखा नहीं देना है। इस पर किसने एतराज किया है जबकि समस्या हर उत्पाद को हलाल बनाने से है।

मदनी को बताना चाहिए कि लिपस्टिक, माचिस, साबुन, तेल, जैसी घरेलु उपयोग की वस्तुओं में हलाल का क्या मतलब है। किस आधार पर इनका प्रमाणीकरण किया जाता है। वास्तव में मुस्लिम समाज हलाल के नाम पर एक समांतर अर्थव्यवस्था खड़ी कर रहा है। हलाल प्रमाणीकरण के लिए कोई सरकारी संस्था नहीं है, एक गैर-सरकारी संगठन हलाल के नाम पर उगाही करके पैसों का कैसे इस्तेमाल कर रहा है, कोई नहीं जानता। उनका कहना है कि वक्फ हमारे बुजुर्गों की विरासत है। उनकी बात सही हो सकती है लेकिन विरासत के दस्तावेज दिखाने से डर क्यों लगता है। सम्पत्ति को वक्फ किया गया है या नहीं, ये नहीं बता सकते तो संपत्ति के कागजात तो दिखाए जा सकते हैं। अगर कागजात नहीं है तो कैसे माना जाए कि सम्पत्ति वक्फ की गई है। वो कहते हैं कि सरकारें वक्फ की बर्बादी का तमाशा देख रही थी। उन्हें बताना चाहिए कि वक्फ को किसने बर्बाद किया. इसका नियंत्रण तो मुस्लिमों के हाथ में है, तो हिन्दू तो इसकी बर्बादी के पीछे नहीं हो सकते। उन्होंने आरोप तो लगा दिया लेकिन ये नहीं बताया कि आरोपी कौन है। पूजा स्थल कानून के बारे में कहते हैं कि उस कानून के होते हुए मथुरा और ज्ञानवापी मस्जिद के मुकदमे कैसे चल रहे हैं। वो यह नहीं कहते कि ये विवादित स्थल क्यों है, उन्हें मस्जिद क्यों कहा जा रहा है जबकि देखने भर से पता चलता है कि ये मंदिरों पर खड़े किए गए ढांचे हैं। अगर मदनी और मुस्लिम समाज मानता है कि विवादित स्थल मस्जिद हैं तो उसकी जांच से क्यों भागते हैं।

ऑल इंडिया इमाम ऑर्गनाइजेशन के प्रमुख अहमद इलियासी ने महमूद मदनी के बयान की निंदा की है।उनका कहना है कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट पर मुसलमानों को भरोसा नहीं है, यह कहना गलत है। इससे देश का माहौल खराब होता है। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया है। ये देश के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि भारत का मुसलमान उनकी बातों से सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि पहले उनके चाचा ने भी अभी ऐसा ही विवादास्पद बयान दिया था जिससे देश का माहौल खराब होता है। उनका कहना है कि देश विरोधी ताकतें देश का माहौल खराब करना चाहती हैं. ऐसे समय में ऐसा बयान देने से बचना चाहिए। जब देश के खिलाफ साजिशें की जा रही हो तो माहौल खराब करने से बचना चाहिए।

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी कहते हैं कि मदनी का बयान समाज को बांटने, देश को भ्रमित करने और मुसलमानों को भड़काने वाला है। देश के मुसलमान अदालतों और संसद पर पूरा भरोसा करते हैं। देश में शांति है परंतु मदनी मुसलमानों को उकसा रहे हैं। इन मुस्लिम धर्म गुरूओं की बात की जाए तो यह सच है कि मदनी देश के मुसलमानों को भड़का रहे हैं। उनका यह कहना कि जब-जब जुल्म होगा, जिहाद होगा, एक तरह से देश को धमकी देना है और कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा देने की कोशिश है। कितने ही आतंकी संगठन ऐसे हैं जो जिहाद को अपने नाम में इस्तेमाल करते हैं। ये लोग बिना किसी शर्म-संकोच के अपनी आतंकवादी गतिविधियों को जिहाद का नाम देते हैं। वो जिहाद को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगा रहे हैं जबकि सच यह है कि किसी शब्द का क्या मतलब है, यह उसके इस्तेमाल से पता चलता है। जब जिहाद का इस्तेमाल आतंकी घटनाओं और हिंसा के लिए किया जाता है तो बदनाम करने का आरोप किस पर लगाया जाए। कुछ लोग बंदूक से आतंकवाद के साथ हैं तो कुछ लोग बुद्धिजीवी बनकर उसका समर्थन करते हैं। ये लोग अपनी वाणी और कलम का इस्तेमाल आतंकवाद के बचाव और उसके समर्थन में करते हैं। संविधान की बात करके उसका इस्तेमाल देश पर हमला करने के लिए करने में इन्हें महारत हासिल है। शरीयत को लागू करने की दिल में तमन्ना लिए ये लोग संविधान के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं। ये लोग शरीयत चाहते हैं लेकिन आंशिक रूप से चाहते हैं। आपराधिक मामलों में ये लोग शरीयत नहीं चाहते लेकिन सामाजिक और धार्मिक मामलों में शरीयत चाहिए।

ये लोग मुस्लिम समाज को पीड़ति साबित करने की कोशिश करते हैं तो दूसरी तरफ आतंकी भी यही कहते हैं कि वो अपने धर्म को बचाने के लिए जान दे रहे हैं। जुल्म के खिलाफ ही कट्टरपंथी युवा आत्मघाती हमलावर बनते हैं। कहीं न कहीं इस विमर्श से आतंकवाद फैलता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और सरकार को मुस्लिम विरोधी सिद्ध करने की कोशिश की है। राममंदिर और तीन तलाक जैसे फैसले को मुस्लिम विरोधी माना है। मदनी कहते हैं कि उनकी बस्ती में उनसे पूछा जा रहा है कि तुम कौन हो। इसमें अब क्या दिक्कत है. कई तरह के दस्तावेज इसलिए तो जारी किए जाते हैं ताकि व्यक्ति की पहचान हो सके। किसी की पहचान उसके घर आकर ही पूछी जाती है, सड़क पर नहीं पूछा जाता। किसी योजना या सरकारी काम के लिए भी पहचान पूछी जा सकती है और उसके लिए दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। इससे हिंदुओं को कोई परेशानी नहीं है तो मुस्लिमों को परेशानी क्यों है।

उनका कहना है कि मायूसी कौम के लिए जहर है. जिंदा कौम मायूस नहीं होती हैं। देखा जाए तो यह पूरी कौम को भड़काने की कोशिश है। न्यायपालिका पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाकर उन्होंने पूरी न्यायपालिका को नीचा दिखाने की कोशिश की है। इससे मुस्लिम समाज को संदेश जाता है कि अदालतें सरकारी दबाव में उनके खिलाफ फैसले दे रही हैं। इसका दूसरा मतलब यही है कि जब अदालतें मुस्लिमों के पक्ष में फैसला दें तो उन्हें स्वतंत्र माना जा सकता है। मदनी जैसे लोग नफरत को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यही लोग कट्टरपंथियों और आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। वास्तव में मुस्लिम बुद्धिजीवियों की बड़ी समस्या यही है कि वो कट्टरवाद का समर्थन करते हैं। ये लोग हिन्दुओं से उम्मीद करते हैं कि वो उदारवादी बने रहें लेकिन मुस्लिमों को कट्टरवादी बनाने की पूरी कोशिश करते हैं।

प्रदूषण की मार सांसों पर आफत

● डॉ विजय गर्ग

प्रदूषण की वजह से व्यक्ति के फेफड़े प्रभावित हैं या नहीं, यह तय करने के लिए सबसे पहले तो सांस लेने में दिक्कत की पहचान खुद के स्तर पर करनी पड़ती है। अगर असहजता होती है, तब चिकित्सक के पास जाकर जांच कराना सबसे प्राथमिक काम होना चाहिए। आमतौर पर फेफड़ों के प्रभावित होने के बारे में स्पष्टता के लिए चिकित्सक पल्मोनरी फंक्शन जांच करते हैं।

यह मौसम ठंड की शुरुआत है, लेकिन इस दौरान पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह की समस्या खड़ी हो रही है, वह अब एक राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुकी है। यह समस्या है- प्रदूषण। हालत यह है कि ज्यादातर लोगों के सामने सुरक्षित सांस लेना भी एक चुनौती बन जाती है और रोज वे सांसों की समस्या से दो-चार होते हैं। दरअसल, इस मौसम में हवा के घनीभूत होने की वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है और वायु में मौजूद प्रदूषक तत्त्वों के कारण श्वास नली में सिकुड़न आ जाती है। इसके बाद व्यक्ति खांसी, घरघराहट और सांस लेने में तकलीफ के दौर से गुजरने लगता है।

कई बार तो समय पर समस्या के कारण की पहचान नहीं हो पाने की वजह से यह परेशानी जटिल हो जाती है।

पहचान का वक्त

प्रदूषण की वजह से व्यक्ति के फेफड़े प्रभावित हैं या नहीं, यह तय करने के लिए सबसे पहले तो सांस लेने में दिक्कत की पहचान खुद के स्तर पर करनी पड़ती है। अगर असहजता होती है, तब चिकित्सक के पास जाकर जांच कराना सबसे प्राथमिक काम होना चाहिए। आमतौर पर फेफड़ों के प्रभावित होने के बारे में स्पष्टता के लिए चिकित्सक पल्मोनरी फंक्शन जांच करते हैं। इससे पता चल पाता है कि फेफड़ों में दिक्कत की वजह से सांस लेने की प्रक्रिया बाधित हो रही है या नहीं। इसके बाद ही लक्षणों के उपचार की प्रक्रिया शुरू की जाती है।

हवा की मुश्किल

यह एक आम हकीकत है कि आज वायु प्रदूषण कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का जनक हो चुका है। सबसे ज्यादा यह फेफड़ों के सामान्य तरीके से काम करने की स्थितियों को प्रभावित कर सकता है। इसमें खासतौर पर अस्थमा से पहले से परेशान लोगों के सामने दिक्कत ज्यादा जटिल हो जा सकती है, क्योंकि प्रदूषण का स्तर अस्थमा और सीओपीडी को बढ़ा सकता है और श्वसन तंत्र के संक्रमण और फेफड़ों की समस्या को और जटिल कर सकता है। कई बार चिकित्सक कैंसर तक की आशंका जाते हैं। वायु प्रदूषण से दिल के दौरे का खतरा भी बढ़ता है, इससे कोरोनरी धमनी रोग और आघात होता है। वाहनों की ज्यादा आवाजाही वाले इलाकों में रहने वाले लोगों में वायु प्रदूषण संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम ज्यादा होता है। वायु प्रदूषण के संपर्क में ज्यादा वक्त रहने से सांस लेने में परेशानी, छाती में दर्द और श्वसन तंत्र की अतिसंवेदनशीलता देखी जा सकती है। जो बच्चे ओजोन प्रदूषण वाले दिनों में बाहरी गतिविधियों में ज्यादा हिस्सा लेते हैं, उन्हें अस्थमा होने की आशंका ज्यादा होती है।

कारणों का दायरा

घर के अंदर वायु प्रदूषण में बाहरी वायु प्रदूषण का बड़ा योगदान है। इसके अलावा, घर के अंदर वायु प्रदूषण के स्रोतों में तंबाकू का धुआं, घर के अंदर खाना पकाना (गैस स्टोव सहित), निर्माण कार्य भी शामिल हैं। खाना पकाने और गर्म करने के लिए बायोमास ईंधन, यानी लकड़ी, अपशिष्ट या पराली आदि जलाना प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है, जो सांस की समस्याएं पैदा करता है। उपचार की राह जोखिम को कम करने पर जोर देने के अलावा, लक्षणों से राहत के लिए उपचार के क्रम में अस्थमा के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयां (जैसे ब्रोंकोडाइलेटर्स, जो वायुमार्ग को खोलती हैं) कुछ राहत दे सकती हैं। इससे श्वास नली खुल सकती है और राहत मिलती है। जोखिम को कम करने के लिए बाहरी वायु प्रदूषकों के संपर्क को रोकना या कम करना जरूरी है। खास कर हृदय या फेफड़ों के विकारों से पीड़ित लोग प्रदूषण के दिनों में बाहरी गतिविधियों को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हवा की गुणवत्ता खराब हो, तो बाहरी व्यायाम को कम करना चाहिए और घर के अंदर रहना चाहिए। धूम्रपान और खाना पकाने जैसे स्रोतों के संपर्क को कम करना भी जरूरी है। (यह लेख सिर्फ सामान्य जानकारी और जागरूकता के लिए है। उपचार या स्वास्थ्य संबंधी सलाह के लिए विशेषज्ञ की मदद लें।)

वेडिंग सीज़न शहनाइयों की गूंज, बाजार की रौनक.......

डॉ विजय गर्ग

देश में वेडिंग सीज़न का आगाज़ हो चुका है। देवउठनी एकादशी से शुरू हुआ यह उत्सव 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान भारत में करीब 46 लाख शादियां होंगी जिनमें लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपये का व्यापार होगा। इस खर्च का बड़ा हिस्सा खानपान, कैटरिंग व ज्वैलरी खरीद में जाता है, साथ ही छोटे व्यवसायियों व मेहनतकश लोगों तक पहुंचता है। शहनाइयों के साथ तकनीकी का भी बोलबाला है। दरअसल भारतीय शादियां सिर्फ दो रूहों का मिलन नहीं, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सालाना 'बूस्टर डोज़' है।

नवंबर की हल्की सर्द शामें, हवा में घुलती धुंध और दूर कहीं से आती ब्रास बैंड की तेज़ आवाज़। अगर आप भारत के किसी भी शहर, कस्बे या गांव में रहते हैं, तो पिछले कुछ दिनों में आपने महसूस किया होगा कि हवा का रुख बदल गया है। सड़कें जाम हैं, बाज़ारों में पैर रखने की जगह नहीं, और रात के सन्नाटे में डीजे का शोर अक्सर नींद में खलल डाल रहा है। पहली नज़र में यह सब अराजक लग सकता है। ट्रैफिक में फंसा एक आम आदमी इसे 'परेशानी' का नाम दे सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा गौर से उस शोर को सुनें, तो उसमें एक उम्मीद की धुन सुनाई देगी। यह धुन है-भारतीय अर्थव्यवस्था के पहियों के घूमने की।

भारत में 'द ग्रेट इंडियन वेडिंग सीज़न' का आगाज़ हो चुका है। देवउठनी एकादशी के साथ ही शुरू हुआ यह उत्सव 15 दिसंबर तक पूरी रफ़्तार पर रहेगा। लेकिन इस साल यह शोर थोड़ा अलग है, थोड़ा ज़्यादा है। यह सिर्फ दो दिलों या दो परिवारों का मिलन नहीं रह गया ; यह मंदी की आहटों के बीच भारतीय बाज़ार का सबसे बड़ा 'सेलिब्रेशन' बन गया है। तो आज दूल्हे की शेरवानी के रंग या दुल्हन के गहनों की चमक पर बात नहीं करेंगे, बल्कि उस अर्थशास्त्र, उस तकनीक और उस बदलते सामाजिक ताने-बाने की पड़ताल करेंगे जो इन शामियानों के पीछे छिपा है।

जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं सहमी हुई हैं, बड़े-बड़े देश 'रिसेशन' शब्द से कांप रहे हैं, तब भारत अपनी मस्ती में झूम रहा है। 'कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स' (कैट) ने हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की है, वह किसी भी अर्थशास्त्री को सोचने पर मजबूर कर दे। एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक नवंबर से 15 दिसंबर के बीच भारत में करीब 46 लाख शादियां होने का अनुमान है। अगर हम इसे पिछले साल के आंकड़ों से तुलना करें, तो यह एक बड़ी छलांग है। लेकिन असली कहानी इन शादियों की संख्या में नहीं, बल्कि उन पर होने वाले खर्च में है। अनुमान है कि इन 46 लाख शादियों में करीब 6.5 लाख करोड़ रुपये का व्यापार होगा।

ज़रा इस आंकड़े को गहराई से समझें। यह रकम दुनिया के कई छोटे देशों की कुल जीडीपी से भी ज़्यादा है। इतनी बड़ी कि भारत के कई मंत्रालयों के सालाना बजट को भी पीछे छोड़ देती है। यह प्रमाण है कि भारतीय समाज में 'उपभोग' की भूख अभी शांत नहीं हुई। महंगाई और मंदी की तमाम खबरों के बीच, भारतीय परिवार अपनी परंपराओं और खुशियों पर खर्च करने में कोई कोताही नहीं बरत रहे। अक्सर जब हम 'बिग फैट इंडियन वेडिंग' की बात करते हैं, तो हमारी आंखों के सामने फाइव-स्टार होटल्स, विदेशी फूल और महंगी गाड़ियां आती हैं। लगता है कि यह पैसा अमीरों की जेब से निकलकर अमीरों की जेब में ही जा रहा है। लेकिन हकीकत इससे अलग और सुखद है।

शादियों का यह अर्थशास्त्र असल में धन के वितरण का बेहतरीन उदाहरण है। जब एक मध्यमवर्गीय पिता अपनी बेटी की शादी के लिए बैंक से अपनी जीवनभर की जमापूंजी निकालता है, तो वह पैसा समाज की नसों में दौड़ने लगता है। कैट का डेटा बताता है, कुल खर्च का एक बड़ा हिस्सा, करीब 10 प्रतिशत, खानपान और कैटरिंग पर व्यय होता है। करीब 15 प्रतिशत हिस्सा ज्वैलरी की खरीद में जाता है। लेकिन जरा ध्यान दीजिये उन 'अदृश्य हाथों' की तरफ जो इस उत्सव को संभव बनाते हैं। ज़रा उस टेंट लगाने वाले मज़दूर के बारे में सोचिए जो बांस और रस्सियों के सहारे शामियाना खड़ा करता है। उस बिजली वाले के बारे सोचिए जो झालरें लगाता है। उस फूल वाले के बारे में, उस नाई, उस धोबी, उस रिक्शा चालक, और स्थानीय पंडित जी के बारे में सोचिए। एक औसत शादी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 50 से 100 लोगों को रोज़गार देती है। ये वो 'असंगठित क्षेत्र' है, जिसकी कमाई का कोई फिक्स्ड ज़रिया नहीं होता। उनके लिए यह वेडिंग सीज़न किसी दिवाली से कम नहीं है। इन 46 लाख शादियों का मतलब है करोड़ों 'मानव-दिवस' रोज़गार। यह पैसा जब इन मेहनतकश लोगों की जेब में पहुंचता है, तो वे राशन खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, और अर्थव्यवस्था का चक्र घूमता रहता है।

अगर आप पिछले एक दशक में किसी शादी में नहीं गए हैं और अब अचानक किसी समारोह में पहुंच जाएं, तो शायद आप चौंक जाएंगे। भारतीय शादियां अब वैसी नहीं रहीं, जैसी 90 के दशक में हुआ करती थीं। अब यहां रस्मों के साथ-साथ 'टेक्नोलॉजी' का भी बोलबाला है। वेडिंग इंडस्ट्री ने तकनीकी बदलाव को बांहें फैलाकर स्वीकार किया है।

एआई और डिजिटल कुंडली : बात अब सिर्फ पंडित जी की पोथी तक सीमित नहीं है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल मैच-मेकिंग से लेकर गेस्ट लिस्ट मैनेज करने तक में हो रहा है। कौन सा मेहमान क्या खाना पसंद करेगा, किसे कहां बैठाना है- सब ऐप्स के ज़रिए तय हो रहा है।

ड्रोन और सिनेमैटोग्राफी : पहले शादी की एल्बम एक दस्तावेज़ होती थी, अब शादी की फिल्म एक 'ब्लॉकबस्टर' होती है। ड्रोन अब स्टेटस सिंबल नहीं, बल्कि ज़रूरत हैं। प्री-वेडिंग शूट्स का बाज़ार इतना बड़ा कि इसने पर्यटन स्थलों पर फोटोग्राफर्स और मेकअप आर्टिस्ट्स के लिए एक नई इंडस्ट्री खड़ी कर दी।

सोशल मीडिया का 'दबाव' और 'बाज़ार': आज की पीढ़ी के लिए, अगर शादी इंस्टाग्राम पर अच्छी नहीं दिखी, तो क्या वो शादी हुई भी? 'इंस्टा-वर्दी' पलों को बनाने के लिए डेकोरेशन पर लाखों खर्च किए जा रहे हैं। एक नई तरह की इकोनॉमी खड़ी हो गई -इंफ्लुएंसर इकोनॉमी। लोग शादियों में 'कंटेंट क्रिएटर्स' को बुला रहे हैं ताकि उनकी रील वायरल हो सके। यह मनोवैज्ञानिक बदलाव नये उत्पादों और सेवाओं की मांग पैदा कर रहा है।

इस साल के वेडिंग सीज़न में एक और महत्वपूर्ण बदलाव दिख रहा है, जो सीधे देशहित से जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले वेडिंग इन भारत का आह्वान किया था। लगता है देश के संभ्रांत वर्ग ने इस अपील को गंभीरता से लिया। कुछ साल पहले तक, इटली का लेक कोमो या तुर्की के रिसॉर्ट्स भारतीय अमीरों की पहली पसंद थे। करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा इन डेस्टिनेशन वेडिंग्स के नाम पर देश से बाहर जा रही थी। लेकिन इस साल रुझान बदला है। उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, केरल और गोवा जैसे भारतीय स्थलों की मांग में जबरदस्त उछाल आया। जब एक बड़ी डेस्टिनेशन वेडिंग भारत में होती है, तो उसका फायदा हमारे होटल उद्योग व एयरलाइंस को मिलता है, और हस्तशिल्पियों को मिलता है। यह 'रिवर्स ड्रेन ऑफ वेल्थ' रोकने का माध्यम बन रहा है।

इसके साथ ही, 'वोकल फॉर लोकल' का असर भी दिख रहा है। बाज़ारों से चीनी लाइटें और सस्ते प्लास्टिक फूल धीरे-धीरे गायब हो रहे हैं। उनकी जगह स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए मिट्टी के दीये, गेंदे के फूलों और भारतीय कपड़ों ने ले ली। यह बदलाव सिर्फ आर्थिक नहीं, भावनात्मक भी है। हम जड़ों की ओर लौट रहे, और हमारी जड़ें हमारे बाज़ार को सींच रही हैं।

अगर भारत शादियों का देश है, तो दिल्ली उसकी राजधानी। कैट की रिपोर्ट विशेष रूप से दिल्ली को इस पूरी आर्थिक गतिविधि का केंद्र बिंदु मानती है। अकेले दिल्ली में इस सीज़न में करीब 4.8 लाख शादियां होने का अनुमान है। दिल्ली के बाज़ारों-चांदनी चौक से लेकर लाजपत नगर, साउथ एक्स से छोटे-मोटे बाज़ारों तक- में करीब 1.8 लाख करोड़ रुपये का कारोबार होने की उम्मीद है। वहां झुग्गी बस्तियों से लेकर पॉश कॉलोनियों तक, हर जगह शहनाई बज रही है। बजट अलग हो सकता है, लेकिन जज़्बा वही।

अक्सर जेहन में यह सवाल उठता है - आखिर हम भारतीयों के लिए शादियों को भव्य बनाना इतना ज़रूरी क्यों है? क्यों एक पिता २० साल तक अपनी ज़रूरतें मारकर बचत करता है, ताकि वह १ दिन की दावत में उसे खर्च कर सके? पश्चिमी अर्थशास्त्री इसे 'तर्कहीन' मान सकते हैं, संसाधनों की बर्बादी कह सकते हैं। लेकिन भारतीय संदर्भ में, यह खर्च सिर्फ उपभोग नहीं, बल्कि 'सामाजिक निवेश' है। रिश्ते मज़बूत करने, सामाजिक दायरा बढ़ाने और अपनी सांस्कृतिक विरासत अगली पीढ़ी को सौंपने का तरीका है। मजे की बात यह कि यही 'भावनात्मक खर्च' हमारी अर्थव्यवस्था को मंदी के झटकों से बचाता है। जब पश्चिम के लोग मंदी के डर से पैसा तिजोरी में बंद कर देते हैं, तब भारतीय लोग शुभ मुहूर्त देखकर बाज़ार में निकल पड़ते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था तर्कों से ज़्यादा भावनाओं पर चलती है, और शादियां उस भावना का सबसे बड़ा उत्सव हैं।

संपादकीय

चिंतन-मनन

स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर: अटूट कनेक्शन : डॉ विजय गर्ग

यह विचार कि मन और शरीर अलग-अलग संस्थाएं हैं, आधुनिक विज्ञान द्वारा तेजी से खारिज किया जा रहा है। सच्चाई यह है कि आपका मस्तिष्क और शरीर एक अंतर्संबंधित प्रणाली हैं, जहां एक का स्वास्थ्य दूसरे को गहराई से प्रभावित करता है। एक स्वस्थ मस्तिष्क वह कमांड सेंटर है जो आपकी शारीरिक भलाई को निर्धारित करता है, और एक स्वस्थ शरीर इष्टतम मस्तिष्क कार्य के लिए आवश्यक ईंधन और वातावरण प्रदान करता है। मस्तिष्कः आपके शरीर का मास्टर नियामक आपका मस्तिष्क एक जटिल, तीन पाउंड का अंग है जो व्यावहारिक रूप से आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम को नियंत्रित करता है, सचेत विचारों और आंदोलनों से लेकर अनैच्छिक कार्यों तक जिनके बारे में आप शायद ही कभी सोचते हैं, जैसे कि आपकी हृदय गति, पाचन और श्वास। संचार नेटवर्कः अरबों तंत्रिका कोशिकाएं, या न्यूरॉन्स, आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में संकेत भेजते हैं। जब मस्तिष्क स्वस्थ होता है, तो ये संकेत तेजी से और कुशल होते हैं, जिससे अच्छा समन्वय, त्वरित प्रतिबिंब और तेज संज्ञानात्मक कार्य संभव हो जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य को नियंत्रित करनाः मस्तिष्क की भूमिका सोच से परे है। यह हार्मोन की रिहाई को नियंत्रित करता है, आपकी तनाव प्रतिक्रिया (₹लड़ाई या उड़ान₹ तंत्र) का प्रबंधन करता है, और यहां तक कि आपके प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य को भी प्रभावित करता है। क्रोनिक तनाव, एक मानसिक स्थिति, कोर्टिसोल जैसे हार्मोनों की रिहाई को ट्रिगर करती है, जिससे उच्च रक्तचाप और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली जैसी शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। आंत-मस्तिष्क धुरीः अनुसंधान तेजी से पेट-मस्तिथि अक्ष, एक दोतरफा संचार पथ पर प्रकाश डालता है। आपके आंतों के रोगाणुओं का स्वास्थ्य, जो आहार और तनाव से प्रभावित हो सकता है, सीधे आपके मूड, व्यवहार और भावनात्मक लचीलापन को प्रभावित करता है। एक सामंजस्यपूर्ण कनेक्शन के लिए मुख्य स्तंभ समग्र स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए, आपको मन और शरीर दोनों को पोषित करना चाहिए, यह समझते हुए कि आप एक क्षेत्र में जो प्रयास करते हैं वह दूसरे का लाभ उठाएगा। 1। शारीरिक गतिविधि मस्तिष्क चिकित्सा है मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए व्यायाम सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है। बेहतर रक्त प्रवाहः शारीरिक गतिविधि मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को बढ़ाती है, जिससे अधिक ऑक्सीजन और आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। मूड संवर्द्धनः यह एंडोर्फिन की रिहाई को ट्रिगर करता है शरीर के प्राकृतिक फील-गुड हार्मोन, जो चिंता और अवसाद के लक्षणों को काफी कम कर सकते हैं। तंत्रिका कोशिका वृद्धिः नियमित व्यायाम नए तंत्रिका कोशिका कनेक्शन के विकास को प्रोत्साहित करता है, जो स्मृति और समग्र संज्ञानात्मक कार्य में सुधार कर सकता है। 2। पोषण के साथ सिस्टम को ईंधन देना आप जो खाते हैं वह सीधे आपके मस्तिष्क और शरीर की संरचना और कार्य को प्रभावित करता है। मस्तिष्क ईंधनः पौधे-आधारित खाद्य पदार्थों, पत्तेदार साग, जामुन, अखरोट, और स्वस्थ वसा (जैसे मछली में पाए जाने वाले) से समृद्ध आहार मानसिक ध्यान के लिए आवश्यक ईंधन प्रदान करता है और संज्ञानात्मक गिरावट को धीमा कर सकता है। सूजन नियंत्रणः विरोधी भड़काऊ खाद्य पदार्थ मस्तिष्क और शरीर दोनों को पुरानी सूजन से जुड़े रोगों से बचाते हैं, जैसे हृदय रोग और स्ट्रोक, जो मस्तिष्क में संवहनी स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। 3। नींद की शक्ति नींद मस्तिष्क के लिए स्मृति को साफ करने और समेकित करने का मौका है, और शरीर की मरम्मत का समय है। बहालीः मस्तिष्क के कार्य, स्मृति और सतर्कता में सुधार के लिए एक अच्छी रात की नींद लेना महत्वपूर्ण है। तनाव प्रबंधनः पर्याप्त नींद तनाव और अवसाद को कम करती है, दैनिक चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए मन तैयार करती है। 4। मन-शरीर अभ्यास गतिविधियाँ जो रणनीतिक रूप से मानसिक ध्यान और शारीरिक आंदोलन को मजबूत करती हैं। तनाव में कमीः योग, ताई ची, ध्यान और गहरी सांस लेने जैसे अभ्यास तंत्रिका तंत्र को शांत करने में मदद करते हैं, जो बदले में तनाव हार्मोन को कम करता है, सूजन को कम करता और प्रतिरक्षा कार्य में सुधार करता है। आत्म-जागरूकताः ये प्रथाएं स्वयं की जागरूकता को बढ़ाती हैं, जिससे आपको शरीर के तनाव या भावनात्मक असुविधा (जैसे दौड़ते दिल या तनावपूर्ण मांसपेशियां) के शुरुआती संकेतों को पहचानने में मदद मिलती है ताकि आप हस्तक्षेप कर सकें और अपनी प्रतिक्रिया को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकें। निष्कर्ष एक स्वस्थ मस्तिष्क और एक स्वस्थ शरीर के बीच तालमेल लंबे, जीवंत जीवन की नींव है। लगातार छह स्तंभों का समर्थन करने वाले विकल्प बनाकर शारीरिक गतिविधि, स्वस्थ आहार, गुणवत्ता नींद, मानसिक जुड़ाव, सामाजिक संबंध और तनाव प्रबंधन— आप सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं कर रहे हैं; आप मास्टर सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। आपके मन का स्वास्थ्य और आपके शरीर की स्थिति दो अलग-अलग लड़ाइयाँ नहीं हैं, बल्कि एक एकीकृत मिशन है।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल पूर्व-पीईएस शैक्षिक स्तंभकार प्रख्यात शिक्षाविद स्ट्रीट कुर चंद एमएचआर पंजाब

फुटपाथ पर जीवन : डॉ विजय गर्ग

किसी दिन अपने भारत में भी ऐसा महानगर बने। दुबई बन सकता है अगर न्यूयार्क जैसा, तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई क्यों नहीं? दुबई को मैंने देखा है उन दिनों से जब यह मछुआरों का छोटा-सा शहर होता था कोई चालीस साल पहले। आज कल्पना करना मुश्किल है। कि कभी यहां सिर्फ एक-दो ऊंची इमारतें हुआ करती थीं और गिनती के एक दो माल। ऐसा नहीं है कि हमारे महानगर बदले नहीं हैं इस दौरान। बदले हैं जरूर, लेकिन इसलिए कि हमारी नगरपालिकाएं इतनी नाकारा हैं कि हमने इन महानगरों में वे सुविधाएं नहीं दी हैं जिनके बिना महानगर असली महानगर नहीं बन सकते हैं।

हमारे शासक हर स्तर पर इतने काहिल हैं कि अगर उनके काम को आपराधिक कुशासन कहा जाए, तो गलत न होगा। जब भी कोई छोटा शहर बड़ा बनता है, तो शासक ध्यान में इस बात को रख कर चलते हैं कि यहां रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करना उनका सबसे बड़ा दायित्व है। उनके लिए बिजली - पानी जैसी सुविधाएं'. तो हैं ही जरूरी, लेकिन मेरी राय में इससे भी जरूरी है कि उनके रहने के लिए घर बनें जिनका किराया गरीब भी दे सकें। मगर ऐसा न हमारे बड़े शहरों में होता है न छोटे शहरों में। गरीब लोग मजबूर हैं फुटपाथों पर अपने बसेरे डालने के लिए। जब ऐसा करते हैं, तो उनके पीछे पुलिस लगी रहती है जो उनको कूड़े की तरह समेट कर इधर से उधर फेंकती रहती है। उनके बच्चों को उठा कर ले जाती है और उनके जीवन को एक बुरे सपने में तब्दील कर देती है बिना यह सोचे कि फुटपाथों पर रहना उनका शौक नहीं उनकी मजबूरी है।

हमारी नगरपालिकाओं में भ्रष्ट अधिकारी इस हद तक हैं कि उनको चिंता रहती है अपने पेट की, शहर के नागरिकों की कम। इसलिए निर्माण की इजाजत देते हैं उनको, जिनके पास रिश्वत देने की ताकत होती है। ऐसा जानते हुए कि नुकसान सिर्फ शहर का नहीं होगा, पूरे देश का होगा। इस बात को वह अनदेखा करते हैं क्योंकि उनको चिंता रहती है सिर्फ इस बात की कि वे खुद कितना कमा सकते हैं किसी अनियोजित निर्माण की इजाजत देकर।

इसलिए हमारे सारे शहर विशाल झुग्गी बस्तियों की तरह दिखते हैं, जिनमें कुछ रिहाइशी और व्यावसायिक इलाके चमकते हैं और जिनके बीच दिखते हैं पांच सितारा होटल तथा माल।

उनकी लापरवाही का सबसे ज्यादा नुकसान होता है शहर के सबसे गरीब लाचार और बेबस नागरिकों का। मैं जिस दिन न्यूयार्क पहुंची थी मुझे फोन आया मुंबई के एक राजनेता का। उसने सोशल मीडिया पर मेरी एक ट्वीट देखी थी, जिसमें मैंने जिक्र किया था एक औरत का, जिसने अपनी सारी जिंदगी गुजारी है। मुंबई के फुटपाथों पर। मैं उसको तब से जानती हूं जब वह छोटी बच्ची थी। फुटपाथ पर पली और बड़ी हुई, फुटपाथ पर उसकी शादी हुई और वहीं उसके बच्चे भी पैदा हुए थे। पहली दो लड़कियां थीं और वह चाहती थी कि उनका जीवन उसके अपने जीवन से बेहतर हो, तो मेरी मदद से इन दोनों लड़कियों को एक निजी संस्था में डाला जो लावारिस बच्चों के लिए कुछ पारसी लोग चलाते हैं। बच्चियां बड़ी हो गई हैं, पढ़-लिख गई हैं, लेकिन उनकी मां अभी तक वहीं की वहीं है, जहां थी और उसका अब एक तीन साल का बेटा भी है।

जिस दिन मैं न्यूयार्क आ रही थी उसका फोन आया मुझे मुंबई की एक पुलिस चौकी से। उसने रोते हुए बताया कि पुलिसवाले उसको उठा कर लाए हैं और उसके बच्चे को 'चिल्ड्रन होम' में डालने की धमकी दे रहे हैं। यह 'चिल्ड्रंस होम' सरकारी है और उसमें बच्चों का इतना बुरा हाल है कि तकरीबन जेल जैसा माहौल है जहां तीन साल का बच्चा अगर बच जाए, तो गनीमत है। मैंने पुलिसवालों से मंगला को रिहा करने को कहा, तो एक पुलिसवाली मुझे उल्टा डांट कर कहने लगी कि किसी को

इजाजत नहीं है फुटपाथ पर रहने की। मैंने जब उसे बताया कि ये लोग चालीस साल से रह रहे हैं उसी फुटपाथ पर, तो उसने कहा कि अब उनको जाना होगा वहां से। मैंने जब पूछा कि कहां जाएं, तो उसने कहा कि इससे उसको कोई मतलब नहीं है।

यानी बेघर होना अपराध है मुंबई में, लेकिन गरीबों के लिए कम किराए वाले घर नहीं होना अपराध नहीं है। जेल भेजे जाते हैं लाचार गरीब लोग और शान से रहते हैं भ्रष्ट अधिकारी। जिस राजनीतिक ने मुझे फोन किया मेरी सोशल मीडिया की पोस्ट पढ़ कर, उसने कहा कि थाने से उसकी बात हुई है और उनका कहना है कि इनको इसलिए हटाया 'जा रहा है, क्योंकि यह जेब काटने जैसे गलत काम करते हैं और चलते-फिरते लोगों को तंग करते हैं। मैंने उसको आश्वासन दिया कि ये पैसा कमाते हैं फूल बेच कर और छोटे-मोटे काम करके। उनका अपराध सिर्फ बेघर होने का है।

ऐसे लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है, ताकि मुंबई की गुरबत सड़कों पर न दिखे। पिछले पैंतीस सालों से मैं इनके बारे में लिखती आई हूं, लेकिन आज तक किसी भी प्रशासन ने ऐसे रैन बसेरे नहीं बनाए हैं, जिसमें ये लोग शरण ले सकें और किराए ये लोग दे नहीं सकते हैं। न ही अपने गांव वापस जा सकते हैं, क्योंकि वहां का जीवन मुंबई के फुटपाथों के जीवन से बदतर है। जाएं तो जाएं कहां? तकरीबन यही हाल है उन मजदूरों का जो मुंबई और दिल्ली आते हैं दूर देहातों से नौकरी करने। ऐसा कभी न्यूयार्क जैसे में भी होता था, लेकिन सौ साल पहले। हमारे शहर कब न्यूयार्क जैसे बनेंगे?

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

भारत की जैव विविधता: एक दोहरी कहानी - संकट और आशा

डॉ विजय गर्ग

भारत, अपनी विशाल भौगोलिक विविधता के कारण, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। हालाँकि, यह देश गंभीर वन्यजीव संकट का सामना कर रहा है, जहाँ कई जीव-जंतुओं की प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर हैं। इसी निराशाजनक परिदृश्य के बीच, हाल ही में उभयचर जीवों की तेरह नई प्रजातियों की खोज वास्तव में एक राहत भरी खबर लेकर आई है और यह जैव विविधता के संरक्षण के महत्व को रेखांकित करती है।

विलुप्ति के कगार पर खड़ी प्रजातियाँ

वन्यजीवों के लिए संकट लगातार गहरा रहा है। मानवीय हस्तक्षेप, आवास का विनाश, जलवायु परिवर्तन, अवैध शिकार और प्रदूषण जैसे कारक कई प्रजातियों के अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं।

प्रमुख संकटग्रस्त प्रजातियाँः बाघ, एशियाई शेर, हिम तेंदुआ, एक सींग वाला गैंडा, काला हिरन, लायन टेल्ड मकाक (सिंह-पूँछ वाला बन्दर), गंगा डॉल्फिन, घड़ियाल और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (गोडावण) जैसी प्रतिष्ठित प्रजातियाँ गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं।

आंकड़ों की भयावहताः अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट के अनुसार, भारत में कई वन्यजीव प्रजातियाँ 'गंभीर रूप से संकटग्रस्त' श्रेणी में सूचीबद्ध हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार, भारत में जंगली जानवरों, सरीसृपों और पक्षियों की 133 प्रजातियाँ विलुप्त होने की कगार पर हैं।

उभयचरों पर विशेष खतराः उभयचर, जो जल और थल दोनों पर जीवन व्यतीत करते हैं, पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं और इसलिए उन्हें ₹बायो-इंडिकेटर्स₹ माना जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में पाए जाने वाले 426 उभयचर प्रजातियों में से 136 विलुप्त होने के कगार पर हैं, जो पश्चिमी घाट जैसे क्षेत्रों में विशेष रूप से चिंताजनक है।

आशा की नई किरणः 13 नई उभयचर प्रजातियों की खोज

इन्हीं चिंताओं के बीच हाल ही में भारत के पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर क्षेत्र में उभयचर जीवों की तेरह नई प्रजातियों की खोज एक सुखद आशा लेकर आई है। यह खोज सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति के गर्भ में अभी भी विविधता छिपी है, जिसे समझने और संरक्षित रखने की आवश्यकता है। नई प्रजातियों की पहचान बताती है कि अभी भी हमारे जंगलों में कई रहस्य अनछुए हैं और अगर संरक्षण सही तरीके से किया जाए तो जैव–विविधता को बचाया जा सकता है।

यह खोज भारत की वैज्ञानिक टीमों की मेहनत, आधुनिक डीएनए तकनीकों, और लगातार क्षेत्रीय सर्वेक्षणों का परिणाम है। इससे यह भी संदेश मिलता है कि यदि अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए और वन्य क्षेत्रों को संरक्षित रखा जाए तो जोखिम में पड़ी प्रजातियों को बचाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकते हैं।

लेकिन राहत की यह खबर हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ाती है। नई प्रजातियों की खोज केवल उत्साह का विषय नहीं, बल्कि यह चेतावनी भी है कि वर्तमान संरक्षण नीतियों और प्रयासों को और मजबूत करना होगा। अगर जंगल सुरक्षित रहे, प्रदूषण नियंत्रण में हो, और स्थानीय समुदायों को संरक्षण योजनाओं से जोड़ा जाए तो भारत की जैव–सम्पदा को बचाया जा सकता है।

इस अंधेरे दौर में, पूर्वोत्तर भारत से आई एक खबर ने जैव विविधता के प्रति आशा को जगाया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में उभयचरों की 13 नई प्रजातियों की खोज की है।

खोज का स्थानः ये प्रजातियाँ मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत के राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश (6 प्रजातियाँ), मेघालय (3 प्रजातियाँ), असम, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में पाई गई हैं। महत्वः ये सभी नई प्रजातियाँ 'रावोर्चेस्टेस' जीनस से संबंधित हैं, जिन्हें बुश मेंढक कहा जाता है। इस नवीनतम खोज से भारत में ज्ञात बुश मेंढक प्रजातियों की संख्या 82 से बढ़कर 95 हो गई है। जैव विविधता हॉटस्पॉटः यह खोज पूर्वोत्तर भारत की छिपी हुई जैव विविधता को उजागर करती है, जो वैश्विक जैव विविधता के हॉटस्पॉट का हिस्सा है। इस तरह की खोजें यह बताती हैं कि प्रकृति ने अभी भी अपने खजानों को पूरी तरह से नहीं खोला है, और यदि संरक्षण के प्रयास किए जाएं तो और भी कई अज्ञात प्रजातियों का अस्तित्व सामने आ सकता है।

निष्कर्षः संरक्षण का संकल्प

विलुप्त होती प्रजातियों का संकट एक अलार्म है कि हमें अपने प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा के लिए तत्काल और कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। हालाँकि, 13 नई प्रजातियों की खोज से यह भी स्पष्ट होता है कि हमारे पास अभी भी अज्ञात जैव विविधता को बचाने और उसका दस्तावेजीकरण करने का अवसर है।

यह खोज इस बात पर जोर देती है कि संरक्षण के प्रयास सिर्फ संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने तक ही सीमित नहीं होने चाहिए, बल्कि उन क्षेत्रों की सुरक्षा पर भी केंद्रित होने चाहिए जो अभी भी प्रकृति के रहस्यों को समेटे हुए हैं। भारत को अपनी वन्यजीव संरक्षण नीतियों को मजबूत करने, आवासों की रक्षा करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करना होगा, ताकि संकट और आशा की इस दोहरी कहानी में आशा की जीत हो सके।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

मसूरी में 600 प्रशिक्षु आईएएस और एक सवाल

"उंगलियों पर हल होने वाला सवाल और भविष्य के प्रशासकों की तैयारी का सच"

मसूरी से उठता सवाल : क्या हमारी प्रशासनिक शिक्षा केवल पुस्तकीय हो गई है? मसूरी में 600 प्रशिक्षु और एक सवाल जिसने सबको सोचने पर मजबूर किया। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी का वास्तविक लक्ष्य : 'थिंकिंग एडमिनिस्ट्रेटर' तैयार करना। प्रशिक्षण का अर्थ केवल पाठ नहीं। मसूरी की कक्षाओं में उठा एक छोटा-सा सवाल, बड़ी सीख। प्रशासनिक प्रशिक्षण का आईना : जब लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में एक साधारण सवाल ने बड़ा संदेश दिया। उत्तराखंड के मसूरी में 100वाँ फाउंडेशन कोर्स और नेतृत्व की बुनियादी समझ पर गहरा संकेत।

-- डॉ प्रियंका सौरभ

उत्तराखंड के शांत, अनुशासित और सुसंस्कृत वातावरण में स्थित मसूरी का प्रसिद्ध प्रशासनिक अकादमी परिसर—लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी—देश के सर्वोच्च सिविल सेवकों के निर्माण का केंद्र बिंदु है। यहाँ आज भी 600 से अधिक प्रशिक्षु अधिकारी भविष्य के भारतीय प्रशासन की रूपरेखा तय करने की तैयारी में डटे हैं। हाल ही में 100वें फाउंडेशन कोर्स का समापन समारोह आयोजित किया गया, जो किसी भी संस्थान के लिए गौरव का क्षण होता है। इस अवसर पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा और भी बढ़ा दी।

समारोह के दौरान रक्षा मंत्री ने एक सरल-सा गणितीय प्रश्न पूछा— "एक आदमी के पास कुछ पैसे थे। उसने आधा ए को, एक-तिहाई बी को और शेष 100 रुपये सी को दिए। बताइए, कुल पैसा कितना था?"

दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाला यह सीधा-सा सवाल प्रशिक्षुओं के लिए अप्रत्याशित सिद्ध हुआ। कई प्रशिक्षु अधिकारी प्रश्न में उलझ गए, जबकि समाधान उंगलियों पर किया जा सकता था। बाद में स्वयं राजनाथ सिंह ने इसे सरल तरीके से हल कर समझाया। यह घटना भले ही साधारण प्रतीत हो, पर प्रशासनिक प्रशिक्षण और नेतृत्व क्षमता की वास्तविक दिशा पर यह बेहद महत्त्वपूर्ण संकेत देती है।

प्रशासनिक कार्यों का मूल तत्व केवल कानून और नियमों का ज्ञान नहीं, बल्कि तुरंत समझने, तर्क लागू करने और व्यवहारिक समाधान निकालने की क्षमता है। कभी-कभी सबसे कठिन परिस्थितियों में सर्वाधिक सरल समाधान ही सर्वश्रेष्ठ होता है—पर इसके लिए मन का खुलापन और व्यावहारिक सोच आवश्यक होती है। यही गुण एक सक्षम प्रशासक को भीड़ से अलग करता है।

यह घटना इस बात का स्मरण भी कराती है कि सिविल सेवा केवल अकादमिक बौद्धिकता का अभ्यास नहीं है; यह मानव स्वभाव, सामाजिक व्यवहार, त्वरित निर्णय-क्षमता और सामान्य समझ की माँग भी करती है। किसी भी शासन प्रणाली में सबसे प्रभावशाली अधिकारी वही होता है जो जटिल समस्याओं को सरलता से हल करने की क्षमता रखता हो।

प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन नहीं, बल्कि व्यवहारिक बुद्धि का विकास भी है। एक छोटा सा प्रश्न प्रशिक्षुओं को यह याद दिलाता है कि वास्तविक प्रशासन वही है जो खेत-खलिहान, बाज़ार, थाने, पंचायत भवन और कार्यालयों में घटित होता है—जहाँ जटिलताएँ कम और सादगी अधिक काम आती है।

राजनाथ सिंह द्वारा पूछा गया प्रश्न प्रशासनिक सोच के दो महत्त्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करता है—

पहला, अधिकारी का ध्यान समस्या के मूल की ओर होना चाहिए, न कि उसकी सतही जटिलता की ओर।

दूसरा, किसी भी चुनौती में घबराना नहीं, बल्कि उसे विभाजित कर सरल रूप में हल करना चाहिए।

सिविल सेवाओं में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब अधिकारी को अचानक लिए गए निर्णयों के आधार पर जनता को राहत, दिशा और सुरक्षा प्रदान करनी होती है। यदि वह क्षणिक दबाव में भी सामान्य तर्क बनाए रखने में दक्ष है, तो वह बेहतर प्रशासक बन सकता है।

यह प्रसंग इस व्यापक प्रश्न को भी जन्म देता है कि आधुनिक प्रशिक्षण पद्धति कहीं अत्यधिक तकनीकी, सैद्धांतिक या औपचारिक तो नहीं हो गई है? क्या हम प्रशासन के मूल तत्व—सरलता, संवेदनशीलता और सामान्य विवेक—को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे?

सिविल सेवा का इतिहास बताता है कि देश के श्रेष्ठ अधिकारी वही रहे, जिन्होंने अत्यधिक बुद्धि के साथ-साथ सरल सोच, जन-संपर्क की क्षमता और सहज निर्णय-प्रक्रिया अपनाई। आज जब देश नई चुनौतियों—प्रौद्योगिकी, जटिल प्रशासनिक व्यवस्था, विस्तृत जनसंख्या और त्वरित परिवर्तनों—से गुजर रहा है, तब एक प्रशासक की भूमिका और भी विस्तृत और बहुआयामी हो चुकी है।

ऐसे समय में यह आवश्यक है कि प्रशिक्षण केवल परीक्षाओं और पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न हो। उसमें व्यवहारिक गणित, तर्कशक्ति, सामान्य समझ, मनोवैज्ञानिक संतुलन और परिस्थितिजन्य विश्लेषण को भी समुचित स्थान मिले।

राजनाथ सिंह द्वारा हल्का-सा पूछा गया यह प्रश्न प्रशासनिक तंत्र को यह संदेश देता है कि नेतृत्व की असल परीक्षा कभी-कभी छोटे-छोटे क्षणों में ही होती है। बड़े निर्णयों का आधार भी वही अधिकारी बनता है जो बेसिक समझ को खोने नहीं देता।

इस प्रसंग से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रशिक्षण के दौरान आने वाले ऐसे अप्रत्याशित प्रश्न अधिकारी के मन को गति देते हैं, उसे दबाव में सोचने की क्षमता प्रदान करते हैं और वास्तविक प्रशासनिक दुनिया के लिए मानसिक रूप से तैयार करते हैं।

समय के साथ यह आवश्यक हो गया है कि सिविल सेवा प्रशिक्षण अकादमियाँ इस प्रकार के संवाद, प्रश्न-आधारित परीक्षण और व्यवहारिक अभ्यास को और भी अधिक बढ़ाएँ। इससे अधिकारी न केवल जनसेवा के लिए अधिक तैयार होंगे बल्कि प्रशासनिक जटिलताओं को सहजता से हल करने की क्षमता भी विकसित करेंगे।

निष्कर्षतः, मसूरी में घटित यह छोटा-सा घटना क्रम इस बात का प्रतीक है कि नेतृत्व की ताकत केवल बड़े भाषणों या उच्च ज्ञान में नहीं, बल्कि सरल तर्क और मौलिक समझ में भी निहित होती है। सिविल सेवा के भविष्य को आकार देने वाले प्रशिक्षुओं के लिए यह एक स्मरणीय संदेश है—प्रशासन की महानता सरलता में है, न कि जटिलता में।

उच्च न्यायालय से हेमंत सोरेन को मिली राहत, एमपी एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट

सियासी बवंडर के बीच मुख्यमंत्री सफ़र निर्विरोध जारी

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची, झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत देते हुए उन्हें एक चर्चित मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी। जमीन घोटाले से जुड़ा यह केस ईडी द्वारा दायर किया गया है। उच्च न्यायालय ने यह फैसला सोरेन द्वारा दायर उस याचिका पर सुनाया, जिसमें उन्होंने एमपी एम एल ए कोर्ट के स्पेशल जज द्वारा जारी उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा गया था। केंद्रीय एजेंसी ने सोरेन के खिलाफ शिकायती केस तब दर्ज किया था जब उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन के बाद ईडी कार्यालय में पेश होने मना कर दिया था। इसके बाद १५ नवंबर को हाई कोर्ट ने ईडी द्वारा दायर एक मामले में रांची की एमपी एमएलए अदालत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पेशी पर लगी रोक हटा दी थी।

ईडी दफ्तर में पेश नहीं होने को लेकर शिकायत करने वाले ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर देवराज झा ने अपनी शिकायत में बताया कि सोरेन को कथित जमीन घोटाले में शामिल होने के सिलसिले में एजेंसी के सामने पेश होने के लिए 10 समन जारी किए गए थे। लेकिन सोरेन सिर्फ दो समन के जवाब में पेश हुए थे, जबकि बाकी समन को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया।

इसके बाद, ईडी ने साल २०२४ में एमपी एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज के सामने एक शिकायत याचिका दायर की। इस शिकायत याचिका की सुनवाई के दौरान, विशेष न्यायाधीश ने सोरेन को रांची स्थित एमपी एमएलए कोर्ट के सामने खुद पेश होने का आदेश दे दिया। इसके बाद सोरेन ने एमपी एमएलए अदालत के इस आदेश को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी।

उच्च न्यायालय ने मामले में ईडी को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था और दिसंबर २०२४ को सोरेन एमपी एमएलए अदालत में पेश होने के आदेश पर रोक लगा दी थी। पिछले साल दिसंबर में हाई कोर्ट के आदेश के कारण, एमपी एमएलए कोर्ट में सोरेन की पेशी पर रोक लगा दी गई थी। राज्य सरकार ने नवंबर में मामले में पेश होते हुए हाई कोर्ट में सुनवाई टालने की मांग की थी। तब कोर्ट ने सरकार को सुनवाई टालने की अनुमति देते हुए, सोरेन के मामले में पहले दिए गए स्टे ऑर्डर (स्थगन आदेश) को रद्द कर दिया।

कानपुर में करोड़ों की जमीन ने करवा दी युवक की हत्या : हिरासत में दो भाई, जांच

सुनील बाजपेई

कानपुर। हत्या के रूप में किसी की मौत और सारे बवाल की वजह जड़ यानी पुरानी रंजिश, जोरू मतलब स्त्री और जमीन ही बनती है। यह पुरानी कहावत कानपुर में भी चरितार्थ होती तब नजर आई जब करोड़ की जमीन के चक्कर में एक युवक की बेरहम सी हत्या कर दी गईआज बुधवार को उसकी लाश मिलने के बाद पुलिस घटना की छानबीन करने के साथ ही हत्यारों की भी तलाश में जुट गई है। इस हत्या की वजह

2.40 करोड़ की जमीन के विवाद से से जुड़ी बताई जाती है ,जिसके चक्कर में ही पान मसाला फैक्ट्री कर्मी की हत्या कर दी गई। उसकी लाश पांडु नदी के पास खाली प्लॉट में पड़ी मिली। युवक के सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। उसके दोनों हाथ पीछे की ओर रस्सी से बंधे थे। चेहरे को बोरी से ढक कर ऊपर पत्थर रख दिया गया था।

यह घटना गुजैनी थाना क्षेत्रके मेहरबान सिंह के पुरवा की है ।लोगों को इस घटना की जानकारी तब हुई जब आज बुधवार सुबह लोग टहलने निकले तो शव देखते ही पुलिस को सूचना दी। हत्या की सूचना पर डीसीपी साउथ, एडीसीपी मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने चेहरे से बोरी हटाई तो सिर के पीछे से खून निकलता दिखा। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मामले में हत्यारोपी दो भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

मौके पर पहुंची पुलिस को साढ़ कस्बे के रहने वाले गंगा प्रसाद ने बताया दोनों बेटे अमित तिवारी व विपिन उर्फ गुड्डू (32) ट्रांसपोर्ट नगर की पान मसाला फैक्ट्री में 8 साल से काम करते थे। अमित जहानपुर में रहता है, जबकि विपिन मेरे, अपनी मां रामसुती, पत्नी शैलू और दो जुड़वा बेटे रामजी, श्यामजी के साथ रहता था। विपिन रोज बस से फैक्ट्री जाता था। वह कल मंगलवार शाम 6 बजे वह फैक्ट्री जाने के लिए घर से निकला था।

बड़े भाई अमित ने बताया- शाम 7:30 बजे विपिन से फोन पर बात हुई तो उसने कहा- बारादेवी पहुंच रहा हूं। फैक्ट्री आने में कुछ देर हो जाएगी। करीब एक घंटे बाद फोन किया, तो कॉल रिसीव नहीं हुई। कुछ देर बाद मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा। पुलिस ने बताया कि लास्ट को पोस्टमार्टम के लिए बेचकरघटना की छानबीन की जा रही है।

इंदौर के युवा गायक अंश जैन का सम्मान किया गया

हरिहर सिंह चौहान इन्दौर

जी आई एस (गोल्डन इंटरनेशनल स्कूल इंदौर) में एक अवार्ड कार्यक्रम रखा गया था। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप मे कर्नल जितेन्द्र बहादुर सिंह जी (कमांडिंग ऑफिसर, इन्फेंटरी स्कूल महू) की उपस्थिति गरिमा पूर्ण रही। साथ ही इन्दौर के युवा गायक अंश जैन ने कुछ समय पूर्व स्कूल में आयोजित बच्चों के संगीत स्पर्धा में निर्णायक की भूमिका निभाई थी। जिसके अंतर्गत स्कूल के डायरेक्टर गोपाल अग्रवाल एवं प्रिंसिपल सर टी आर ब्राउन और उनके स्कूल स्टॉफ के द्वारा उनका सम्मान किया गया। उन्हें सम्मानित करते हुए युवा गायक अंश जैन को एक ट्रॉफी प्रदान की गयी। इसमें प्रभावी भूमिका अनुराग जैन व प्रिंस जैन की रही।

नई पीढ़ी की आवाजें: नेतृत्व और जीवन

वर्तमान समय तीव्र परिवर्तन का युग है। तकनीक, विचारधाराओं, सामाजिक मूल्यों और जीवनशैली में निरंतर हो रहे बदलावों ने समाज की दिशा और गति दोनों को प्रभावित किया है। इन परिवर्तनों के केंद्र में खड़ी है नई पीढ़ी, जो अपने स्पष्ट विचारों, नवाचारों, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक चेतना के कारण वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान बना रही है। नई पीढ़ी की सोच और उसका नेतृत्वशैली पारंपरिक ढाँचों से भिन्न है। यह पीढ़ी महज़ बदलाव की बात नहीं करती, बल्कि स्वयं बदलाव की प्रक्रियाओं को गति देती हुई दिखाई देती है। समाज, राजनीति, विज्ञान, तकनीक, कला, उद्यमिता और सामुदायिक नेतृत्व—हर क्षेत्र में युवा वर्ग की सक्रियता और प्रभाव उल्लेखनीय है।

नेतृत्व का बदलता स्वरूप

आज का युवा नेतृत्व को केवल पद या अधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया नहीं मानता, बल्कि इसे प्रेरणा, सहभागिता और सामूहिक प्रगति का माध्यम मानता है। जहाँ पारंपरिक नेतृत्व अनुभव आधारित था, वहीं नई पीढ़ी का नेतृत्व आत्मविश्वास, नवाचार और प्रयोगशीलता पर आधारित है।

युवा मानते हैं कि नेतृत्व का आधार—

पारदर्शिता, प्रामाणिकता, सहभागिता, और समानता पर होना चाहिए। इसी कारण "सहभागी नेतृत्व मॉडल" तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है, जिसमें टीम के प्रत्येक सदस्य की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है।

जीवन-दृष्टि: स्वतंत्रता और संतुलन की खोज

नई पीढ़ी का दृष्टिकोण जीवन को केवल जिम्मेदारियों के दायरे में बाँधकर नहीं देखता। उनके लिए जीवन—स्वयं की पहचान,

व्यक्तिगत विकास, रचनात्मकता,

मानसिक स्वास्थ्य और समाज के प्रति योगदान का संतुलित संगम है। युवा वर्ग "जीने के लिए काम" की अवधारणा को अपनाता है, न कि "काम करने के लिए जीने" को। यही दृष्टि उन्हें अधिक संवेदनशील और मानवीय बनाती है।

डिजिटल युग: शक्ति और अवसर

डिजिटल दुनिया नई पीढ़ी की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरी है। इंटरनेट, स्मार्टफोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सोशल मीडिया और नई तकनीकों ने उनके सोचने, सीखने और अभिव्यक्ति के तरीके में व्यापक परिवर्तन लाया है। तकनीक ने युवाओं को वैश्विक मंचों तक पहुँचाया, असीमित जानकारी, और स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रदान की है। आज का युवा एक कमरे में बैठकर भी लाखों लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि डिजिटल नेतृत्व एक नई सामाजिक शक्ति के रूप में उभर रहा है।

मूल्य और नैतिकता

नई पीढ़ी अपने मूल्य और नैतिकता को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है। वे अन्याय, असमानता, हिंसा और भेदभाव के खिलाफ खुलकर आवाज उठाते हैं।

युवा नेतृत्व के प्रमुख मुद्दों में

महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, मानसिक स्वास्थ्य, पशु अधिकार, और शिक्षा का लोकतांत्रिक विस्तार जैसे विषय प्रमुख

हैं। यह पीढ़ी परंपराओं का सम्मान करती है, लेकिन गलत प्रथाओं को चुनौती देने में पीछे नहीं हटती।

अवसर निर्माण की शक्ति

नौकरी तलाशने से अधिक अवसर बनाने में विश्वास रखने वाली नई पीढ़ी उद्यमिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रही है। भारत सहित विश्वभर में युवा स्टार्टअप्स—सामाजिक नवाचार, पर्यावरण संरक्षण, तकनीकी प्रगति और मानव हित को केंद्र में रखकर काम कर रहे हैं। असफलताओं को सीखने का हिस्सा मानना, जोखिम उठाने का साहस और वैश्विक दृष्टि—युवा उद्यमिता की सबसे बड़ी विशेषताएँ हैं।

वैश्विक सोच, स्थानीय समझ

नई पीढ़ी वैश्विक विचारधारा से प्रेरित है, लेकिन अपनी जड़ों से भी गहराई से जुड़ी रहती है। यह पीढ़ी अंतरराष्ट्रीय अनुभवों को स्थानीय समस्याओं के समाधान में उपयोग करने की क्षमता रखती है। उनके माध्यम से परंपरा और आधुनिकता का संतुलित समन्वय संभव है, जो किसी भी विविधतापूर्ण समाज के विकास के लिए आवश्यक है।

चुनौतियाँ भी कम नहीं

नई पीढ़ी की आवाज़ें मज़बूत होने के बावजूद युवाओं के सामने कई चुनौतियाँ मौजूद हैं—

प्रतिस्पर्धा का दबाव, मानसिक तनाव, सोशल मीडिया का प्रभाव,

परिवार व समाज की अपेक्षाएँ,

करियर-जीवन संतुलन, और पर्यावरणीय संकट।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए अनुभव और मार्गदर्शन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। वरिष्ठ पीढ़ी का सहयोग और समझ युवाओं के लिए दिशा-निर्देशक सिद्ध हो सकता है।

भविष्य की धड़कनें हैं नई पीढ़ी की आवाजें

नई पीढ़ी का नेतृत्व आने वाले समय में समाज और विश्व की दिशा तय करेगा। उनके विचारों में नवाचार, कार्यों में गति और दृष्टिकोण में मानवता प्रमुख है।

यदि उन्हें उपयुक्त अवसर और वातावरण मिले, तो वे एक ऐसा भविष्य गढ़ सकते हैं जो अधिक न्यायपूर्ण, समानतापूर्ण और मानवीय होगा। नई पीढ़ी की आवाज़ें केवल विचार नहीं—भविष्य की धड़कनें हैं। यह पीढ़ी एक ऐसा कल लिख रही है जिसमें मनुष्य और मानवता दोनों केंद्र में होंगे।

लता जोशी शिक्षाविद्, लेखिका

"मोटिवेशनल स्पीकर कनुप्रिया का प्रेरक कैरियर सत्र—छात्राओं ने जाना भविष्य की राह"

डॉ.शंभू पंवार

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में कार्यरत एवं मोटिवेशनल स्पीकर, कैरियर मार्गदर्शक, रेडियो प्रेजेंटर कनुप्रिया ने सर्वोदय बाल कन्या विद्यालय, मंडावली पटपड़गंज, दिल्ली में 11वीं और 12वीं कक्षा की छात्राओं के लिए प्रेरक कैरियर मार्गदर्शन संगोष्ठी को संबोधित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़ाना था, बल्कि 12वीं के बाद उपलब्ध विविध और नवीन करियर विकल्पों की स्पष्ट और व्यावहारिक जानकारी प्रदान करना भी था।

कनुप्रिया ने बदलते समय, नई तकनीकों और उभरते अवसरों की चर्चा करते हुए बताया कि आज का युग पारंपरिक करियर के साथ-साथ डिजिटल मीडिया, मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, डाटा एनालिटिक्स, डिज़ाइनिंग, टूरिज्म, होटल मैनेजमेंट तथा प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे अनगिनत क्षेत्रों में भी अवसरों से भरा हुआ है। उन्होंने मानविकी, वाणिज्य और विज्ञान—तीनों ही विधाओं में उपलब्ध संभावनाओं का सरल और प्रभावी भाषा में विश्लेषण किया। संगोष्ठी के दौरान छात्राओं ने उत्साहपूर्वक करियर से जुड़े अनेक प्रश्न पूछे—कौन-सा कोर्स चुनें? रुचि कैसे पहचानें? कौन-सा विषय किस करियर में सहायक है?—इन सवालों से पूरा माहौल संवादपूर्ण और जीवंत हो उठा। कनुप्रिया ने धैर्यपूर्वक सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा "कैरियर का चुनाव रुझान, क्षमता और लक्ष्य की पहचान से होता है। डरकर नहीं, जानकारी लेकर आगे बढ़ें।" उन्होंने 12वीं के बाद उपलब्ध कौशल आधारित कोर्स, डिप्लोमा प्रोग्राम, अनुवाद, भारतीय भाषा और विदेशी भाषा में कोर्स और नए उभरते व्यवसायों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। कार्यक्रम में विद्यालय की प्रधानाचार्य सुश्री समता जैन, शिक्षकगण और विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहे। प्रधानाचार्या ने कनुप्रिया के विचारों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम छात्राओं को जीवन और करियर—दोनों में स्पष्ट दिशा देने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं।

वॉटर, वॉर और वीरता: नौसेना दिवस की कहानी

[नीला आकाश, नीला समंदर, और सफेद वर्दी का जज़्बा]

[सफेद वर्दी, लाल-जज़्बा : समुद्र की ओर भारत का गर्व]

जब समुद्र की लहरें तेज़ी से उठती हैं और युद्धपोतों की गड़गड़ाहट आसमान तक गूँजती है, तब पूरा भारत गर्व से भर उठता है—यही है नौसेना दिवस की सच्ची शक्ति। 4 दिसंबर का यह खास दिन वह पल है जब देश अपने समुद्री वीरों को दिल से सलाम करता है। यह कोई साधारण तारीख नहीं, बल्कि 1971 के भारत-पाक युद्ध की वह यादगार रात है जब भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर ऐसा वार किया कि दुश्मन संभल ही नहीं पाया। ऑपरेशन ट्राइडेंट, जिसका नाम सुनते ही रोमांच दौड़ जाए। पहली बार किसी एशियाई देश ने एंटी-शिप मिसाइलों का इस्तेमाल किया, चार पाकिस्तानी जहाज़ डूब गए, कराची का बंदरगाह जल उठा और उनकी नौसेना बिखरकर रह गई। यह सिर्फ जीत नहीं, बल्कि समुद्री युद्ध के इतिहास में लिखा गया एक चमकता हुआ अध्याय था। तभी से 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस के रूप में पूरे देश में गर्व के साथ मनाया जाता है।

लेकिन यह दिन सिर्फ इतिहास की वीरगाथा नहीं सुनाता, यह वर्तमान की ताकत और भविष्य की तैयारी का भी प्रमाण है। भारतीय नौसेना आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और सबसे सक्षम नौसेनाओं में शुमार है। 67000 से ज्यादा जांबाज़ सैनिक, 150 से अधिक युद्धपोत, 250 से भी अधिक विमान और पनडुब्बियाँ—ये सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि हिंद महासागर में भारत की संप्रभुता का दस्तावेज़ है। आईएनएस विक्रांत – देश का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत – जब समुद्र में उतरा, तब पूरी दुनिया ने देखा कि भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं, बल्कि खुद अपनी शक्ति गढ़ने वाला राष्ट्र है। वहीं आईएनएस अरिहंत ने जब परमाणु त्रिशूल पूरा किया, तो बड़े-बड़े देश भी भारत की क्षमता के आगे गंभीर हो गए। बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस यह पनडुब्बी दुश्मन के लिए साफ संदेश है—भारत की ओर आँख उठाई, तो कीमत भी चुकानी पड़ेगी और जवाब भी ऐसा मिलेगा कि याद रखना मुश्किल हो जाएगा।

हिंद महासागर में भारतीय नौसेना आज सिर्फ रक्षक नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र का संतुलन संभालने वाली शक्ति है। मालदीव संकट में जब ऑपरेशन कैक्टस चला, श्रीलंका में आईपीकेएफ के दौरान जब नौसेना ने मानवीय मदद पहुँचाई, सुनामी की तबाही में जब हजारों जानें बचाईं, और हाल ही में ऑपरेशन राहत व ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब युद्धग्रस्त देशों से भारतीयों को सुरक्षित घर लाया गया—हर बार नौसेना ने साबित किया कि उसकी ज़िम्मेदारी केवल समुद्र की सुरक्षा तक सीमित नहीं है। उसकी पहुँच वहाँ तक है, जहाँ तक भारत का एक भी नागरिक मौजूद है—चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो।

आज जब चीन अपनी 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' रणनीति से हिंद महासागर में घेरा कसने की कोशिश कर रहा है, भारतीय नौसेना बिल्कुल शांत बैठने वाली नहीं है। क्वाड का मजबूत सदस्य बनकर, मालाबार अभ्यास में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ कदम मिलाकर, फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास में अपनी क्षमता दिखाकर, और रूस के साथ इंद्रा नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेकर भारत ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है—हिंद महासागर में दबाव, धमकी या दादागिरी नहीं चलेगी। आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस चक्र, ब्रह्मोस से लैस स्टील्थ फ्रिगेट्स और पी-8आई पोसाइडन विमान

सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि भारत की दृढ़ इच्छाशक्ति और समुद्री शक्ति के चमकते प्रतीक हैं।

लेकिन नौसेना की सच्ची शक्ति उसके लोहे के जहाज़ों में नहीं, बल्कि उन सफेद वर्दी वाले वीरों में बसती है। वे ही हैं जो महीनों अपने परिवार से दूर रहते हैं; जब तूफान जहाज़ को झकझोरता है, नीचे अथाह समुद्र और ऊपर दुश्मन की नज़र होती है—फिर भी उनके चेहरे पर मुस्कान रहती है। वे समुद्र की गोद में रातें काटते हैं, ताकि करोड़ों भारतीय चैन से सो सकें। उनकी आँखों में गहराई है, दिल में देशभक्ति की गर्मी और हाथों में अजेय साहस। और उनके पीछे खड़ी होती हैं वे माएँ जो बेटे के जहाज़ पर चढ़ते ही आशीर्वाद देती हैं, वे पत्नियाँ जो हर तूफान में प्रार्थना करती हैं, वे बच्चे जो दिन गिनते रहते हैं—यही मौन शक्ति नौसेना को अपराजेय बनाती है।

हर साल नौसेना दिवस पर जब गेटवे ऑफ इंडिया के सामने जहाज़ सलामी देते हैं, जब मिग-29के आसमान को चीरते हुए दहाड़ते हैं, जब काले परिधान में मार्कोस कमांडो अपने रोमांचक करतब दिखाते हैं—तब हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। पर यह गर्व सिर्फ उस पल तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि यह नीली सीमा हमें यूँ ही नहीं मिली; इसे वीरों ने अपने जीवन से सुरक्षित किया है। कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला, जिन्होंने आईएनएस खुकरी के डूबते समय जहाज़ के साथ समुद्र में समा जाना चुना, सिखाते हैं कि वर्दी से ऊपर कुछ भी नहीं। लेफ्टिनेंट कमांडर कपिश सिंह मुन्नो ने दुश्मन की पनडुब्बी को ध्वस्त कर दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय वीरों की नसों में डर नहीं—दृढ़ता बहती है।

4 दिसंबर वह दिन है जब राष्ट्र अपने समुद्री क्षितिज को देख कर खुद से एक वादा करता है कि भारतीय नौसेना को हम और भी अजेय, और भी अतुल्य बनाएँगे। यह केवल जश्न मनाने का अवसर नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने का पल है। हम स्वदेशी जहाज़ों और हथियारों की शक्ति से वह आधार रचेंगे, जिस पर एक दिन दुनिया की सबसे मजबूत नौसेना का ध्वज गर्व से लहराएगा। यह दिन हमें याद दिलाता है कि समुद्र महज़ जलराशि नहीं—यह भारत की साँस, भारत की गति, भारत की जीवनरेखा है। हमारे 90 प्रतिशत से अधिक व्यापार का मार्ग इसी नीले विस्तार से होकर गुजरता है। यदि यह मार्ग बाधित हुआ, तो न केवल हमारी सुरक्षा, बल्कि हमारी सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था ठहर जाएगी। इसलिए नौसेना की ताकत देश की सीमाओं की रखवाली ही नहीं करती, बल्कि हर नागरिक की समृद्धि की रक्षा भी करती है।

और इसी वजह से, इस नौसेना दिवस पर हमें केवल ताली बजाकर आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए। हमें अपने बच्चों को उन जांबाज़ों की गाथाएँ सुनानी चाहिए, जिनकी सफेद वर्दी में भारत का गर्व, साहस और स्वाभिमान चमकता है। उन्हें समझाना चाहिए कि यह वर्दी सिर्फ कर्तव्य का वस्त्र नहीं—यह राष्ट्र की प्रतिष्ठा का प्रतीक है। उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि वे भी एक दिन इस अथाह नीले प्रहरी का हिस्सा बनें। क्योंकि जब तक यह सफेद वर्दी समुद्र की लहरों पर शान से दमकती रहेगी, तब तक भारत की आन, बान और शान सुरक्षित, सशक्त और अडिग रहेगी। जय हिंद। जय भारतीय नौसेना।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

जागा मिशन के नाम पर करोड़ों की वसूली—पट्टा वितरण में भारी अनियमितताएं - प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजकुमार यादव

राउरकेला में विवाद तेज, राशि वापसी की मांग पर बस्तीवासियों का उबाल

परिवहन विशेष न्यूज

राउरकेला: ओडिशा में सत्ता परिवर्तन के बाद जागा मिशन के तहत राउरकेला नगर निगम द्वारा किए गए पट्टा वितरण को लेकर गंभीर आरोप उभरकर सामने आए हैं। मिशन की आड़ में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं और भ्रष्टाचार हुए होने का आरोप है, जिसके तहत बस्तीवासियों से पट्टा के नाम पर करोड़ों रुपये वसूले गए—जबकि सरकारी प्रावधानों के अनुसार यह योजना पूरी तरह निःशुल्क थी।

तथ्यों के अनुसार—

कुल 4747 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण के योग्य पाया गया।

इनमें से 1423 लोगों को मुफ्त में प्रमाण पत्र दिया गया।

जबकि 1528 लाभार्थियों से कुल 2,80,76,670 की वसूली की गई।

निगम के अनुसार यह राशि लेखा अनुभाग में जमा है और सभी प्रमाण पत्र तहसीलदार के हस्ताक्षर सहित जारी किए गए।

हालाँकि, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजकुमार यादव ने निगम के दावों पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि—

"रिकॉर्ड में चढ़ी रकम तो केवल काग़ज़ी आँकड़ा है, वास्तविक जाँच उन पैसों की भी होनी चाहिए जो सीधे अधिकारियों की जेब में गए होंगे।"

बस्तीवासियों ने भी आरोप लगाया कि उनसे वसूली गई राशि एक समान नहीं थी—

किसी से लाखों तो किसी से कुछ हज़ार रुपये तक वसूले गए।

कई परिवारों ने बताया कि प्रमाण पत्र होने के बावजूद उनके घर वन विभाग और रेलवे द्वारा तोड़े गए, जिससे ये दस्तावेज़ वास्तविक उपयोग में अमान्य सिद्ध हुए।

कई प्रमाण पत्र बैंक लोन के लिए भी मान्य नहीं पाए गए, जिससे उनकी विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं।

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ने इसे पिछली सरकार और स्थानीय नेताओं की "वोट बैंक नीति" बताते हुए तीखा हमला बोला। पार्टी का कहना है—

"फर्जी पट्टा वितरण के नाम पर गरीबों को योजनाबद्ध तरीके से ठगा गया। यह बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार का स्पष्ट उदाहरण है।"

इधर, बस्तीवासियों में आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। लोगों ने निगम प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी है कि—

यदि वसूली गई पूरी राशि शीघ्र वापस नहीं की गई, तो आने वाले दिनों में नगर निगम के खिलाफ बड़े स्तर पर जनांदोलन खड़ा किया जाएगा।

राउरकेला में जागा मिशन की इन अनियमितताओं को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज है। मामला अब एक बड़े घोटाले के रूप में सामने आता दिख रहा है, जिस पर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख़्त कार्रवाई की माँग जोर पकड़ रही है।

गुरु की नगरी अमृतसर में 19वां पाईटैक्स आज से, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल करेंगे उदघाटन:करण गिल्होत्रा

पाईटैक्स से मजबूत होगा भाईचारा, पंजाब को मिलेगा आर्थिक लाभ: रोहित गुप्ता

अमृतसर 3 दिसंबर (साहिल बेरी)

अमृतसर। पीएचडी चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा पंजाब सरकार के सहयोग से आयोजित किया जा रहा 19वां पंजाब इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो गुरु की नगरी अमृतसर में चार दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। जिसका औपचारिक उदघाटन भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पांच दिसंबर को करेंगे। उनके साथ पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा विशेष अतिथि के रूप में भाग लेंगे।

यह जानकारी पीएचडी चैंबर ऑफ कामर्स पंजाब चेप्टर के चेयर कर्ण गिल्होत्रा ने बुधवार को पाईटैक्स मैदान में पत्रकारों से बातचीत में दी।

नगर निगम आयुक्त आईएएस विक्रमजीत सिंह शेरगिल ने बताया कि पाईटैक्स के आयोजन के दौरान यहां बिजली, पानी, सफाई आदि प्रबंधों के लिए कर्मचारियों व अधिकारियों को तैनात किया गया है।

इस अवसर पर विशेष रूप से पहुंचे अमृतसर के अतिरिक्त उपायुक्त रोहित गुप्ता ने कहा कि पाईटैक्स के कारण अमृतसर को एक नई पहचान मिली है। यहां पांच दिन तक देश के कई राज्यों तथा पड़ोसी देशों के कारोबारी अपने उत्पादों का प्रदर्शन करते हैं। इससे जहां आपसी भाईचारा मजबूत होगा वहीं पंजाब को आर्थिक रूप से भी लाभ मिलेगा। पंजाब सरकार के कई विभाग इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। जिले के संबंधित विभागों को पाईटैक्स में सहयोग के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

अगले पांच दिनों तक होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए पीएचडीसीसीआई पंजाब के चेयर कर्ण गिल्होत्रा ने बताया कि चार दिसंबर को स्ट्रेंथ वेलनेस एंड एंटरप्राइज:भविष्य को आकार देती महिलाएं विषय पर आयोजित सेमिनार में राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन विजया किशारे राहटकर बतौर मुख्य अतिथि भाग लेंगी।

पांच दिसंबर को सुबह के सत्र में एग्री, न्यूट्रीश्यन एंड वेलनेस सिनर्जी समिट में पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां बतौर मुख्य अतिथि भाग लेंगे। इसी दिन शाम के सत्र में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 19वें पाईटैक्स का औपचारिक उदघाटन करेंगे।

छह दिसंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए पीएचडीसीसीआई फैशन टेक्स-टेक फोरम की चेयर हिमानी अरोड़ा ने बताया कि शाम के समय होटल ताज में पंजाब हेरीटेज शो का आयोजन किया जाएगा। जिसमें बालीवुड कलाकार रजत बेदी विशेष अतिथि के रूप में भाग लेंगे। इस शो का मुख्य आकर्षण बॉलीवुड में 80 व 90 के दशक की महान कलाकार हेलेन खान बतौर मुख्य अतिथि भाग लेंगी।

इसी दिन रात्रि के समय दूसरे पंजाब टूरिज्म अवार्ड दिए जाएंगे। जिसमें पंजाब के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामले मंत्री तरूणप्रीत सोंद प्रतिभागियों को सम्मानित करेंगे।

कर्ण गिल्होत्रा ने बताया कि सात दिसंबर को समावेशी विकास और समान अवसर: सभी के लिए भविष्य का निर्माण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल प्रो.असीम घोष बतौर मुख्य अतिथि भाग लेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर विशेष रूप से भाग लेंगी जबकि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इसी सत्र में पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत भुल्लर भी पाइटैक्स का अवलोकन करेंगे।

आठ दिसंबर को 19वें पाईटैक्स के समापन समारोह में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया तथा पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस विशेष रूप से मौजूद रहेंगे।

इस अवसर पर पीएचडीसीसीआई की वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक भारती सूद, क्षेत्रीय संयोजक जयदीप सिंह के अलावा कई गणमान्य मौजूद थे।

राष्ट्रीय महिला आयोग – अमृतसर में आज करेगा महिला जन सुनवाई

अमृतसर, 3 दिसंबर (साहिल बेरी)

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा "राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार – महिला जन सुनवाई" कार्यक्रम का आयोजन 4 दिसंबर 2025 को सुबह 11 बजे बचत भवन, रंजीत एवेन्यू, अमृतसर में किया जा रहा है। इस जन सुनवाई की अध्यक्षता माननीय राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन श्रीमती विजया रहाटकर करेंगी।

इस संबंध में चल रही तैयारियों का जायज़ा लेते हुए डिप्टी कमिश्नर श्री दलविंदरजीत सिंह ने बताया कि महिला जन सुनवाई के दौरान वर्ष 2023–2025 के बीच अमृतसर और जालंधर जिलों से संबंधित महिलाओं के लंबित पुलिस मामलों की सुनवाई की जाएगी। इसके अलावा महिलाओं की अन्य शिकायतें भी सुनी जाएंगी।

डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि कोई भी महिला, जिसे किसी प्रकार की शिकायत है, वह इस अवसर पर उपस्थित होकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है तथा वहीं पर उसकी शिकायत की जन सुनवाई भी की जाएगी।

इस बैठक में अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर श्रीमती अमनदीप कौर, जिला प्रोग्राम अधिकारी श्री गुरमीत सिंह, सीडीपीओ जसप्रीत सिंह एवं गगनदीप सिंह, मैडम प्रीति, डीएसपी सरताज सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

बांग्लादेशी सोचकर 8 लोगो को भद्रक पुलिस थाने में ले गए थे

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भूबनेश्वर : भद्रक जिले में बांग्लादेशियों की पहचान का काम ज़ोरों पर चल रहा है, इसी बीच मंगलवार रात बासुदेवपुर पुलिस ने शहर के अलग-अलग इलाकों से अपने घर लौट रहे 8 लोगों को हिरासत में लिया। SP मनोज राउत रात में बासुदेवपुर पुलिस स्टेशन पहुंचे और उनसे पूछताछ की।उन्होंने उनके वोटर, आधार कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट्स चेक किए। पुलिस ने बताया कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद इलाके में मिलने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। अब तक जिले में 300 से ज़्यादा बंगाली बोलने वाले लोगों को वेरिफिकेशन के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया है। SP ने बताया कि खासकर समुद्री पुलिस स्टेशन इलाके में पहचान की प्रक्रिया को और सख्त किया जा रहा है।

करमजीत सिंह रिंटू ने घाला माला चौक से गोपाल मंदिर और गोकुल नगर तक सड़कों पर प्रीमिक्स डालने का काम शुरू करवाया

अमृतसर,3 दिसंबर (साहिल बेरी)

इंप्रूवमेंट ट्रस्ट अमृतसर के चेयरमैन एवं उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के इंचार्ज कर्मजीत सिंह रिंटू ने आज घाला माला चौक से गोपाल मंदिर और गोकुल नगर तक सड़कों पर प्रीमिक्स डालने का काम शुरू करवाया। रिंटू ने कहा कि सड़कों पर प्रीमिक्स डालने के कार्य को पूरी गुणवत्ता के साथ करवाया जा रहा है। सड़के बनवाने वाली कंपनी 5 वर्ष तक सड़कों की मेंटेनेंस भी करेगी। उन्होंने कहा कि सड़कों को फिर से बनाने के दौरान सड़कों का लेवल ऊपर उठने की बात सामने आ रही है, जिससे बारिश का पानी लोगों के घरों में घुसने लगता है। उन्होंने कहा कि लोगों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सड़कों को खोदकर पुराने लेवल पर बनाया जाएगा और आने वाले कुछ दिनों में सड़क बनाने का काम पूरा कर लिया जाएगा।

करमजीत सिंह रिंटू ने कहा कि सर्दी बढ़ जाने के कारण सड़कों को प्रिमिक्स से बनवाने के कार्य आने वाले लगभग 10 दिनों तक ही चलेंगे। उन्होंने कहा कि हॉट मिक्स प्लांट सर्दी के बढ़ने से बंद हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र की शेष रहती सड़कों को अगले वर्ष मार्च महीने में बनवा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़कों और गलियों को आरएमसी, सीसी फ्लोरिंग और इंटरलॉकिंग टाइलों के साथ बनवाने का कार्य लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों से किए गए सभी वादों को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं का हल निकाल रहे हैं।

रिंटू ने कहा कि सफाई व्यवस्था को लेकर पहले कुछ समस्या आई थी। जिसे अब ठीक करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा की नई कंपनी को शहर की सफाई व्यवस्था का ठेका अलाट हो चुका है और कंपनी द्वारा मशीनरी सड़कों पर उतारी जा रही है। उन्होंने कहा कि कंपनी के अधिकारियों के साथ वह लगातार बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले नए वर्ष में शहर की सफाई व्यवस्था बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के वॉलिंटियर्स और शहर के गणमान्य लोग भी मौजूद थे।

माधुरी ने 1 करोड़ 60 लाख लिए हैं: मंत्री प्रदीप बलसामन्त

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वर : बिधान सभा में मंत्री ने कहा , बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी ने ओडिशा हैंडलूम की ब्रांड एंबेसडर बनने के लिए बहुत बड़ी रकम ली है। माधुरी ने सरकारी खजाने से 1.6 करोड़ रुपये लिए हैं। उन्होंने फ्लाइट के साथ रहने और खाने का खर्च अलग से लिया है। कपड़ा उद्योग मंत्री प्रदीप बाला सामंत ने MLA अरुण साहू के सवाल का जवाब दिया है।फ्लाइट के साथ रहने और खाने का खर्च अलग से लिया गया है। विधानसभा का प्रश्नकाल सामान्य रूप से चल रहा है। आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र का छठा दिन है। अलग-अलग विभागों के मंत्री विधायकों और विधायकों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। इस बीच, सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष अलग-अलग मुद्दों पर आमने-सामने हो सकते हैं। मुख्य विपक्षी दल BJD चावल बाजार की समस्या पर स्थगन का प्रस्ताव दे सकता है। इस बीच, ऊर्जा, कृषि, खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण विभागों में प्रश्नकाल है।

राज्य में 35 कोल्ड स्टोरेज हैं। मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कांग्रेस MLA रामचंद्र कदम के सवाल का जवाब दिया। 33 प्राइवेट और 2 सरकारी कोल्ड स्टोरेज चालू हैं। पिछले 10 सालों में राज्य में 26 कोल्ड स्टोरेज बनाए गए हैं। अभी 22 चालू हैं और 4 चालू नहीं हैं। इनमें से 20 सरकारी और 78 प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज हैं। सब-डिवीजन लेवल पर 58 बनाने का टारगेट रखा गया है। 252 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। 15 नए और 2 बंद कोल्ड स्टोरेज को चालू करने के लिए एप्लीकेशन मिले हैं।

देश को राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति देने वाला झारखंड राजभवन का भी नाम बदला अब लोक भवन

आर्किटेक्ट सेड्लो बैलार्ड ने 1930 मे इसका डिजाइन तैयार किया था

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

रांची , देश के तमाम राजभवनों की तरह झारखंड राजभवन का नाम बदल गया है. इस भवन का नाम अब 'लोक भवन' होगा. केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर झारखंड राजभवन से राज्यपाल सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी की है. इसमें कहा गया है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या 7/10/2025 पीएआर-एम एंड जी ,दिनांक 25 नवंबर 2025 और झारखंड के राज्यपाल की स्वीकृति के बाद राजभवन का नाम आधिकारिक रूप से 'लोक भवन' किया जाता है. दुमका राजभवन भी लोक भवन कहलायेगा . राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव नितीन मदन कुलकर्णी के हस्ताक्षर से जारी इस अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि सभी आधिकारिक कार्यों के लिए राजभवन झारखंड को अब से लोक भवन झारखंड कर दिया गया है. यह भी कहा गया है कि यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

लगभग 62 एकड़ में फैले झारखंड राज भवन आड्रे हाउस समेत , की स्थापना वर्ष 1930 में शुरू हुई थी और मार्च 1931 में लगभग 7 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया था. सनद रहे कि यह वही राजभवन रहा जहां से दो -दो राज्यपाल अब देश के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रहे हैं ।

इस भवन का निर्माण हेतु आर्किटेक्ट सेड्लो बैलार्ड का डिजाइन तैयार किया था. कुल 62 एकड़ क्षेत्र में से 52 एकड़ में मुख्य राजभवन परिसर है. लगभग 10 एकड़ में ऑड्रे हाउस बना है. इसे अब हेरिटेज हाउस के रूप में बदल दिया गया है. ऑड्रे हाउस का निर्माण वर्ष 1850 से 1856 के बीच किया गया था

धनबाद के केन्दुआ डीह मे जहरीली गैस रिसाव से दर्जनों लोग बीमार, पंछियों की भी मौत, झारखंड के झरिया कोयलांचल की घटना

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

धनबाद , बीसीसीएल झरिया क्षेत्र में केन्दुआ डीह थाना इलाके के राजयूत बस्ती, मस्जिद मोहल्ला और 5 नंबर सहित कई इलाकों में तेज दुर्गंध के साथ जहरीली गैस रिसाव से हड़कंप मच गया है. लगभग एक हजार की आबादी वाले इन इलाकों में दो दर्जन से अधिक लोग बीमार हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

वहीं, सूचना मिलने पर जांच टीम ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया. टीम में बीसीसीएल के सेफ्टी ऑफिसर, केंदुआडीह थाना प्रभारी सहित अन्य अधिकारी गैस डिटेक्टर मशीन के साथ मौके पर पहुंचे हैं. प्राथमिक जांच में अनुमान लगाया गया कि थाना के समीप स्थित जीएम गेस्ट हाउस के समीप झाड़ियों के आसपास से गैस का रिसाव हो रहा है. हालांकि गैस का प्रकार और रिसाव का सटीक स्रोत स्पष्ट नहीं हो पाया है

इस संबंध में कुसुंडा के एरिया सेफ्टी ऑफिसर तुषारकांत ने बताया कि क्षेत्र के आसपास की जगहों में गैस रिसाव लेने की आशंका है. गैस रिसाव का प्रतिशत अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन गैस की दुर्गंध काफी ज्यादा है. इस संबंध में उच्च अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है. गैस का रिसाव बंद करने के लिए कदम उठाए जाएंगे. वहीं बीसीसीएल एजेंट लखन लाल बरनवाल ने कहा कि गैस रिसाव का लोकेशन ट्रेस करने के प्रयास जारी हैं. जैसे ही स्रोत मिलेगा, उसे भरने का काम शुरू कर दिया जाएगा. डिटेक्टर मशीन से जांच चल रही है.

वहीं, स्थानीय लोगों ने सिरदर्द, उल्टी और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्या बताई है. लोगों ने कहा कि गैस रिसाव के कारण कई लोग बीमार हो गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है. स्थानीय टिंकू अंसारी ने बताया कि इलाके में कई लोग अचानक बीमार हो गए हैं. वहीं, स्थानीय रामकिशन ने बताया कि गैस रिसाव के कारण उनका पालतू तोता भी मर गया है.

एक व्यक्ति ने बताया कि उनकी बच्ची सुबह घर से स्कूल के लिए जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही चक्कर आने से वह गिर गई. अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि उसे जहरीली गैस का असर हुआ है. उन्होंने दावा किया कि जहरीली गैस के रिसाव से दर्जनों लोग प्रभावित हैं और कई लोग परिवार सहित अस्थायी रूप से इलाके को छोड़ दिया है.

वहीं इस संबंध में केंदुआडीह थाना प्रभारी प्रमोद पांडे ने कहा कि स्थानीय लोगों और पार्षद की सूचना पर मामले को गंभीरता से लेते हुए बीसीसीएल को जानकारी दी गई. टीम मौके पर गैस रिसाव बंद करने के प्रयास में जुटी है.

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023